PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

फरवरी 2022 / Issue-2

बजट :एक नजर में

स्कूल में यूनिफॉर्म तथा “धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार”

रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी की भूमिका

आरक्षण और योग्यता के मध्य संबंध

भारत में भूमिगत जल : प्रबंधन तथा विनियमन

डिजिटल यूनिवर्सिटी : शिक्षा में नवीन युग का आरम्भ

दक्षिण एशिया में बढ़ती अस्थिरता तथा भारत

dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Target IAS Prelims 2022
हिन्दी माध्यम

Starts from 16th Feb. 2022

भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सेवा होने के कारण सिविल सेवा देशभर से अभ्यर्थियों को आकर्षित करती हैं। लेकिन सीटों की संख्या सीमित होने से इस परीक्षा में सफलता हेतु उच्चतम स्तर की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता हैं। ऐसे मे एक नियोजित तैयारी और प्रभावी रणनीति सफलता की कुंजी बन जाती हैं। इस विचार और इरादे के साथ हमारे अत्यंत ही कुशल, दक्ष एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ऐसी विशिष्ट एवं प्रभावी रणनीति तैयार की जाती हैं, जिससे सुपरिभाषित तरीके से सभी टॉपिक को कवर किया जा सके। बेहतर अवधारणात्मक समझ हेतु हम अभ्यर्थियों की सहायता करते हैं। साथ ही अन्तर-अनुशासनात्मक दृष्टीकोण के विकास हेतु मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। हमारी नवोन्मेषी अध्ययन प्रणाली एक विश्वासयुक्त रोड मैप तैयार करती है ताकि इस सुनहरे लक्ष्य को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सके। सपनों को साकार करने और आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु हम आपको सशक्त बनाते हैं, साथ ही परिश्रम, समर्पण, विश्वास एवं सही दिशा जैसे अव्यय के विकास में आपके साथ हर कदम पर खड़े रहते हैं। UPSC के तेजी से बदलते पैटर्न के अनुरूप अपने प्रदर्शन में समायानुकूल बदलाव हेतु हम सदैव अभ्यर्थियों के साथ प्रो-ऐक्टिव होकर कार्य भी करते हैं।

छात्र अपनी आवश्यकता अनुरूप निम्नलिखित में से किसी भी कोर्स का चयन कर सकते है।

Target IAS Prelims 2022

Fee: 28,000/-

Objective	Features
कोर्स में सामान्य अध्ययन के सभी भागों को विस्तार से कवर किया जायेगा जिसमें करेंट अफेयर्स भी शामिल रहेगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से सामान्य अध्ययन के परंपरागत (Static) और अद्यतन (Dynamic) भाग की गहन समझ प्रदान किया जाएगा। इस प्रोग्राम में विषय विशेषज्ञों के द्वारा live class में विभिन्न मुद्दों और उनसे तत्संबंधी हाल के नवीन घटनाक्रमों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही लाइव/डिलेड लाइव या रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से सामान्य अध्ययन के परंपरागत (Static) हिस्से पर गुणवत्तापूर्ण कंटेंट भी दिया जाएगा। इस कोर्स में सी-सैट भी शामिल होगा। इस हिस्से में छात्र विभिन्न सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग संबंधी बेहतर और प्रभावी समझ विकसित कर सकेंगे। अवधारणात्मक समझ और संबंधित विषयवस्तु का स्पष्टीकरण भी इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा होगा। CSAT खंड से जुड़े प्रश्नों को आसानी से हल करने के जरूरी तकनीकों और तरीकों पर विस्तृत परिचर्चा भी आयोजित की जायेगी।	• 100 घण्टे की लाइव क्लास जिसमें सामान्य अध्ययन के अद्यतन (Dynamic) हिस्से को कवर किया जाएगा। • 150 घण्टे की लाइव/डिलेड (Delayed) लाइव/रिकॉर्डेट क्लास जिसमें सामान्य अध्ययन के परम्परागत (Static) हिस्से को अपनी सुविधानुसार देखने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। • 150 घंटे की क्लास में सी-सैट का पूर्ण कवरेज। • सभी लाइव क्लासेस के अंत में समस्या समाधान हेतु आधे घंटे का समय दिया जाएगा। • एकेडमिक चैट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। • PDF फारमैट में डाउनलोड हेतु विषय-सामग्री App पर प्रदान की जाएगी। • Perfect 7 की 24 कॉपियां (2000 रुपये मूल्य वाली) भी कोर्स के साथ प्रदान की जाएगी। • कोर्स के साथ एक Prelims टेस्ट सीरीज (2500 रुपये मूल्य वाली) भी शामिल रहेगा।

Course Content	Faculty Name
General Studies- Static	
Indian History+ Art & Culture	Vijay Ved
Geography of India & World	Divyavadan Singh Parihar
Indian Polity & Governance	Vineet Anurag & Jay Singh
Economy	Kumar Amit
General Science	Raghvendra Singh
General Studies- Dynamic (Current Issues & Developments)	
Indian Polity & Governance	Vineet Anurag & Shashidhar
Environmental Ecology, Bio-Diversity & Climate Change	Sanjay Singh
Economy + Budget & Economic Survey	Kumar Amit
Technology	Q. H. Khan & Peeyush
Health	Javed Haque
International Issues	Vineet Anurag
CSAT	
Maths and Reasoning	Mukesh Singh
Comprehension	Shweta Singh

Call : 9205274741 / 42 / 44

CLICK HERE FOR ENROLLMENT

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

General Studies - Target IAS Prelims 2022

Fee: 18,000/-

Objective

कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि उसमें करेंट अफेयर्स के साथ सामान्य अध्ययन के सभी खण्डों को विस्तार पूर्वक कवर किया जा सके। इस प्रोग्राम के माध्यम से सामान्य अध्ययन के सभी अद्यतन हिस्सो की गहन समझ प्रदान की जाएगी। विषय- विशेषज्ञों के द्वारा Live Class के माध्यम से मुद्दों और तत्संबंधी हालिया घटनाक्रमों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही Live/Delayed Live या Recorded classes के माध्यम से करेंट अफेयर्स के परम्परागत भाग पर गुणवत्ता पूर्ण सामग्री भी प्रदान की जाएगी, जिससे छात्र असीमित समय तक देख सकेंगे।

Features

- 100 घण्टे की लाइव क्लास जिसमें सामान्य अध्ययन के अद्यतन (Dynamic) हिस्से को कवर किया जाएगा।
- 150 घण्टे की लाइव/डिलेड (Delayed) लाइव/रिकॉर्डेट क्लास जिसमें सामान्य अध्ययन के परम्परागत (Static) हिस्से को अपनी सुविधानुसार देखने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
- सभी लाइव क्लासेस के अंत में समस्या समाधान हेतु आधे घंटे का समय दिया जाएगा।
- एकेडमिक चैट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- PDF फारमैट में डाउनलोड हेतु विषय-सामग्री App पर प्रदान की जाएगी।

Course Content	Faculty Name
General Studies- Static	
Indian History+ Art & Culture	Vijay Ved
Geography of India & World	Divyavadan Singh Parihar
Indian Polity & Governance	Vineet Anurag & Jay Singh
Economy	Kumar Amit
General Science	Raghvendra Singh
General Studies- Dynamic (Current Issues & Developments)	
Indian Polity	Vineet Anurag & Shashidhar
Environmental Ecology, Bio-Diversity & Climate Change	Sanjay Singh
Economy + Budget & Economic Survey	Kumar Amit
Technology	Q. H. Khan & Peeyush
Health	Javed Haque
International Issues	Vineet Anurag

Spotlight Current Affairs - IAS Prelims 2022

Fee: 10,000/-

Objective

कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि उसमें करेंट अफेयर्स के साथ सामान्य अध्ययन के सभी खण्डों को विस्तार पूर्वक कवर किया जा सके। इस प्रोग्राम के माध्यम से सामान्य अध्ययन के सभी अद्यतन हिस्सो की गहन समझ प्रदान की जाएगी। विषय- विशेषज्ञों के द्वारा live class के माध्यम से मुद्दो और तत्संबंधी हालिया घटनाक्रमों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा।

Features

- 100 घण्टे की लाइव क्लास जिसमें सामान्य अध्ययन के अद्यतन (Dynamic) हिस्से को कवर किया।
- सभी लाइव क्लासेस के अंत में समस्या समाधान हेतु आधे घंटे का समय दिया जाएगा।
- एकेडमिक चैट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- PDF फारमैट में डाउनलोड हेतु विषय-सामग्री App पर प्रदान की जाएगी।

Course Content	Faculty Name
General Studies- Dynamic (Current Issues & Developments)	
Indian Polity & Governance	Vineet Anurag & Shashidhar
Environmental Ecology, Bio-Diversity & Climate Change	Sanjay Singh
Economy + Budget & Economic Survey	Kumar Amit
Technology	Q. H. Khan & Peeyush
Health	Javed Haque
International Issues	Vineet Anurag

UPSC CSAT

Fee: 10,000/-

Objective

इस हिस्से में छात्र विभिन्न सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग संबंधी बेहतर और प्रभावी समझ विकसित कर सकेंगे। अवधारणात्मक समझ और संबंधित विषयवस्तु का स्पष्टीकरण भी इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा होगा। CSAT खंड से जुड़े प्रश्नों को आसानी से हल करने के जरूरी तकनीकों और तरीकों पर विस्तृत परिचर्चा भी आयोजित की जायेगी।

Features

- 150 घंटे की क्लास में सी-सैट का पूर्ण कवरेज।
- सभी लाइव क्लासेस के अंत में समस्या समाधान हेतु आधे घंटे का समय दिया जाएगा।
- एकेडमिक चैट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- PDF फारमैट में डाउनलोड हेतु विषय-सामग्री App पर प्रदान की जाएगी।

Course Content	Faculty Name
Maths and Reasoning	Mukesh Singh
Comprehension	Shweta Singh

3 दिन की अतिरिक्त कक्षाये संचालित की जाएगी जिसमें खेल, पुरस्कार, स्थान, वर्तमान में चर्चित पुस्तकों से सबंधित विषय शामिल होंगे।

ध्येय स्टूडेंट्स के लिए आकर्षक छूट

- 100% छूट Spotlight Current Affairs प्रोग्राम के लिए उन ध्येय विद्यार्थियों को जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद एडमिशन लिया है।
- 50% छूट Spotlight Current Affairs प्रोग्राम के लिए उन ध्येय विद्यार्थियों को जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 से पहले एडमिशन लिया है।

प्रथम चरण (प्रारंभिक परीक्षा)

प्रश्न पत्र 1 (अंक: 200) अवधि: 2 घंटे
⊙ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ
⊙ भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
⊙ भारत एवं विश्व भूगोल - भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल
⊙ भारत राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था - संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि।
⊙ आर्थिक और सामाजिक विकास - सतत् विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि।
⊙ पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है।
⊙ सामान्य विज्ञान

प्रश्न पत्र 2 (अंक: 200) अवधि: 2 घंटे
⊙ बोधगम्यता
⊙ संचार कौशल सहित अंतर - वैयक्तिक कौशल
⊙ तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता
⊙ निर्णयन और समस्या समाधान
⊙ सामान्य मानसिक योग्यता
⊙ आधारभूत संख्यात्मक अभियोग्यता (संख्याएँ और उनके संबंध, विस्तार क्रम, आदि-दसवीं कक्षा का स्तर), आंकड़ों का निर्वचन (चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता, आदि - दसवीं कक्षा का स्तर)

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director

प्रस्तावना

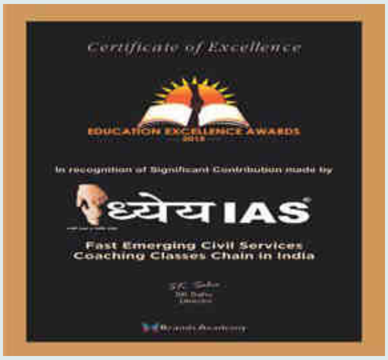

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है. आईएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाय. परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है. इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है. एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिक. ाओं, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी , अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर है. शब्दावली और अन्य आयामों एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा.

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टर्स को 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहेगी. इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नही बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें. हमें उम्मीद हैं कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा.

विनय कुमार सिंह
सम्पादक
ध्येय **IAS**

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

संपादक	विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	क्यू. एच. खान
सहसंपादक	गौतम तिवारी
उप-संपादक	आशुतोष मिश्र
	सौरभ चक्रवर्ती
प्रकाशन प्रबंधक	डॉ.एस.एम.खालिद
संपादकीय सहयोग	प्रिंस कुमार, गौरव चौधरी, देवेंद्र सिंह, लोकेश शुक्ल
मुख्य लेखक	विवेक ओझा
सहायक लेखक	मृत्युंजय त्रिपाठी,
मुख्य समीक्षक	ए.के श्रीवास्तव
	विनीत अनुराग
	बाघेन्द्र सिंह
आवरण सज्जा एवं विकास	प्रगति केसरवानी
	पुनीष जैन
टंकण	सचिन
	तरून
कार्यालय सहायक	राजू, चन्दन, अरुण

साभार : PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, डाउन टू अर्थ, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, योजना, कुरुक्षेत्र, द प्रिंट

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR	: 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR	: 9205274743
LAXMI NAGAR	: 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD	: 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ)	: 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR)	: 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA	: 9205336037, 9205336038
KANPUR	: 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR	: 8599071555
SRINAGAR (J&K)	: 9205962002

PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

विषय सूची

समसामयिक लेख ———————— 1-15

- बजट :एक नजर में
- स्कूल में यूनिफॉर्म तथा "धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार"
- रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी की भूमिका
- आरक्षण और योग्यता के मध्य संबंध
- भारत में भूमिगत जल : प्रबंधन तथा विनियमन
- डिजिटल यूनिवर्सिटी : शिक्षा में नवीन युग का आरम्भ
- दक्षिण एशिया में बढ़ती अस्थिरता तथा भारत

संक्षिप्त मुद्दे राष्ट्रीय ---------------- 16-17

संक्षिप्त मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय ---------------- 18

संक्षिप्त मुद्दे पर्यावरण ---------------- 19

संक्षिप्त मुद्दे विज्ञान एवं तकनीक ---------------- 20-21

संक्षिप्त मुद्दे आर्थिक ---------------- 22-23

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें --------- 24-26

समसामयिक घटनाएं एक नजर में ---------------- 27

ब्रेन बूस्टर ---------------- 28-34

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा समसामयिक बहुविकल्पीय प्रश्न ---------------- 35-39

GS Paper IV के लिए हल केस स्टडी ---------------- 40

व्यक्ति विशेष ---------------- 41

राजव्यवस्था शब्दावली ---------------- 42

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

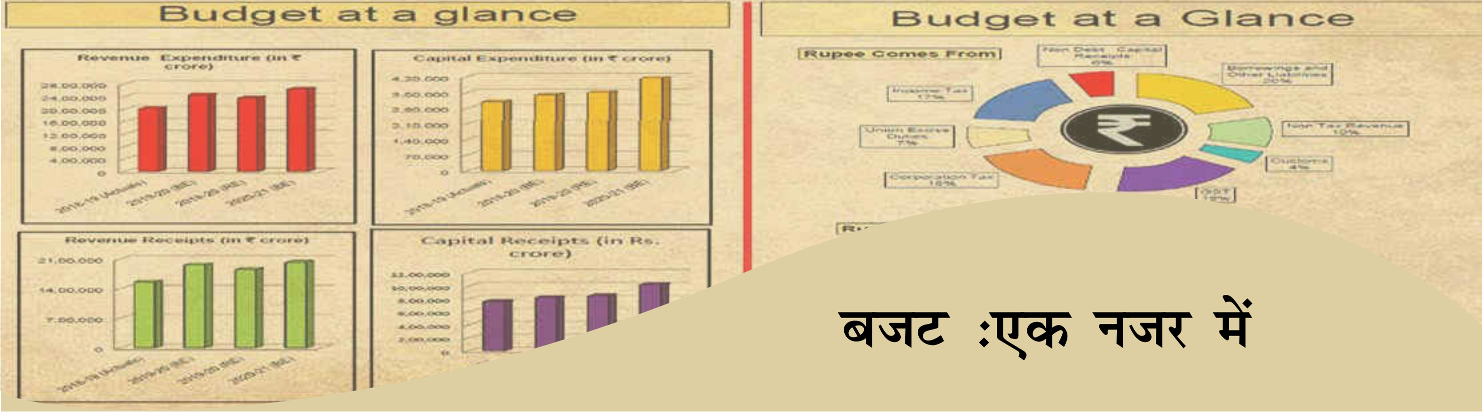

बजट :एक नजर में

बजट में 3 क्रमागत वर्षों के आकड़ो को 4 शीर्षकों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाता है. इसमें निम्नलिखित आंकड़े सम्मिलित होते हैं :-

- इसमें बजट वर्ष से 2 वर्ष पहले (वित्त वर्ष 2020-21) के वास्तविक आंकड़े.
- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान (पिछले वर्ष के बजट में प्रस्तुत) के आकड़े भी.
- वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए संसोधित अनुमान (पिछले बजट में प्रस्तुत आंकड़ो में हुए परिवर्तन)
- आगामी वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए बजट अनुमान.

वर्तमान में "भारत आजादी का महोत्सव" मना रहा है. तथा इसने अमृतकाल में प्रवेश किया है. अभी आजादी के 100 वर्ष "भारत /100" के लिए भारत के पास 25 वर्षो का समय है. इस दौरान सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री द्वारा इस स्वतंत्रता दिवस पर व्यक्त किये गए दृष्टिकोणों को प्राप्त करने से है.

प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए दृष्टिकोण निम्न. वत हैं :-

- व्यष्टि आर्थिक स्तर पर समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के साथ समष्टि आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना.
- डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा फिनटेक को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण, तथा जलवायु अनुकूल क्रियान्वयनों को करना.
- सार्वजनिक पूंजी निवेश के साथ निजी निवेश से शुरू होने वाले व्यापार चक्र पर भरोसा कर निजी निवेश को बढ़ावा देना.
- आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. इस प्रक्रिया से जिसमें 60 लाख नई नौकरियां तथा अगले 5 वर्षो के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन की सम्भावना है.

नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति का कार्यान्वयन :-

- एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हो गया है.
- एनआईएनएल (नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड) के रणनीतिक भागीदार का चयन किया गया है इसके साथ ही एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम शीघ्र ही अपेक्षित है. 2022-23 में अन्य सार्वजानिक क्षेत्र की कंप. नियों का भी विनिवेश किया जायेगा.

भारत की अर्थव्यवस्था में वापसी :-

- वित्त वर्ष 2022 के लिए अनुमानित विकास दर 9.2% तथा वित्त वर्ष 2022-23 ले लिए अनुमानित विकास दर 8.0-8.5% है

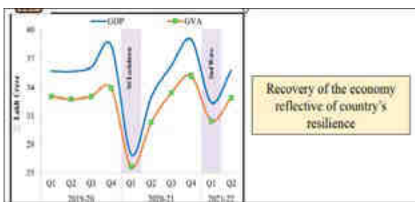

- यह भारतीय अर्थव्यवस्था में **V** शेप रिकवरी को प्रदर्शित करता है.

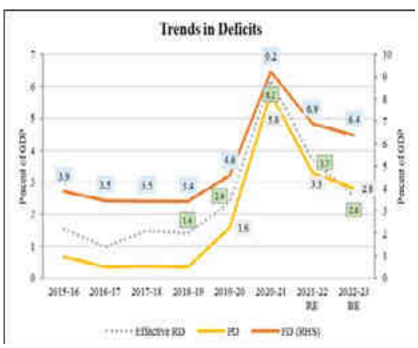

2022-23 में प्रदर्शित घाटे :-

- राजकोषीय घाटा (अपने व्यय के वित्तपोषण के लिए सरकार द्वारा उधार का एक संकेतक) जीडीपी के 6.4% पर लक्षित है.
- राजस्व घाटा (राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता) सकल घरेलू उत्पाद के 3.8% पर लक्षित है.
- 2021-22 में प्राथमिक घाटा (जो ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है) सकल घरेलू उत्पाद के 2.8% पर है.

Table 8: FRBM targets for deficits (as % of GDP)

	Actuals 2020-21	Revised 2021-22	Budgeted 2022-23
Fiscal Deficit	9.2%	6.9%	6.4%
Revenue Deficit	7.3%	4.7%	3.8%
Primary Deficit	5.8%	3.3%	2.8%

Sources: Medium Term Fiscal Policy Statement, Union Budget 2022-23; PRS.

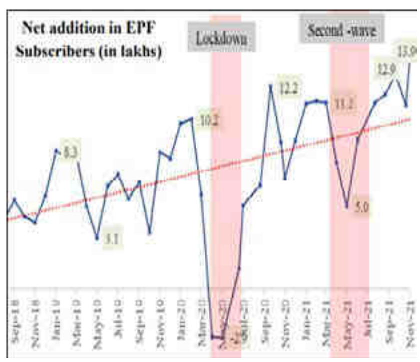

- लॉकडाउन के उपरांत स्थिति सामान्य होने पर नवीन रोजगार का सृजन किया गया. इसके फलस्वरूप रोजगार सृजन में वृद्धि हुई है.
- भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 634 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया इसके साथ ही साथ भारत 12 महीनों से अधिक का आयात कवर की स्थिति में पहुंच गया.

पीएम गतिशक्ति :-

- यह 7 इंजनों द्वारा संचालित की जाएगी. वे 7 निम्नलिखित हैं :-
- सड़कें,
- रेलवे,
- हवाई अड्डे,
- जलमार्ग,
- बंदरगाह,
- मास ट्रांसपोर्ट, और
- लॉजिस्टिक अवसंरचना

एक्सप्रेस वे के लिए मास्टर प्लान:- 2022-23 में 25000 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है.

- यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्ले. टफॉर्म सभी मोड ऑपरेटरों के बीच डेटा एक्सचेंज को सक्षम बनाता है.
- यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक.
- 2022-23 में पीपीपी मॉडल पर 4 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किये जायेंगे.
- रेलवे इंफ्रा
- डाक और रेलवे नेटवर्क के एकीकरण से पार्सल की आवाजाही और सुविधाजनक होगी है.
- एक स्टेशन एक उत्पाद
- कवच परियोजना के तहत कवरेज का विस्तार
- 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें

शहरी अवसंरचना :-

- बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी.
- पारंपरिक सड़कों के स्थायी विकल्प के रूप में राष्ट्रीय रोपवे विकास योजना.
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण.

समावेशी विकास :-

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण :-

- कृषकों को रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना है. इसका आरम्भ गंगा नदी के समीप के किसानो से होगा.
- बाजरे के उत्पादों की कटाई के बाद मूल्यवर्धन, उपभोग तथा ब्रांडिंग को बढ़ावा देना.

कृषि में तकनीक :-

- पीपीपी मोड में किसानों को डिजिटल और हाई-टेक सेवाओं की डिलीवरी.
- किसानों की सहायता के लिए कृषक ड्रोन का उपयोग.
- कृषि स्टार्टअप को वित्त देने के लिए मिश्रित पूंजी के साथ कोष की व्यवस्था.

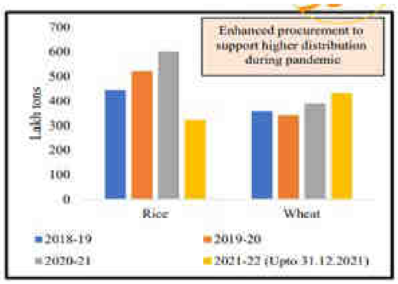

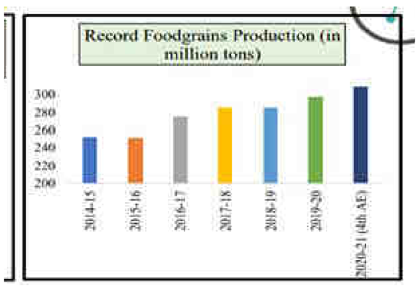

नदीओं को आपस में जोड़ना :-

केन बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन

- 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ. न्वित किया जायेगा.
- 62 लाख लोगों को पीने योग्य जल उपलब्ध होगा.
- 130**MW** बिजली उत्पन्न की जायेगी.

ऐसी ही 5 अन्य परियोजनाएं- दमनगंगा-. पिंजाल, पारा-तापीनर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जायेगा.

एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु तथा माध्यम उद्योग) :-

- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) द्वारा महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में सहायता मिली है. इस योजना के अंतर्गत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अति आवश्यक अतिरिक्त ऋण प्रदान किया है. यह योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है.
- 50000 करोड़ के गारंटी कवर को कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। अतिरक्त राशि उद्यमों विशेष रूप से आतिथ्य तथा अन्य संबंधित उद्यमों के लिए निर्धारित की जाएगी.
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना को अतिरिक्त वित्त पोषण के साथ नए स्वरुप में परिवर्तित किया जायेगा. इस योजना से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्राप्त होगी जिससे रोजगार के अवसरों में विस्तार होगा.
- एमएसएमई क्षेत्र को अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने के लिए 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रदर्शन (आरएएमपी) कार्यक्रम को बढ़ाने तथा उसे गति प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा.
- उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को आपस में जोड़कर उनके क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा.

शिक्षा :-

- वन क्लास वन टीवी चौनल कार्यक्रम को 200 टीवी चौनलों तक विस्तारित किया जाएगा.
- कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल लैब और स्किलिंग ई-लैब की स्थापना की जाएगी.
- सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य से एक विश्वस्तरीय गुणवत्ता से युक्त डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी.

- डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाला ई-कंटेंट वितरित किया जायेगा.

कौशल विकास :-

- ऑनलाइन प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड (DESH-Stack e-portal) लॉन्च किया जाएगा.
- ड्रोन-ऐज-अ-सर्विस की सुविधा को बढ़ाने के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा.

स्वास्थ्य :-

- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का आरम्भ किया जायेगा.
- गुणवत्तापरक परामर्श के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा.
- मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, और पोषण 2.0 का एक इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर लॉन्च किया जाएगा.
- 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंग. नबाड़ियों में अपग्रेड किया जायेगा.

सभी के लिए समावेशी कल्याण :-

- हरघर, नल से जल : 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा.
- प्रधानमंत्री आवास योजना : 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा.
- पीएम-डिवाइन : पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं के आधार पर बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के लिए वित्त उपलब्ध करना.
- आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम : इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों के पिछड़े ब्लॉकों के विकास है.
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम : उत्तरी सीमा पर विकास की मुख्य धारा से दूर गांवों के विकास को लक्षित करना.
- डाकघरों द्वारा डिजिटल बैंकिंग : 100% डाकघर को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना.
- डिजिटल भुगतान : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इका. इयां स्थापित करेंगे.

उत्पादकता वृद्धि और निवेश :

व्यापार सुगमता 2.0 :-

- 14 क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव) देना तथा इन क्षेत्रो को 5G तकनीकी से सहयोग प्रदान करना.
- विश्वास आधारित शासन.
- पर्यावरण मंजूरी से सम्बंधित परिवेश (PARIVESH) पोर्टल के दायरे का विस्तार.
- भूमि अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) को बढ़ावा देना.
- कंपनियों के स्वैच्छिक समापन की सुविधा के लिए सी-पेस की स्थापना.
- AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स.
- ऑनलाइन ई-बिल प्रणाली को समाप्त करना तथा सरकारी खरीद में श्योरिटी बांड का उपयोग करना.
- उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना.

जीवन की सुगमता :-

- शहरी नियोजन में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना करना.
- शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग नीति प्रदान करना.
- चिप एम्बेडेड ई-पासपोर्ट को जारी करना.
- भवन उपविधियों का आधुनिकीकरण, नगर नियोजन योजनाओं को लागू करना तथा पारगमन उन्मुख विकास को बढ़ावा देना.

निवेश वित्तपोषण :-

- 2022-23 में मांग की निरंतरता बनाये रखने के लिए प्रमुख निजी निवेश तथा सार्व. जनिक निवेश को बढ़ाया जाएगा.
- 2022-23 से आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत.
- पूंजीगत व्यय को बढ़कर 35.4% (वर्ष-दर-वर्ष) तक किया जायेगा.

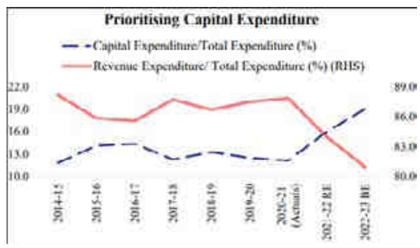

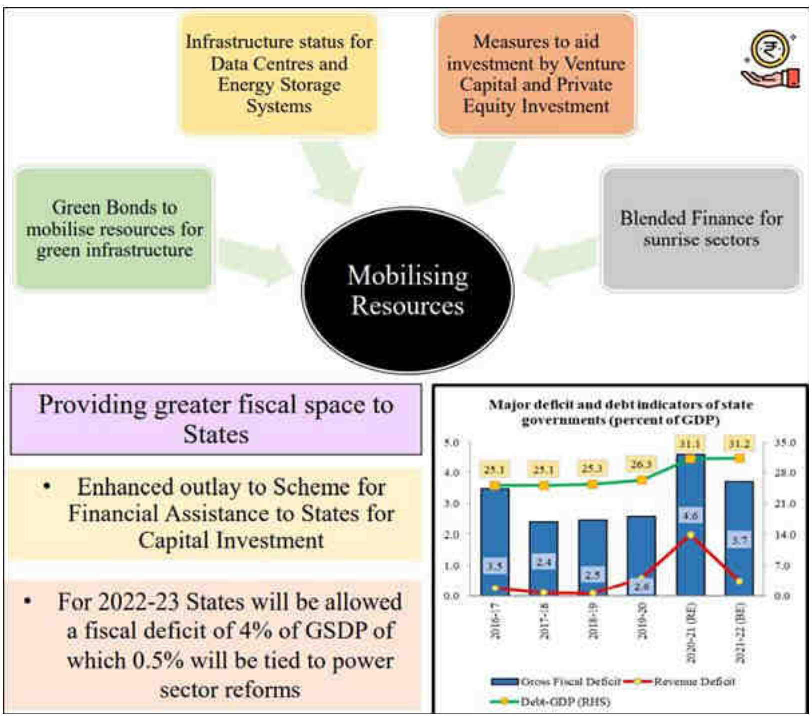

स्कूल में यूनिफॉर्म तथा "धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार"

संदर्भ :-

हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा प्री– यूनिव. र्सिटी स्कूलिंग के लिए स्कूल प्रशासन द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म को अनिवार्य बनाने के उपरांत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर एक नवीन विवाद आरंभ हो गया. स्कूल में हिज. ाब पहन कर आने वाली लड़कियों को स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल में प्रवेश वर्जित कर दिया गया. जिसे इन लड़कियों ने इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का उलंघन बताया है.

परिचय :-

भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधि कार प्राप्त है. हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के उपरांत धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर एक नवीन बहस छिड़ गई है. यह मुद्दा स्पष्ट रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तथा विद्यालय प्रशासन की स्वायत्तता में विरोधाभासी स्थिति को प्रदर्शित करता है. भारत में इस प्रकार के मुद्दों का मुख्य कारण यह है कि यहां राज्य धर्मनिरपेक्ष है जबकि समाज धार्मिक है.

यूनिफॉर्म निर्धारण के पक्ष में तर्क

- विद्यालय की स्वायत्तता : विद्यालय अथवा कॉलेज जैसे संस्थान के पास एक सीमा तक स्वच्छता होती है. उन्हें यूनिफॉर्म निर्धारित करने का अधिकार है.
- शिक्षा की धर्मनिरपेक्षता: शिक्षा स्थल धार्मिक पहचान से अलग होते हैं. इन्हें किसी धर्म के बंधन में बांधना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए ठीक नहीं है. अत: शिक्षा स्थलों को धार्मिक पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शन से परे होना चाहिए.
- पितृसत्तात्मक मानसिकता: कुछ लोगों का तर्क है कि महिलाओं के लिए हिजाब की अनिवार्यता इस्लाम का अनिवार्य तत्व न होकर पितृसत्तात्मक मानसिकता द्वारा आरोपित किया गया है. तथा धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर पितृसत्तात्मक मानसिकता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता.
- सामूहिक अधिकारों को प्राथमिकता:

फातिमा तसनीन बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी संस्था के सामूहिक अधि कारों को व्यक्तिगत अधिकारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इस निर्णय के आलोक में हम देखें तो हिजाब पहनने के अधिकार पर विद्यालय की सामूहिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए.

यूनिफॉर्म निर्धारण के विपक्ष में तर्क

- धार्मिक स्वतंत्रता: कुछ लोगों का यह तर्क है कि हिजाब सिक्खों की पगड़ी की तरह ही इस्लाम धर्म का प्रतीक है. हिजाब पहनने से रोका जाना इन महिलाओं के ध ार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है.
- अनुच्छेद 15 का उलंघन : अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए धर्म के आधार पर विभेदन से प्रतिषेध करता है. इस प्रकार यह तर्क बन सकता है धार्मिक प्रतीक (हिजाब) के कारण किसी को विद्यालय (सार्वजनिक स्थल) पर आने से रोकना (हिजाब पहनने वाली महिलाओं को) धर्म के आधार पर विभेदन कर इनके अनुच्छेद 15 का उलंघन होगा.
- "एजुकेशन फॉर ऑल" के तत्वार्थ के विरुद्ध : इस प्रकार की धार्मिक प्रतीक चिन्ह (हिजाब) पर प्रतिबंध लगाने से यह भी संभव है कि मुस्लिम परिवार बालिकाओं की शिक्षा ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगा दे. इस प्रकार यह समस्या "एजुकेशन फॉर ऑल" के तत्वार्थ के विरुद्ध होगी. आमना विंत बशीर बनाम सीबीएससी मामले में केरल उच्च न्यायालय ने हिजाब को एक अनिवार्य ध ार्मिक अभ्यास माना है जिसे अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण प्राप्त है.

भारतीय संविधान में धर्म से संबंधित प्रावधान

प्रस्तावना

- प्रस्तावना के अनुसार भारत में राज्य की प्रवृत्ति धर्मनिरपेक्ष है.
- प्रस्तावना किसी भी व्यक्ति को विचार , अभिव्यक्ति ,विश्वास ,उपासना एवं धर्म की स्वतंत्रता देता है.

संविधान का भाग 3: मूल अधिकार

- **अनुच्छेद १५** तथा अनुच्छेद 16 धर्म के आधार पर विभेदन से प्रतिषेध करता है.
- **अनुच्छेद २५:** यह सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को निर्बाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त है. यद्यपि यह अधिकार आत्यंतिक नहीं है तथा राज्य द्व ारा इस स्वतंत्रता को लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर निर्बंधित किया जा सकता है.
- **अनुच्छेद २६**–
- सार्वजानिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा कि
- धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थ. ानों की स्थापना और रखरखाव कर सके
- धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए
- चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने के लिए
- विधि के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करना

अनुच्छेद २७: किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं.

अनुच्छेद २८

(1) राज्य-निधि से पूर्णत: पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी.

(2) खंड (1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है.

(3) राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है.

आवश्यक धार्मिक अभ्यास का सिद्धांत -

सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 1954 में शिरूर मठ मामले में धर्म के आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया. न्यायालय के अनुसार धर्म के अंतर्गत आधारभूत तथा अन्य प्रथाएं होती हैं तथा किसी धर्म की आवश्यक और गैर-आवश्यक प्रथाओं को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व न्यायालय का होगा.

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के समक्ष चुनौतियां

- भारत एक विविध धर्मों वाला देश है यहां कई धर्म तथा पंथो के लोग पाए जाते

हैं. जिनमें आपसी टकराव बना रहता है. स्वतंत्रता तथा स्वछंदता के सीमा निर्धारण में असफलता से धार्मिक स्वतंत्रता कई बार धार्मिक कट्टरता में परिणत हो जाती है. इसी के कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं.

- अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने 2020 की अपनी रिपोर्ट में भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में विशेष रूप से चिंता ग्रस्त देश की श्रेणी में रखा था. इस संस्था के अनुसार 2019 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का तीव्र ह्रास हुआ. नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय रजिस्टर, जम्मू कश्मीर की स्थिति परिवर्तन, तथा धर्मांतरण विरोधी कानून धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले कारक माने गए. इस संस्था ने यह भी अनुशंसा की थी कि अमेरिकी सरकार अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें.
- भारत का राज्य तथा राजनीति धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप चलता है वही भारत का समाज धार्मिक प्रवृत्ति का है. इस स्थिति के कारण कई बार समाज तथा राज्य में टकराव की स्थिति देखने को मिलती है यथा ट्रिपल तलाक का मुद्दा, सबरीमाला मुद्दा इत्यादि. राज्य तथा समाज की प्रवृत्ति में यह विरोधाभास भी धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करता है.

निष्कर्ष

ध्यान से देखें तो हम यह पाते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा को उच्चतम न्यायालय द्वारा निरंतर कम किया गया है तथा इन निर्णयों से अनुच्छेद 44 में वर्णित यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ प्रगति में सहायता मिली है. स्कूल यूनिफार्म को सामान्य करना एक प्रकार से यूनीफॉर्मिटी को ही प्रदर्शित करता है इस प्रकार यह कदम स्वागत योग्य है. यद्यपि अभी इस पर कोर्ट का निर्णय आना बाकी है परंतु यह कहा जा सकता है कि विद्यालय की स्वायत्तता तथा धार्मिक स्वतंत्रता के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए जिससे एजुकेशन फॉर ऑल का तत्वार्थ बाधित न हो.

NOTES

रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी की भूमिका

चर्चा में क्यों?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25 प्रतिशत का उपयोग उद्योग, स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों के लिए आवंटित किया जायेगा. जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास में प्रयुक्त होगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की "निजी उद्यमों को, एसपीवी मॉडल के अनुसार डीआरडी. ओ और अन्य संगठनों के सहयोग से, सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा".

भारत में रक्षा निर्माण उद्योग :-

- भारतीय रक्षा निर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को तेजी से विकसित करने की आवश्यकता है.
- भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 2016 से 2020 के मध्य 3.9% की सीएजीआर वृद्धि देखी गई है.
- भारत सरकार ने 2025 तक 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2025 तक निर्यात से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर सहित) के रक्षा उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है.
- 2019-20 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था.
- वित्त वर्ष 2020 में भारत का रक्षा आयत 463 मिलियन डालर था जबकि वित्तवर्ष 2021 में इसके 469.5 मिलियन अमेरिकी डालर होने का अनुमान है.
- भारत के रक्षा निर्यात में पिछले 2 वर्षो में वृद्धि देखी गई. भारत ने अगले 5 वर्षों में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात करने का लक्ष्य रखा है. 2019 तक, भारत 42 देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात करके दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातकों की सूची में 19वें स्थान पर है.

रक्षा विनिर्माण में निजी उद्योगों की भागीदारी :-

आंकड़ो के अनुसार, 2016-17 के बाद रक्षा विनिर्माण में सार्वजानिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के मध्य ट्रांजिशन की अवस्था दिखी है. कुल रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान 2016-17 के 19% से बढ़कर 2018-19 में 22% हो गया है. इसी अवधि में, सार्वजनिक क्षेत्र (डीपीएसयू प्लस आयुध बोर्ड) का योगदान 75% से घटकर 72% हो गया है.

रक्षा विनिर्माण में निजी उद्योग की भागीदारी में उत्पन्न बाधाएं :-

- इस क्षेत्र में सार्वजानिक क्षेत्रक की संस्था डीआरडीओ रक्षा उपकरणों तथा आयुधो के डिजाइन, परिचालन तथा विनिर्माण में अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है. इसके पास बेहतर बुनियादी ढांचे, कुशल जनशक्ति और विनिर्माण सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके कारण सभी महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण अनुबंध डीआरडीओ को ही मिलते हैं. इस परिदृश्य में निजी उद्यम मात्र दूसरे विकल्प के रूप में कार्य करता है तथा उसे केवल रक्षा परियोजनाओं में स्पिल ओवर/ बचे हुए भागीदारी के लिए गुंजाइश होती है.
- भारत में निजी क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक लाने के साथ साथ इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण कमियों को दूर कर उत्पादन प्रक्रिया को तीव्र गति से संचालित करने के लिए देखा जा रहा है. चुकी वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग को पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीकियों के प्रयोग से नहीं बढ़ाया जा सकता, अत: इसे आगे बढ़ाने में विदेशी ओईएम से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की आवश्यकता है. प्रमुख सैन्य शक्तियां अपने द्वारा निर्मित तकनीक को रणनैतिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हुए तकनीक के निर्यात को नियंत्रित करती हैं. अत: निजी क्षेत्र के लिए विदेशी प्रौद्योगकियों को प्राप्त करना आसान नहीं होगा.
- तीसरा, अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के विपरीत, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश **(FDI)** की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं है। जून 2020 में घोषित एफडीआई नीति के अनुसार, 76% से अधिक एफडीआई के लिए सरकारी अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया है, इस प्रावधान के फलस्वरूप देश में आधुनिक तकनीक आने का मार्ग कुछ आसान हुआ है. इसके पूर्व, यदि विदेश ओईएम भारत में एक विनिर्माण आधार स्थापित करना चाहती थीं तो उन्हें भारत के घरेलू फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की आवश्यकता होती थी.
- सामरिक भागीदारों के चयन की प्रक्रिया में अंतर्विरोध की स्थिति है. किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी महत्वपूर्ण आयुध प्रणाली कार्यक्रम को मात्र अपनी क्षमता पर पूर्ण न कर पाने के कारण दीर्घकालिक साझेदारी के लिए भागीदारों का चयन एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया बन जाती है. यह मान लेना तर्कसंगत है कि सामरिक भागीदारों (एसपी) का चयन नियमित आरएफपी प्रक्रिया के बाद सत्यापित प्रदर्शन के बाद ही किया जाता है. हालांकि, यह निजी क्षेत्र से एसपी के चयन के लिए पात्रता मानदंड विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा दिए गए सुझावों से भिन्न है.
- निजी क्षेत्र में, रक्षा उत्पादन के संबंध में सीमित अनुभव और विशेषज्ञता है. इसके साथ ही जटिल रक्षा प्रणालियों और उप प्रणालियों एकीकरण के संबंध में भी सीमित विशेषज्ञता एक चुनौती के रूप में सामने आती है. इसलिए, रक्षा निर्माण में अनुभव के बजाय, बहु-विषयक कार्यात्मक प्रणालियों के एकीकरण में क्षमता, सिस्टम इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता को प्राथमिकता देनी

होगी.

रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल :-

- सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' योजना के तहत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 'रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020' तैयार की है. रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात सहित 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है.
- 2020 की नीति ने विदेशी ओईएम को "भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से विनिर्माण या रखरखाव संस्थाओं" की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई श्रेणी 'खरीदें (भारत में वैश्विक-निर्माण)' पेश की है. नए दिशानिर्देश से व्यापक स्तर पर रक्षा उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा. घटक और पुर्जे के अतिरिक्त, घरेलू रूप से विकसित रक्षा प्लेटफार्मों में अब कम से कम 60% भारतीय सामग्री होनी चाहिए.
- भारत सरकार ने नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस की मांग करने वाली कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में 74 प्रतिशत तक और सरकारी मार्ग से 100% तक एफडीआई को मंजूरी दी है. इससे भारत में आधुनिक रक्षा तकनीक के आने में सहायता मिलेगी.
- आयात प्रतिस्थापन के लिए एमएसएमई/स्टार्टअप्स/उद्योग को विकास सहायता प्रदान करने के लिए उद्योग इंटरफेस के साथ डीपीएसयू/ओएफबी/सेवाओं के लिए अगस्त 2020 में एक स्वदेशीकरण पोर्टल 'सृजन' शुरू किया गया है.
- सरकार ने एक उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से मार्च 2019 में 'रक्षा प्लेटफार्मों में उपयोग किए जाने वाले घटकों और पुर्जों के स्वदेशीकरण के लिए नीति' अधिसूचित की है जो रक्षा के लिए आयातित घटकों (मिश्र धातु और विशेष सामग्री सहित) तथा भारत में निर्मित उपकरणों के उप-संयोजनों के स्वदेशीकरण हेतु सक्षम है.
- सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक-एक रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए हैं. अभी तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा दोनों गलियारों में 3342 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारों ने भी इन दो गलियारों में निजी क्षेत्रकों के साथ-साथ मूल उपकरण निर्माताओं (ओइएम) सहित विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एयरोस्पेस और रक्षा नीतियों की घोषणा की है.
- अप्रैल 2018 में रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (IDEX) शीर्षक से रक्षा में नवाचार बढ़ाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया. **iDEX** का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत उद्योगों, नवप्रवर्तक, अनुसंधान एवं विकास संस्थान और शिक्षाविद को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना है.
- इस योजना का उद्देश्य इन हितधारकों को अनुदान/वित्त पोषण और अन्य सहायता प्रदान कर भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस में डिजाइन और विकास के लिए 300 नए स्टार्टअप को लाभ पहुंचाना है.
- इस क्षेत्र में निवेश के लिए निवेश के अवसरों, प्रक्रियाओं और नियामक आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने सहित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए मंत्रालय में फरवरी-2018 में रक्षा निवेशक सेल (डीआईसी) बनाया गया है.

आगे की राह :-

- प्रधानमंत्री के आत्मानिर्भर भारत एजेंडे के अनुरूप, भारतीय उद्योगों के द्वारा आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप एक बार पुन: रक्षा पूंजी खरीद के लिए 68 प्रतिशत (बढ़ी हुई) का घरेलू आवंटन किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत उद्योग, स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों के लिए निर्धारित करना एक दूरदर्शी

उपाय है, जो सीमांत प्रौद्योगिकियों और क्षमता विकास में निवेश के मार्ग को प्रशस्त करेगा.
- एक रक्षा औद्योगिक बेस बनाने के लिए, सरकार को भारत में निजी क्षेत्र का समर्थन करने और बड़े और स्थिर रक्षा अनुबंधों के साथ निजी क्षेत्र पर विश्वास करने पर विचार करना चाहिए. भारत में रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की अनुसंधान और विकास, और डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं का समर्थन करना महत्वपूर्ण है.
- महत्वपूर्ण आयुध प्रणालियों तथा सैन्य प्लेटफार्मों के विकास के लिए एसपीवी मोड के माध्यम से डीआरडीओ के नेतृत्व में भारतीय रक्षा उद्योग की स्थिति में व्यापक परिवर्तन होगा. जो भारतीय रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से बदलकर भारत को रक्षा उपकरण/ प्रणालियों का शुद्ध-निर्यातक बनने में सहायक होगा.

NOTES

आरक्षण और योग्यता के मध्य संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने नीट की अखिल भारतीय कोटा सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोटा की संवैधानिक वैधता को जारी रखा है. न्यायालय ने माना कि खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण योग्यता से असंगत नहीं है. पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश के मामले के साथ ही अन्य कारणों से भी यह निर्णय ध्यान देने योग्य है.

प्रमुख बिंदु :-

- सकारात्मक भेदभाव के आलोचक लंबे समय से तर्क दे रहे हैं कि आरक्षण योग्यता का उल्लंघन करता है. आरक्षण के पक्षधर लोग भी इसे स्वीकार करते हैं साथ ही वो तर्क देते हैं कि सकारात्मक भेदभाव सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे अन्य लक्ष्यों की पूर्ति करता हैं.
- न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित निर्णय ने, आरक्षण संबंधी बहस को एक नवीन आयाम प्रदान किया है. न्यायालय ने इस अवसर पर योग्यता बनाम आरक्षण के मुद्दे को 12 पैराग्राफ के अंतर्गत सीधे संबोधित किया है.
- निर्णय अवसर की समानता के हमारे संवैधानिक वादे को रेखांकित करते हुए औपचारिक समानता के बजाय वास्तविक समानता के सिद्धांत को याद कर पुन: उसे पुष्टि करने से शुरू होता है.
- संविधान सभा में आरक्षण संबंधी बहस के आलोक में, यह निर्णय हमें याद दिलाता है कि संविधान निर्माताओं का इरादा वास्तविक संरचनात्मक बाधाओं को दूर कर अवसर की समानता को सुनिश्चित करने का था.
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस, केसी वसंत कुमार (1985) और इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) जैसे ऐतिहासिक मामलों पर आधारित है. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण का प्रावधान अपवाद नहीं है बल्कि अनुच्छेद 16(1) में प्रतिपादित समानता के सिद्धांत का विस्तार है.
- निर्णय में कहा गया है कि सभी नागरिकों के बीच अवसर और स्थिति की वास्तविक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में आरक्षण साधक है. इन बाधाओं को दूर करने के लिए आरक्षण एक उपाय है.किसी विशेष व्यक्ति को प्राप्त विशेषाधिकार, व्यक्तिगत, भाग्य या परिस्थितियों का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग कुछ समूहों द्वारा करने से होने वाले संरचनात्मक नुकसान को दूर करने में आरक्षण की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है.
- दूसरा, निर्णय उन तंत्रों के विनिर्देशन में योगदान करता है जिनके माध्यम से सामाजिक विशेषाधिकार कार्य करते हैं.
- के.सी. वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य (1985) वाद में न्यायमूर्ति सी रेड्डी ने जाति की सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था में अंतर्निहित कठोर प्रकृति पर जोर देकर आरक्षण के दावों को सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखे जाने की आलोचना की थी.
- निर्णय मार्क गैलेंटर के अवधारणा के अनुकूल है. जिसमें संसाधन संचय की प्रक्रियाएं परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन को प्रभावित करती है.
- इस समझ को विस्तार देते हुए यह निर्णय शायद पहली बार के.वी. श्यामप्रसाद के कार्य (सांस्कृतिक पूंजी की भूमिका) को मान्यता प्रदान करता है.
- निर्णय में कहा गया है कि 'सांस्कृतिक पूंजी यह सुनिश्चित करती है कि एक बच्चे को अपने परिवार की स्थिति के अनुरूप उच्च शिक्षा या उच्च पद लेने के लिए पारिवारिक वातावरण द्वारा अनजाने में ही प्रशिक्षित किया जाता है. यह उन व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं और उन समुदायों से आते हैं जिनके पारंपरिक व्यवसायों के परिणामस्वरूप खुली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल का संचार नहीं होता है।
- यह निर्णय इस प्रक्रिया के निहितार्थों के प्रति भी सजग है कि आरक्षण को योग्यता के आधार पर खारिज करने वाला प्रबुद्ध वर्ग पारिवारिक संस्कारों, सामुदायिक जुड़ाव और विरासत में मिले कौशल को वैध ठहराता है.
- निर्णय सामाजिक पदानुक्रमों की पुष्टि करता है, कि एक परीक्षा में कम अंक उन लोगों की गरिमा को कम करने का काम करता है जो अपनी उन्नति में उन बाधाओं का सामना करते हैं जो उनके द्वारा बनाए हुए नहीं हैं.
- तीसरा, यह निर्णय सामाजिक पूर्वाग्रहों को उजागर करता है जो 'प्रशासन की दक्षता' और योग्यता के कमजोर पड़ने की आशंका पैदा करता हैं.
- निर्णय कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के कौशल के बारे में पूर्वाग्रही रूढ़ियों को सुधारने की आवश्यकता पर बल देता है.
- बीके पवित्रा बनाम कर्नाटक राज्य वाद 2019 के निर्णय में कहा गया था कि प्रशासन की दक्षता के लिए योग्यता का बेंचमार्क एक उम्मीदवार के प्रदर्शन द्वारा मापा गया असंबद्ध, अमूर्त आदर्श नहीं है. संघ या राज्य के मामलों में प्रशासन की दक्षता को एक समावेशी अर्थ में परिभाषित किया जाना चाहिए, जहां समाज के विविध वर्ग के लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन की सच्ची आकांक्षा के रूप में प्रतिनिधित्व पाते हो.

- अंत में, निर्णय मामले की तह तक जाकर और योग्यता के उपाय के रूप में परीक्षाओं पर प्रश्नचिह्न लगाता है.
- अश्विनी देशपांडे के अध्ययन का हवाला दिया गया है, जो परीक्षाओं द्वारा मापने का दावा करने और वास्तव में वे क्या मापते हैं के बीच की असमानता को उजागर करता है. अर्थात परीक्षाओं योग्यता मापने का दावा तो करती है मगर वो इस प्रक्रिया में उम्मी. दवारों को प्राप्त विशेषाधिकार की अनदेखी करती हैं. दूसरे शब्दों में योग्यता के मापन के क्रम में अवसर की समनता की अनदेखी कर बैठती हैं.
- विषय को विस्तार देते हुए सतीश देशपांडे के शोध का हवाला देते हुए कहा गया है कि अक्सर परीक्षा की विषयवस्तु का उन कार्यों से अप्रत्यक्ष और कमजोर संबंध होता है जिन्हें उम्मीदवार को करना होता है.
- उनका तर्क है कि प्रतियोगी प्रवेश परीक्ष. ाओं को दोषरहित बताया जाता है ताकि मानकों और मूल्यांकनकर्ता की प्रतिष्ठा को संरक्षित रखा जा सके.
- सतीश देशपांडे इन परीक्षाओं को पक्षप. ातपूर्ण मानते हुए इसे 'दर्दनाक रक्तपात'की संज्ञा देते हैं, जो पेशेवर वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, हाशिये पर के समूहों के साथ किए जाते हैं.
- इस प्रकार, देशपांडे ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि परीक्षाएं कम क्रूर होती हैं, तो उनके 'बहिष्कार के लिए उम्मीदवारों के विशाल बहुमत' को राजी करने का उनका मुख्य सामाजिक कार्य बाधित हो जाएगा.
- इन पहलुओं पर विचार करते हुए, निर्णय में कहा गया है कि परीक्षा केवल एक व्यक्ति की वर्तमान क्षमता को प्रतिबिंबित कर सकती है, लेकिन उनकी क्षमता या क्षमताओं के उत्कृष्टता को नहीं.

व्यक्तिगत चरित्र, जीवंत अनुभवों और बाद के प्रशिक्षण के महत्व को आगे बढ़ाते हुए, निर्णय इस बात पर जोर देता है कि परीक्षाएं अपवाद है क्योंकि यह सुविधाजनक संसाधन आवंटन के तरीकों की पहचान नहीं करती. जिनको लेकर हमारे संवैधानिक आदर्श विशेष रूप से सजग हैं.

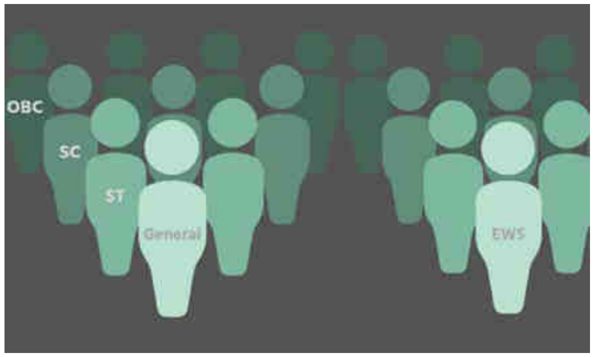

महत्व :-

- आरक्षण से योग्यता में कमी आती है जैसी व्यापक भ्रांति के आधार पर आरक्षण की आलोचना उच्च जाति के कुलीन वर्ग के हितों के अनुकूल है. शायद उन्होंने अपने दू. रगामी दृष्टि के चलते ही आरक्षण के विरुद्ध सुनियोजित ढंग से ऐसी भ्रांतियां पैदा की, जिन्हें आम जनमानस सहजता से स्वीकार करने लगा.
- अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा विप. रीत भेदभाव के दावों को वास्तविक समानता के प्रतिमान के तहत उचित ठहराया जाना चाहिए.
- यह निर्णय ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैध ानिकता की एक कठोर न्यायिक समीक्षा के लिए पृष्ठभूमि निर्मित करता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए सांस्कृतिक पूंजी की भूमिका की अनदेखी करता है और ओबीसी की क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए समान आय सीमा का निर्धारण करता है.
- यह निर्णय नीतिगत क्षेत्र में परीक्षाओं के ऐसे मॉडल के विकास की पहल करता है जो भाषाई, वर्गगत, स्कूल, बोर्ड और क्षेत्रीय पूर्वाग्रह से मुक्त हो.
- इस निर्णय के सदंर्भ में नीट पर जस्टिस एके राजन की रिपोर्ट, उच्च शिक्षा तक पहुंच के लोकतंत्रीकरण के लिए एक संभावित खाका हो सकती है.
- योग्यता के पीछे छिपे सामाजिक विशेष. ाधिकारों की मान्यता जातिगत जनगणना की मांग को भी पुष्ट करती है, यह दस्तावेज जातियों द्वारा संचित विशेषाधिकार को उजागर कर सकता है.

निष्कर्ष :-

इस निर्णय के आलोक में हमारे देश में योग्यता बनाम आरक्षण संबंधी एक लंबी, खंडित और निरर्थक बहस को सुलझाया जा सकता है. देश के सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ऐसे तर्कों के आने से जनता को विरासत में मिली जातिगत विशेषाधिकारों की वास्तविकता को समझना चाहिए. जो योग्यता के रूप में सामने आती हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि यह निर्णय न्यायिक आदेश में, सार्वजनिक नीति निर्माण में दूरगामी परिणाम देना वाला साबित होगा.

NOTES

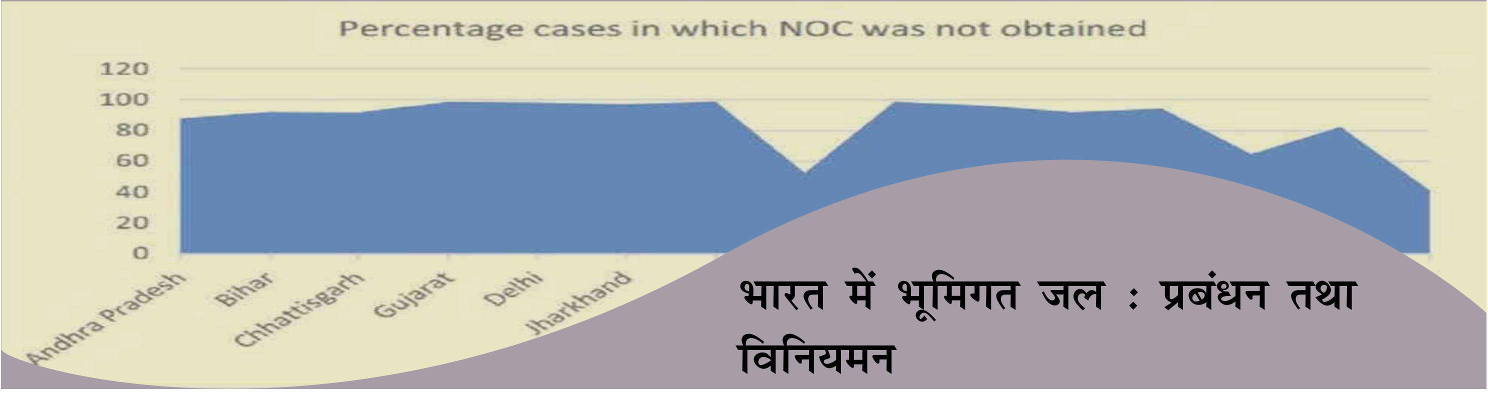

भारत में भूमिगत जल : प्रबंधन तथा विनियमन

परिचय

भूजल एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो कि कृषि तथा पेयजल के काम आता है. भूजल प्रबंधन तथा रेगुलेशन पर कैग ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए है. यह रिपोर्ट 2013 से 2018 तक के भूजल प्रबंधन से संबंधित है इसके साथ ही साथ यह भूजल प्रबंधन पर योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन भी करती है.

भूमिगत जल का निर्माण

चट्टानों तथा मिट्टी से रिस कर भूमि के नीचे जमा होने वाले जल को भूमिगत जल कहा जाता है. वह चट्टान जिन में भूमिगत जल जमा होते हैं उन्हें जलभृत या एक्वाइफर कहा जाता है.

एक्वाइफर सामान्य रूप से रेत बलुआ पत्थर चूना पत्थर इतिहास से बने होते हैं. इन चट्टानों में बड़ी तथा परस्पर जुड़ी हुई सुराखें होती हैं जो चट्टानों को पार्गम्मय बनाती हैं. इन्हीं सुराखों में से जल धरती के नीचे जाता है.

प्रमुख शब्दावली

- संतृप्त जोन: जलभृत में जिन स्थानों पर जल का जमा होता है.
- जलस्तर : धरती की सतह में जिस गहराई से जल प्राप्त होता है.

भारत में भूमिगत जल जमाव की स्थिति: भारत में मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में जलभृत पाए जाते हैं.

सिंधु गंगा के मैदान के कछारी जलभृत : यह भूमिगत जल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र है. यहां पर पाए जाने वाले जलभ्रितो में जलसंग्रहण की पर्याप्त क्षमता है. इस क्षेत्र में पेय जल तथा कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल का प्रयोग बढ़ रहा है. यह भारत के जलभृत क्षेत्र का लगभग 35% है.

प्रायद्वीपीय भारत में जलभृत : यह कठोर चट्टान वाला क्षेत्र भारत के समग्र जलभृत क्षेत्र का लगभग 65% भाग कवर करता है इन चट्टानों में जटिल तथा निम्न संग्रहण की जलभृत व्यवस्था तैयार होती है. इनकी जल भेदयता अत्यंत कम है, जिसके कारण ये बारिश होने पर भी दुबारा नहीं भर पाते. अतः निरंतर प्रयोग किए जाने से सूख जाते हैं.

भूजल की उपलब्धता

तालिका 1 : भारत में जल संसाधनों से संबंधित आंकड़े

मानदंड	इकाई (अरब क्यूबिक मीटर /वर्ष)
वार्षिक जल उपलब्धता	1,869
उपयोग योग्य जल	1,123
सतही जल	690
भूजल	433

भूजल प्रबंधन तथा रेगुलेशन पर कैग की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु :

- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूजल निष्कर्षण का स्तर (पुनर्भरण तथा निस्कर्षण का अनुपात) 2004 में 58 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 63 प्रतिशत हो गया है.
- दिल्ली, हरियाणा , राजस्थान में निष्कर्षण 100 प्रतिशत से अधिक है.
- 13 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में निष्कर्षन का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है.
- जिले के आधार पर आकलन के बाद रिपोर्ट ने यह पाया कि 267 जिलों में जल निकासी का स्तर 64 प्रतिशत से 384 प्रतिशत था. जो आगे चलकर जल संकट को जन्म दे सकता है.

कैग की रिपोर्ट : मुख्य समस्याएं तथा उन्हें हल करने के उपाय

- कैग ने बताया कि केंद्रीय भूजल बोर्ड को प्रति 2 वर्ष में भूजल संसाधनों का आंकलन करना चाहिए परंतु 2013 में आकलन के उपरांत अगला आंकलन 2017 में किया गया. कैग ने सुझाव दिया है कि आंकलन की अनियमितता को कम करना होगा.
- केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भी भूजल का आंकलन ऑब्जर्वेशन वेल्स के द्वारा किया जाता है, इसके लिए मार्च 2017 तक 50000 कुओं का प्रस्ताव रखा गया था परंतु मार्च 2019 तक मात्र 15000 कुएं बन पाए. इस संदर्भ में कैग ने यह सुझाव दिया कि जल शक्ति मंत्रालय को ओवजर्वेशनल वेल्स बढ़ाने पर विचार करना होगा.
- भूजल राज्य का विषय है. कई राज्यों में अलग अलग कानून हैं. जो कई बार असममित समस्या को जन्म देते हैं ।इस संदर्भ में कैग ने एक मॉडल कानून के निर्माण की बात कही है.
- उद्योगों को भूजल के उपयोग में एन ओ सी प्रदान की जाती है. यह केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है. कैग के आंकड़ों के अनुसार 2013 से 2018 के मध्य 474 एनओसीज का रिन्यूअल होना था परंतु इसके लिए आवेदको ने प्रस्ताव ही नही दिया. इस संदर्भ में कैग का यह प्रस्ताव है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों को कठोर रूप से लागू करना चाहिए.
- इसके साथ ही कैग ने यह बताया कि भूजल प्रबंधन तथा रेगुलेशन योजना के लिए स्वीकृत व्यय (4051 करोड़ रुपए) का मात्र 27 प्रतिशत वास्तविक रूप से व्यय किया गया. यह स्थिति त्रुटिपूर्ण प्रदर्शन को दर्शाती है. कैग ने इस संदर्भ में यह सुझाव दिया है कि विभाग को जलभृत क्षेत्र के मैपिंग का कार्य पूर्ण कर उस आधार पर व्यय करना चाहिए.

भारत में भूमिगत जल के अधिक दोहन के कारण

यूनेस्को की जल विकास रिपोर्ट-2018 में स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया गया है कि भारत सर्वाधिक भूमिगत जल के निष्कर्षण करने वाले देशो में एक है. भारत में भूमिगत जल के निष्कर्षण के मुख्य कारणो का वर्णन निम्नवत है.

- बढ़ता शहरीकरण :-भारत में तेजी से शहरीकरण का विकास हो रहा है. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने भी कहा है कि 2018 से 2050 के बीच भारत में शहरी आबादी 46.1 करोड़ से बढ़कर 87.7 करोड़ यानी दोगुनी हो जाएगी. इस स्थिति में आवासीय स्थानों के निर्माण, तथा शहरी जनता के उपभोग के लिए भूमिगत जल का तीव्र निष्कर्षण हो रहा है.
- हरित क्रांति :-हरित क्रांति तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणाओं ने कुछ फसलों की कृषि को समर्थन प्रदान किया.इसके फल. स्वरूप सूखा प्रवण अथवा कम जल वाले स्थानों में भी अधिक जल गहन फसलों का उत्पादन आरम्भ किया गया. फसल में लगने वाली आवश्यक जलापूर्ति भूमिगत जल के निष्कर्षण से की गई. इसके कारण भूमिगत जल का दोहन किया गया. सीजीडब्ल्यूबी के अनुसार, भारत में कृषि भूमि की सिंचाई के लिये प्रति वर्ष लगभग 230 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का निष्कर्षण किया जाता है.
- बढ़ता औद्योगिक क्षेत्र : भारत विक. ासशील देश से विकसित देश की प्रक्रिया में बढ़ रहा है. इसके लिए उद्योगों का विक. ास किया जा रहा है. विशेष, आर्थिक क्षेत्र तथा अन्नय आर्थिक क्षेत्रो का निर्माण किया जा रहा है. इसके लिए भूमिगत जल का निष्कर्षण किया जा रहा है. इसके साथ ही साथ उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण से अन्य जल स्रोत यथा नदिया, झरने इत्यादि प्रदूषित हो रहे हैं जिसके कारण, भूमिगत जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है.

उपरोक्त कारणो के साथ ही साथ विनियमन के अभाव के कारण भारत में तेजी से भू. मिगत जल को निष्कर्षित किया जा रहा है.

भारत में भूमिगत जल संरक्षण के उपाय :

भूमिगत जल के महत्व को जानते हुए सरकार ने भूमिगत जल संरक्षण के कई उपाय किये हैं. जिनका वर्णन निम्नवत है.

जल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिये मास्टर प्लान- 2020:

- इस प्लान को राज्य सरकारों की सहायता से सीजीडब्ल्यूबी द्वारा बनाया गया है.
- इस योजना का लक्ष्य लगभग 1.4 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का है.

जल शक्ति अभियान :-

- जल शक्ति अभियान के प्रथम चरण का आरम्भ 2019 में किया गया था.
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में जल की कमी वाले 256 जिलों में जल की कमी को दूर करना था.
- यह योजना 2022 में समाप्त हुई. इस योजना के दौरान देश के 256 जिलों के 2836 ब्लॉकों में से केवल 1592 जल संकट वाले ब्लॉकों को कवर किया गया.
- जल शक्ति अभियान का दूसरा चरण 22 मार्च 2021 (जल दिवस) के अवसर पर आरम्भ किया गया. इसका उद्देश्य मानसून आरम्भ होने के पूर्व कृत्रिम पुनर्भरण संरचन. ाओं का निर्माण, मौजूदा तालाबों और जल निकायों को पुनर्जीवित कर भूमिगत जल के संरक्षण से है.

अटल भूजल योजना:-

- 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई है.
- इस योजना का कुल परिव्यय 6 हजार करोड़ रुपए हैं तथा यह 5 वर्षों की अवधि (2020-21से 2024-25) के लिए लागू की जाएगी.
- इस योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिक. ता वाले 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा,कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जन भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है.
- इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 जिलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

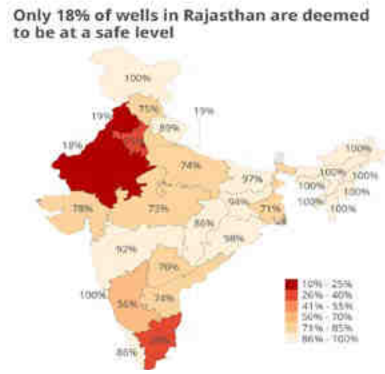

जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन

- जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत हेलीबॉर्न भू भौतिकी सर्वेक्षण (हेलीकॉप्टर द्वारा सर्वेक्षण) तथा अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड जल शक्ति मंत्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
- भूभौतिकीय डाटा का उपयोग पृथ्वी की सतह और उप सतह के भौतिक गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करना के लिए किया जाता है. इस प्रकार भू भौतिकी डेटा हाइड्रोकार्बन खनिज संग्रह तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने में मदद कर सकता है.
- हेलीबॉर्न भू भौतिकी के अध्ययनों का उपयोग करके **high&resolution** जलभ. ृत मानचित्रण तथा आर्टिफिशियल रिचार्ज हेतु साइट्स की पहचान करना है.

जल जीवन मिशन

- जल शक्ति मंत्रालय के तहत इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत के हर घर में पाइप से पानी की पहुंच सुनिश्चित करना है
- भारत सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार अर्थात हर घर नल से जल को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन में पुनर्गठित करने के साथ ही इसमें सम्मिलित किया है.

कैच द रेड : राष्ट्रीय जल मिशन

- हाल ही में राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र संगठन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से कैच द रेड नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है.

- इसकी टैगलाइन:"बारिश के पानी का संरक्षण, जहां भी संभव हो जैसे भी संभव है.
- सभी स्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहीत करने के लिए जल वर्षा संचयन संरचना का निर्माण करना है.

राष्ट्रीय जल नीति-2012:- इस नीति में सामुदायिक भागीदारी तथा वैज्ञानिक हस्तक्षेप के माध्यम से भूमिगत जल संरक्षण का प्रावधान किया गया है.

आगे की राह

- भूमिगत जल का संरक्षण पर्यावरण की दृष्टिकोण से अत्यंत अनिवार्य है. परन्तु इसके साथ- साथ आर्थिक विकास तथा शहरीकरण की आवश्यकता भी है. अत: यह आवश्यक है कि सरकार तथा निजी क्षेत्रक मिलकर महासागरीय तथा अनुपयोगी जल के उपयोग तथा जल के प्रयोज्य पुनर्चक्रण पर तकनीकी नवोन्मेष को बढ़ावा दें.
- पर्यावरण के संरक्षण से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि की जा सकती है. इसके साथ ही साथ आर्द्रभूमि के संरक्षण की भी आवश्यकता है.
- जल संरक्षण तथा भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए "स्वच्छ भारत अभियान" की तरह जन आंदोलन आरम्भ किया जाना चाहिए.

डिजिटल यूनिवर्सिटी : शिक्षा में नवीन युग का आरम्भ

परिचय :

कोविड-19 महामारी के उपरांत शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने से छात्रों को नुकसान उठाना पड़ा. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र डिजिटल क्रांति से अछूते रह गए थे. कोरोना के कारण शिक्षा में हुए हानि के प्रभाव को कम करने के लिए बजट 2022-23 में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है. यह डिजिटल विश्वविद्यालय विविध भाषाओं में उच्च गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करने में सक्षम होगा. इसकी अवधारणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित लक्ष्यों के साथ संरेखित है. हब एंड स्पोक मॉडल नेटवर्क पर काम करने वाली डिजिटल यूनिवर्सिटी में शिक्षा सेंट्रलाइज्ड कैंपस से निकलकर स्टूडेंट्स तक डिस्ट्रीब्यूट होगी. देश का प्रथम पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में अनावृत हो चुकी है. इस यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य "एजुकेशन ऐट योर डोरस्टेप (शिक्षा छात्र के द्वार) है.

बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्य प्रस्ताव :-

- बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि केंद्र सरकार "विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा" प्रदान करने तथा भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी. इस विश्वविद्यालय का निर्माण एक नेटवर्क हब-स्पोक मॉडल पर होगा. इस विश्वविद्यालय में बिल्डिंग अत्याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता और सार्वजनिक संस्थान हब-स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे.
- इसी के अंतर्गत सरकार कोरोना के दौरान हुए शैक्षिक हानि ('लर्निंग लॉस') के शमन के लिए 'प्रधानमंत्री ई-विद्या' **(PM e-Vidya)** के अंतर्गत 'वन क्लास वन टीवी चैनल ' के क्षेत्र में विस्तार करेगी. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि कोरोना के चलते हैं पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री ई-विद्या स्कीम के तहत फ्री चौनल 12 से बढ़ाकर 200 किए जाएंगे अत: सभी राज्यों में रीजनल भाषाओं में कक्षा 1 से 12 तक के लिए 200 फ्रीटीवी चौनल के माध्यम से पढ़ाई होगी.
- प्रस्तावित डिजिटल विश्वविद्यालय और विस्तारित टीवी शिक्षण कार्यक्रम से भारत के 'अमृत काल' में आगे बढ़ने हेतु आधुनिक, अग्रणी रूप रेखा तैयार करने में सहायता प्राप्त होगी.

भारत में डिजिटल यूनिवर्सिटी क्यों आवश्यक है ?

- कोरोना प्रभाव के शमन के लिए :- पिछले दो वर्षों में कोरोना के प्रभाव के कारण शिक्षा व्यापक रूप से प्रभावित हुई. इससे सिर्फ शिक्षा में व्यवधान नहीं हुआ बल्कि कई छात्रों के लिए शिक्षा का अंत हो गया. ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता के शैक्षिक असमानता में वृद्धि भी हुई है. चुकी शिक्षा मानव संसाधन के लिए अनिवार्य है इसीलिए शिक्षा पर कोरोना के प्रभाव को जल्द से जल्द कम करना आवश्यक है. इसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.
- एजुकेशन फॉर आल के लक्ष्य के लिए :- भारत में विषम सामाजिक -आर्थिक स्थिति के कारण कई छात्र (विशेष रूप से छात्रा) के लिए घर से कहीं दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं होता. डिजिटल यूनिवर्सिटी की अवधारणा इस समस्या को कम करने में सहायक होगी. डिजिटल यूनिव

सिटी की केंद्रीकृत नेटवर्क के माध्यम से देश के दूरदराज इलाके में बैठा व्यक्ति भी किसी यूनिवर्सिटी के विशेष पाठ्यक्रम में हिस्सा ले सकेगा. इसके साथ ही यह युनिवर्सिटी शिक्षा ग्रहण करने में भाषायी प्रतिबंधों का शमन करेगी. क्योंकि इसे लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओँ में संचालित किया जाएगा.

- एसडीजी -4 के लक्ष्यों की प्राप्त के लिए: डिजिटल यूनिवर्सिटी की संकल्पना एसडीजी -4 में वर्णित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी.

डिजिटल यूनिवर्सिटी के लाभ :

- लर्निंग का वर्तमान मॉडल छात्रों की आवश्यकताओं रूचियों वित्तीय क्षमता और विविध संज्ञानात्मक क्षमताओं का ध्यान रखने हेतु शिक्षा को अनुरूपता प्रदान कर सकने में विफल रहा है. डिजिटल युनिवेर्सिटी इस समस्या का समाधान कर सकती है.
- यह युनिवर्सिटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के संरेखण में तैयार होगी. जिससे नीतिगत दोहराव की समस्या से बचा जा सकेगा. इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित बहू विषयक शिक्षा की संकल्पना को डिजिटल माध्यम से आसानी से लागू किया जा सकता है.
- शिक्षा के डिजिटलीकरण के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण न्याय संगत और समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है तथा शिक्षा की भागीदारी और ज्ञानार्जन के परिणामों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच के अंतर को दूर किया जा सकता है.
- यह वंचित वर्ग के समावेशन में भी सहायक होगा. वर्तमान समय में दिव्यांग वर्ग, सामाजिक बंधन में फसी महिलाऐं / ट्रांसजेंडर इत्यादि, जो आसानी से भौतिक युनिवर्सिटी पहुंच पाने में सक्षम नहीं है उनकी समस्याओं का निवारण डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो सकता है.
- डिजिटल शिक्षा के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है जिसके द्वारा सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि होगी एवं कॉलेज ड्रॉपआउट जैसी समस्याओं का समाधान हो सकेगा.
- डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की स्थापना हो सकेगी.
- विद्यार्जन में भाषायी जानकरी बाधा नहीं बनेगी तथा क्षेत्रीय भाषाओँ का महत्व बढ़ेगा.
- इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार देखा जाएगातथा देश के कुशल शिक्षकों द्वारा तैयार किया हुआ पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए आसानी से उपलब्ध होगा.
- डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी समय की बाध्यता नहीं होगी.
- डिजिटल विश्वविद्यालय और विस्तारित टीवी शिक्षण कार्यक्रम से भारत के अमृत काल में आगे बढ़ने हेतु आधुनिक अग्रणी और व्यवहारिक खाका तैयार करने में मदद मिलेगी.
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व अन्य उभरते हुए क्षेत्रों में कुशल लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी में अनेक कार्यक्रम चलाए जाएंगे कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा.

डिजिटल यूनिवर्सिटी की संकल्पना के विरोध में तर्क

- स्कूल, कॉलेज अथवा शिक्षण संस्थान मात्र शिक्षा ग्रहण करने के स्थान नहीं होते. इसके साथ ही साथ इन शिक्षण संस्थानों में अनुशासन, टीम वर्क, सहयोग , प्रतिस्पर्धा , सामाजिक कुप्रथा पर कुठाराघात जैसे मूल्य भी विकसित होते हैं जोकि डिजिटल माध्यम द्वारा संभव नहीं है.
- आनलाइन शिक्षा के माध्यम से अधिगम स्तर में वृद्धि की जा सकती है परंतु इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता.
- ऑनलाइन शिक्षा क्योंकि पूंजीवाद समर्थित रहती है यह भी संभव है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से उपभोक्तावादी अथवा व्यक्तिवादी बन जाए. जो कि मनुष्य के सामाजिक स्थिति को प्रभावित करेगा.
- सौंदर्य संस्कृति, फैशन डिजाइन और सिलाई, यात्रा और पर्यटन आदि जैसे विषयों में व्यावहारिक ज्ञान (प्रैक्टिकल नॉलेज) की आवश्यकता होती है. इन विषयों में डिजिटल -लर्निंग प्रभावी नहीं है.

- ऑनलाइन शिक्षण को सार्थक शिक्षा का पूर्ण विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. स्कूल बंद रहने की स्थिति में यह कुछ संलग्नता प्रदान कर सकता है, लेकिन कक्षा और स्कूल के छात्रों या लर्निंग कम्युनिटी के लिए यह व्यक्तिगत शिक्षण के दृष्टिकोण से शैक्षणिक रूप से निम्नतर विकल्प ही है.
- डिजिटल लर्निंग कई सामाजिक- आर्थिक समस्याओं से भी संबंद्ध है. जिसमें बार-बार बाधित होने वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं बिजली कटौती से लेकर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करने की वित्तीय बाधाएं और देश में कॉलेज जाने वाले छात्रों के पास डिजिटल साक्षरता की कमी एवं डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच, साइबर हमले जैसी कई समस्याएं सम्मिलित हैं.

शिक्षा के डिजिटलीकरण के लिए किये गए प्रयास :-

- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड :- माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं वाले सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से.
- 'शगुन' :- सभी ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइटों के लिए एक जंक्शन बनाकर स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार करना.
- भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी :- देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए.
- शोधगंगा :- विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शोधार्थियों के लिए डिजिटल रिपोजिटरी.

आगे की राह

- ऑनलाइन अधिगम तथा ऑफलाइन अधि. गम के परस्पर सहयोग से विश्वविद्यालयों को छात्रों की प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने कार्यक्रम को अनुकूलित करना होगा.
- ऑनलाइन लर्निंग को एक बड़े जटिल तंत्र के छोटे से हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए. इसके साथ ही यहाँ प्रत्यक्ष मानव संलग्नता और सामाजिक शिक्षण को केंद्रीय भूमिका में रखा जाना चाहिए.
- डिजिटल विश्वविद्यालय में, स्वयं प्रभा ईपीजी पाठशाला, ई- ज्ञानकोष, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लैब जैसी पूर्ववर्ती योजनाओ के क्षमताओं को एकीकृत किया जा सकता है.
- डिजिटल विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया से लेकर डिजिटल प्रारूप में शिक्षण सामग्री प्रदान करने, ऑनलाइन अंत: क्रिया निरंतर मूल्यांकन और डिग्री प्रदान करने तक लर्निंग मूल्य श्रृंखला के सभी घटकों को एकत्रित कर सकते हैं.

दक्षिण एशिया में बढ़ती अस्थिरता तथा भारत

सन्दर्भ :-

हाल ही में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के मध्य कुनार प्रांत में डूरंड रेखा संघर्ष आरम्भ हो गया. यह क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है. वर्तमान में ऐसी कई स्थितियां हैं जिनके फलस्वरूप दक्षिण एशिया की स्थिरता प्रभावित हो रही है.

परिचय :-

यद्यपि अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय संबंध सदैव तनावपूर्ण रहे हैं परंतु वर्तमान में यह तनाव बढ़ चुका है. पाकिस्तान सेना के द्वारा अफगानिस्तान की सीमा के 15 किलोमीटर अंदर चाहर बुर्जक नंगहार, कुनार प्रांत तक अतिक्रमण के कारण पाकिस्तानी सेना तथा तालिबान के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है. वर्तमान में कई अन्य संकटों से ग्रस्त दक्षिण एशिया में स्थिरता बढ़ेगी. दक्षिण एशिया की अस्थि. रता से भारत की विश्व की नीति स्पष्ट रूप से प्रभावित होगी.

दक्षिण एशिया :

दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से अफग. ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालद. ीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका देश सम्मिलित हैं. इन देशो का एक संगठन है जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संग. ठन (SAARC दक्षेश) के नाम से जाना जाता है.2020 में दक्षिण एशिया की समग्र जनसँख्या 1.94 बिलियन तथा जीडीपी 3.326 ट्रिलियन रही है. यहाँ प्रतिव्यक्ति आय 1826 डालर रही.

दक्षिण एशियाई अस्थिरता :

क्षेत्रीय संघर्ष

भारत तथा पाकिस्तान की आपसी प्रतिद्व ंद जग विख्यात है इसके साथ पाकिस्तान -अफगानिस्तान में तनाव, भारत तथा नेपाल के सीमा विवाद ने क्षेत्र की अस्थिरता को बढ़ावा दिया है.

देशों की आंतरिक कलह

अभी हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अफगानिस्तान में तालिबान तथा लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के आंतरिक कलह को देखा है. नेपाल में मधेसी आंदोलन, म्यांमार में सेना तथा लोकतांत्रिक तत्वों के बीच तनाव, मालदीव में आंतरिक गतिरोध जैसी समस्याएं दक्षिण एशिया की अस्थिरता को बढाती हैं.

गैरराज्य अभिकर्ताओं की बढ़ती गति. विधियां

यह क्षेत्र गैर राज्य अभिकर्ताओं की बढ़ती गतिविधियों से भी संकट ग्रस्त है. यहाँ आतंकवाद , नक्सलवाद, संगठित अपराध की समस्यांए हैं. सम्पूर्ण विश्व में अवैध ड्रग्स तस्करो के लिए स्वर्ग माने जाने वाले दो क्षेत्र गोल्डन क्रिसेंट (ईरान-अफगानिस्तान-पाि. कस्तान) तथा गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, थाईलैंड और लाओस) इस क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव डालते हैं. इन अभिकर्ताओं की गति. विधियां क्षेत्र की अस्थिरता को बढ़ाती हैं.

उपरोक्त स्थितियों के साथ साथ देशो में आंतरिक सांप्रदायिक समस्याएं , नृजातीय तथा धार्मिक संघर्ष होते रहते हैं जो क्षेत्र की अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं.

दक्षिण एशियाई अस्थिरता के कारण

कृत्रिम सीमाएं

दक्षिण एशियाई क्षेत्र मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है. यह पूरा क्षेत्र उत्तर में हिमालय पश्चिम में हिंदू कुश तथा दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर क्षेत्र से घिरा है। क्षेत्र में भौगोलिक सीमाएं लगभग शून्य हैं तथा भौगोलिक रूप से यह सभी देश एक ही भूभाग का हिस्सा हैं. यहां ऐतिहासिक गलतियों तथा औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के कारण कृत्रिम सीमाओं का निर्माण हुआ है यह कृत्रिम सीमाएं त्रुटिपूर्ण

हैं. कृत्रिम सीमाओं की त्रुटियां क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा देती हैं.

देशों के मध्य आपसी विश्वास संकट

भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत तथा तालिबान नेतृत्व,नेपाल इत्यादि एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते. यहां एक बिग ब्रदर सिंड्रोम की अवधारणा चलती है जिसके अंतर्गत यह मानते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखता है. यह स्थितियां क्षेत्र में विश्वास संकट को जन्म देती है.

चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव

दक्षिण एशियाई देशों में आपसी विश्वास संकट के कारण चीन को दक्षिण एशिया में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हो रहा है. छोटे देश भारत को संतुलित करने के लिए चीन की तरफ देख रहे हैं जिससे चीन इन देशों में व्यापक पहुंच स्थापित कर रहा है. चीन बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव परियोजना के माध्यम से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वित्तीय साम्राज्यवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तथा लगातार दक्षिण एशिया को अस्थिर कर रहा है.

सामाजिक समस्याएं

दक्षिण एशिया का मानव विकास सूचकांक लगभग 0.70 है. यह क्षेत्र जनसंख्या दबाव, गरीबी, भुखमरी, रोजगार संकट से ग्रस्त है. इसी के फलस्वरूप यहां अपराध भी अधिक होते हैं.

आर्थिक संकट

क्षेत्र विश्व की लगभग 24.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है परंतु यह क्षेत्र मात्र 4.42 % वैश्विक जीडीपी का उत्पादन करता है. जिसके कारण यहां क्षमता अत्यंत कम है. इसके साथ ही साथ यहां आर्थिक एकीकरण के प्रयास तथा सहयोग अत्यंत नगण्य हैं. आर्थिक अस्थिरता के कारण दक्षिण एशियाई देश प्राय: अस्थिर होते हैं.

शरणार्थी संकट

क्षेत्र शरणार्थी संकट से भी ग्रस्त है. रोहिंग्या समस्या , चकमा शरणार्थी समस्या के कारण भारत में तनाव बढ़ रहा है.

धार्मिक संघर्ष

क्षेत्र में प्राय: धर्म संघर्ष भी होते रहते हैं. म्यांमार में बौद्ध समुदाय अल्पसंख्यक मुसलमान को अपना नागरिक नहीं मानता वही पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश (जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं) में अन्य अल्पसंख्यकों का धार्मिक उत्पीड़न किया जाता है. भारत में भी प्राय: सांप्रदायिकता धर्म संघर्ष होते रहते हैं.

दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए क्या करना होगा ?

- वर्तमान दौर वैश्वीकरण की अपेक्षा क्षेत्रीय अनुबंधों का दौर है. यूरोपीय संघ, आसियान जैसे कई क्षेत्रीय संगठन है जो व्यापक आर्थिक प्रगति कर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. दक्षिण एशिया में आर्थिक संभावनाएं बहुत अधिक है परंतु आपसी संघर्ष तथा तनाव के कारण आर्थिक संभावनाओं का दोहन नहीं किया जाता रहा है. दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए आर्थिक विकास अत्यंत आवश्यक है. इस संदर्भ में सभी देशों को सोचना चाहिए.
- वर्तमान समय में वैश्विक महाशक्तियां क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रही है. विश्व शक्ति संतुलन यूरोप तथा अटलांटिक से हटकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शिफ्ट हो गया है. जल्द ही दक्षिण एशिया वैश्विक महा शक्तियों का युद्धस्थल बनने वाला है. दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्वाधीनता बचाने के लिए यह आवश्यक है कि दक्षेस को मजबूत किया जाए.
- वर्तमान समय में चीन वित्तीय साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है. इस वित्तीय साम्राज्यवाद के कारण श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह, बांग्लादेश के बंदरगाह इत्यादि में चीन की पहुंच बढ़ रही है। क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए चीन को क्षेत्र से दूर करना होगा.
- भारत तथा पाकिस्तान इस क्षेत्र के दो सबसे बड़े देश हैं. दोनों को क्षेत्र की स्थिरता के लिए पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए.
- इस संदर्भ में भारत को बड़ी भूमिका निभानी होगी. जीडीपी क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के मामले में भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। आसियान की देश भारत को चीन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका में देखते हैं परंतु दक्षिण एशिया की असुरक्षा से भारत की सुरक्षा प्रदाता की भूमिका पर संदेह किया जा सकता है. यद्यपि भूटान के डोकलाम विवाद ने भारत ने यह दिखाया कि क्षेत्रीय स्वाधीनता के लिए वह चीन के सामने खड़ा हो सकता है.
- इसके साथ ही साथ भारत को क्षेत्र में विश्वास संकट को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए. भारत इस दिशा में प्रयासरत भी है हाल ही में आए करो ना महामारी में भारत में दक्षिण एशियाई देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई इसके साथ ही साथ 10 मिलियन डॉलर का इमरजेंसी फंड बनवाया है जो विश्वास संकट को कम करने में सहायक हो सकता है.

निष्कर्ष

वैश्वीकरण के कमजोर होने के साथ ही क्षेत्रीय गठजोड़ो की भूमिका बढ़ेगी. यह क्षेत्र भौगोलिक, सांस्कृतिक रूप से लगभ्ग समान है. इनकी समस्याएं भी लगभग समान हैं. समान समस्याओं का साझा निदान किया जा सकता है तथा निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि स्थिर दक्षिण एशिया में ही भारत का हित है. भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है ऐसे में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है. इसके साथ ही भारत यदि वैश्विक स्तर पर नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वयं की भूमिका चाह रहा है तो भारत को दक्षेस को स्थिर करना होगा.

संक्षिप्त मुद्दे

1 देश के शीर्ष जॉब पोर्टल के साथ सरकार की बैठक

श्रम और रोजगार मंत्रालय नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) परियोजना को एक मिशन मोड परियोजना के तौर पर लागू कर रहा है ताकि रोजगार से संबंधित विभिन्न सेवाएं जैसे जॉब मैचिंग, करियर काउंसलिंग, वोकेशनल गाइडेंस, कौशल विकास संबंधी जानकारी प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम, अप. रेंटिसशिप, इंटर्नशिप आदि प्रदान की जा सके. एनसीएस के तहत सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं. जिन्हें 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया या था. इस पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाएं सभी हितधारकों के लिए मुफ्त हैं. इन हितधारकों में नौकरी चाहने वाले, नियोक्ता, प्रशिक्षण प्रदाता और प्लेसमेंट संगठन शामिल हैं. एनसीएस पोर्टल्स को सीधे तौर पर अथवा करियर सेंटर (रोजगार एक्सचेंज), कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑ. फिस नेटवर्क, मोबाइल, साइबर कैफे आदि के जरिये एक्सेस किया जा सकता है.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भारत में 'एम्प्लॉयमेंट एंड स्कि. लिंग इकोसिस्टम' यानी रोजगार एवं कौशल परिवेश को मजबूती प्रदान करने के लिए देश के शीर्ष निजी जॉब पोर्टल के प्रतिनिधियों के साथ 10 फरवरी 2022 को एक बैठक की. श्रम एवं रोजगार सचिव ने अपने उपयोग. कर्ताओं के लिए नौकरी एवं कौशल संबंधी अवसरों को बेहतर करने के लिए पूरे परिवेश की मजबूती के लिए मंत्रालय के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी. उन्होंने प्रतिभागियों को यह भी बताया कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुरूप उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़े रहेंगे.

बैठक में नौकरी, मॉन्स्टर, लिंक्डइन, इंडीड, टाइम्सजॉब्स, क्वेस कॉर्प लिमिटेड, एचटी शाइन, फ्रेशर्सवर्ल्ड (टीमलीज की कंपनी), क्विकरजॉब्स, पोर्शिया, फ्रेशर्स लाइव, हाय. रमी, फर्स्टजॉब जैसे शीर्ष निजी जॉब पोर्टल के प्रतिनिधियों ने काफी उत्साह के साथ भाग लिया और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की सराहना की. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव ने यह भी बताया कि भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की) और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) जैसे शीर्ष उद्योग संगठनों ने भी देश में रोजगार एवं कौशल परिवेश को मजबूत करने के विषय पर सहमति जताई है.

श्रम एवं रोजगार सचिव ने सभी उद्योगों में सभी रोजगार एवं कौशल विकास सं. बंधी पहल के लिए नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए मंत्रालय के दृष्टिकोण को रेखांकित किया. उन्होंने ई-श्रम, उद्यम और असीम पोर्टल के साथ लिंकेज पर भी जोर दिया. प्रतिभागियों को एनसीएस पर आसान पंजीकरण की सु. विधा के लिए ईश्रम और ईपीएफओ द्वारा जारी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का लाभ उठाने के लिए मंत्रालय की पहल के बारे में भी बताया गया.

2 आंध्र प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन के बाद रायलसीमा क्षेत्र चर्चा में

आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 13 नए जिलों के गठन का निर्णय किया है और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो जाएगी. आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. अच्छा प्रशासन और विकास करने की मंशा को इस निर्णय के पीछे आधार बताया गया है. आंध्र प्रदेश डि. स्ट्रिक्ट फॉरमेशन एक्ट 1974 की धारा 3 की उपधारा 5 के तहत इन नए जिलों का गठन किया जाना है.

दो नए आदिवासी जिलों का निर्माण किया जा रहा है एक तो मन्यम जिसका मुख्यालय पार्वतीपुरम में होगा और दूसरा अल्लूरी सीता. राम राजू जनपद जिसका नाम तेलुगु स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है. अनाकाप. ल्ली, कोनसीमा, काकीनाडा, एलुरु, एनटी. आर, बापटला और पलनाडु, नंदयाल, श्री सत्य साई, अन्नामाया और श्री बालाजी जिलों का गठन किया जाना है.

इसी के साथ कुछ अन्य महान व्यक्तित्वों, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर आंध्र प्रदेश में जिलों को बनाने की मांग तेज हो गई है जिसमें सबसे प्रमुख नाम है भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की. अभी कुछ माह पहले आंध्र प्रदेश के सीएम ने भारत के तिरंगे झंडे को डिजाईन करने वाले फ्रीडम आर्टिस्ट, स्वतन्त्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया को भारत रत्न देने की मांग की थी.

भूगर्भ शास्त्र में रुचि रखने वाले पिंगाली वेंकैया को हीरे के खनन का इतना ज्ञान था कि उन्हें उनके जन्म स्थान मछलीपट्टनम के लोग डायमंड वेंकैया कहते थे. कांग्रेस के 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में उन्होंने ही सबसे पहले तिरंगे झंडे का सुझाव दिया था. रायलसीमा क्षेत्र में 4 जिले बन रहे हैं जिसमें कुरनूल, कडप्पा,चित्तूर और अनंतपुर शामिल

थे और यह सभी चारों पारंपरिक रूप से लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट रहे हैं. अब यह 4 जिले 8 नए जिलों में पुनर्गठित किए गए हैं जिसके बाद रायलसीमा के पास पहली बार अपना समुद्र तट भी हो गया है. लंबे समय से आंध्र प्रदेश में तटीय और गैर तटीय जिलों के विभाजन में असमानता देखी गई है लेकिन अब शुष्क रायलसीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश के जिलों के पुनर्गठन के बाद पहली बार समुद्री तट वाला क्षेत्र हो गया है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो नया जिला श्री बालाजी जिला बना है उसके दायरे में नेल्लोर के कुछ भाग भी शामिल हो गए हैं. श्री बालाजी डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय तिरुपति होगा.

3 इन्टेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0

भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बृहद टीकाकरण अभियान लागू कर रहा है. भारत के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार हर साल तीन करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जायेगा. हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आईएमआई 4.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया.

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि **COVID**-19 महामारी के कारण उभरी कमियों को दूर करने के लिए IMI 4.0 के तीन चरणों की योजना तैयार की गई है. इसे कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों में लागू किया जायेगा. पहले चरण (फरवरी-अप्रैल 2022) में आईएमआई 4.0 का संचालन 11 राज्यों में किया जायेगा. ये राज्य- असम, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ हैं. अन्य 22 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशो में अप्रैल-मई 2022 में योजना का संचालन किया जायेगा। इन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पुडुचेरी, दिल्ली, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं.

मिशन इंद्रधनुष -

- मिशन इंद्रधनुष 2014 में आरम्भ किया गया भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है. यह योजना 2022 तक भारत के 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य रखती है.
- मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन सभी असंबद्ध अथवा आंशिक टीकाकृत बच्चों को कवर कर सार्वभौमिक टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंचना था.

इंटेन्सीफाइड मिशन इंद्रधनुष :-

- टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक तीव्रता प्रदान करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2017 को गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) का शुभारंभ किया. इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य दो साल तक के प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं को कवर करना था जिन्हे इसके पूर्व की नियमित टीकाकरण कार्यक्रम/यूआईपी योजनाओ में इन्क्लूजन एरर का सामना करना पड़ा. 90% पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को 2020 के स्थान पर दिसंबर 2018 में ही पा लिया गया.

इन्टेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 :-

- देश में नियमित टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2019 से सभी उपलब्ध टीकों की पहुंच से बाहर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए इन्टेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 आरम्भ किया गया.
- इसका उद्देश्य 2030 तक प्रिवेंटिव चाइल्ड डेथ को समाप्त करने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है.
- इसका उद्देश्य 27 राज्यों में 272 जिलों और उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्लॉक स्तर (652 ब्लॉक) पर टीकाकरण करना है. यह रिमोट क्षेत्रों तथा आदिवासी आबादी को कवर करता है.

इन्टेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 :-

- यह नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से छूट जाने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से सम्बंधित अभियान है.
- इसका उद्देश्य मिशन मोड हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण में तेजी लाना है.
- यह देश के पहले से पहचाने गए 250 जिलों/शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है.
- इसमें महामारी के दौरान टीकाकरण से वंचित प्रवास क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों के लाभार्थियों को लक्षित किया जाएगा.

यह टीकाकरण बड़े पैमाने पर बीमारियों के प्रकोप को रोकने के साथ-साथ एक क्षेत्र में बीमारी को नियंत्रित कर स्वास्थ्य प्रणाली के स्ट्रेस को कम करता है. अतः टीकाकरण मातृ मृत्यु दर तथा बाल मृत्युदर के संकेतकों को सुधारने में सहायक होता है. निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम योजना के साथ मिशन इंद्रधनुष संयुक्त राष्ट्र द्वारा बीमारियों के उन्मूलन, शिशु मृत्यु दर को कम करने और गर्भवती महिला और उसके बच्चे को अधिक सहायता प्रदान करने के स्थायी लक्ष्यों को पूरा करने में एक मास्टर स्ट्रोक है.

अंतरराष्ट्रीय

1 भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य सीईसीए समझौता

चर्चा में क्यों:

हाल ही में कैनबरा के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ एक "अंतरिम" मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)करने के लिए प्रतिबद्ध है.

व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) क्या है?

- यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है.
- सामान्य रूप से सीईसीए केवल व्यापार शुल्क और टीआरक्यू (टैरिफ दर कोटा) दरों पर बातचीत को कवर करता है. इसकी व्यापकता सीईपीए से कम है. भारत ने मलेशिया और सिंगापुर के साथ सीईसीए पर हस्ताक्षर किए हैं.
- समझौते का उद्देश्य व्यापार और निवेश प्रवाह के विस्तार द्वारा आर्थिक और सामाजिक लाभों को बढ़ाना, जीवन स्तर में सुधार करना और अपने संबंधित क्षेत्रों में वास्तविक आय में उच्च और स्थिर वृद्धि सुनिश्चित करना है.

व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों (सीईसीए) के लाभ:-

- सीईसीए भारत और ऑस्ट्रेलिया में अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन में योगदान देता है, इसके साथ ही यह भारत में व्यवसायों के लिए अधिक व्यापार तथा निवेश से लाभ के अवसर प्रदान करता है.
- सीईसीए न केवल टैरिफ को कम अथवा समाप्त करते है बल्कि वे वस्तुओं तथा सेवाओं के मार्ग में आने वाले अन्य बाधाओं को भी दूर करने का प्रयास करता है. इसके साथ ही साथ यह निवेश को प्रोत्साहित करने, बौद्धिक सम्पदा को बढ़ाने, ई-कॉमर्स और सरकारी खरीद जैसे मुद्दों को प्रभावित करने वाले नियमों में सुधार के सन्दर्भ में भी वार्ता को महत्व देता है.
- सीईसीए भारत के व्यवसायों और उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी मूल्य वाली वस्तुओं और सेवाओं, नई तकनीकों और नवीन प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है.
- सीईसीए भारत को विदेशी निवेश से अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद करता है.
- सीईसीए क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं और भारत और हमारे व्यापारिक भागीदारों के बीच व्यापार और निवेश के लिए साझा दृष्टिकोण का निर्माण करता है.
- सीईसीए उन्नत व्यापार तथा निवेश के अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक विकास हो सकता है.
- सीईसीए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तथा बी2बी सम्बन्धो का समर्थन करता है इसके साथ ही यह एफटीए भागीदारों के साथ भारत के समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाता है.
- सीईसीए भारत तथा अन्य व्यापारिक भागीदारों को अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकते हैं. इसके साथ ही ये नियामक सुधार तथा व्यापार उदारीकरण को प्रोत्साहित कर सकते हैं.

भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार संबंध-:

- दोनों देशो के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 2007 में 10.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 18.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया.
- 2020 में, भारत ऑस्ट्रेलिया का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, कोयला और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा संचालित छठा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया भी भारतीय निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य है.
- 2020 में, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद परिष्कृत पेट्रोलियम (287 मिलियन अमेरिकी डॉलर), पैकड दवाएं (277 मिलियन अमेरिकी डॉलर), और रेलवे पैसेंजर कारे (166 मिलियन अमेरिकी डॉलर)हैं.
- 2020 में, भारत के लिए ऑस्ट्रेलियाई निर्यात 15.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को निर्यात किए जाने वाले मुख्य उत्पाद कोयला ब्रिकेट (12.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर), सोना (604 मिलियन अमेरिकी डॉलर), और पेट्रोलियम गैस (419 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था.
- 2020 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश **(FDI)** का कुल मूल्य 1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर था.

अन्य देशों के साथ भारत का सीईसीए

- सिंगापुर और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए 29 जून 2005 को सीईसीए पर हस्ताक्षर किए गए थे.
- मलेशिया और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए, सीईसीए पर 27 अक्टूबर 2010 को कुआलालंपुर, मलेशिया में हस्ताक्षर किए गए थे.

पर्यावरण

1 भारत के दो नए स्थल रामसर स्थल घोषित हुए

विश्व आर्द्रभूमि दिवस (2 फरवरी) के दिन पर्यावरण के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी उपलब्धि फिर हासिल हुई है. भारत के दो और अभयारण्यों को रामसर साइट घोषित किया गया है और इसके साथ ही भारत से अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुल आर्द्रभूमियों की संख्या 47 से बढ़कर 49 हो गई है. गुजरात के खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में हैदरपुर वेटलैंड को अभी हाल ही में भारत का 47 वां रामसर स्थल घोषित किया गया था.

भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि विकास और पर्यावरण का साथ साथ चलना भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 40% जैव विविधता वेटलैंड से ही आती है। गौरतलब है कि भारत में 200000 से अधिक छोटे तालाब हैं ,उनमें से कई ऐसे हैं जिनको संरक्षित किए जाने की जरूरत है क्योंकि वहां पर जलीय पक्षी और अन्य जीव-जंतुओं के संरक्षण की जरूरत है. भारत में इस समय 49 रामसर स्थल हैं. ये 10.93 हेक्टेयर के इलाके में फैले हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा इलाका है.''

रामसर संधि आर्द्रभूमि के संरक्षण और कुशलता से उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है. इसका नाम कैस्पियन सागर पर ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां दो फरवरी, 1971 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे.

उत्तर प्रदेश से अब कुल १० वेटलैंड हुए रामसर स्थल :

- ऊपरी गंगा नदी (ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव)
- नवाबगंज पक्षी अभयारण्य (उन्नाव)
- साण्डी पक्षी अभयारण्य (हरदोई),
- समसपुर पक्षी अभयारण्य (रायबरेली)
- समन पक्षी अभयारण्य (मैनपुरी),
- पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य (गोंडा),
- सरसई नावर झील (इटावा),
- सुर सरोवर झील/कीथम झील (आगरा),
- हैदरपुर वेटलैंड
- बखिरा वन्यजीव अभयारण्य (संत कबीर नगर)

2 एनजीटी द्वारा पर्यावरणीय जुर्माना

हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वेदांता ग्रुप के फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना लगाने के पीछे का आधार यह है कि रा. जस्थान के भीलवाड़ा जिले में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन किया है. दरअसल एनजीटी के पास एक मामला आया था जिसमें यह कहा गया था कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1200 हेक्टेयर खनन क्षेत्र के पास स्थित गांवों में लेड जिंक और अन्य संबंधित खनिजों के माइनिंग लीज को एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है और इस आधार पर पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन हो रहा है. एनजीटी के चेयर पर्सन जस्टिस एके गोयल ने भीलवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए गए निर्देश में कहा है कि खनन के इन प्रोजेक्ट्स से गांव पर पड़ने वाले असर और उसमें सुधार करने पर आने वाली लागत के रूप में 25 करोड़ रुपये जुर्माना 3 माह के अंदर अंदर जमा किए जाए. इसके साथ ही एनजीटी ने यह भी निर्देश दिया है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा की एक ज्वाइंट कमिटी ऐसा रेस्टो. रेशन प्लान तैयार करें जिससे भीलवाड़ा के क्षेत्रों के भूमिगत जल की गुणवत्ता और मिट्टी का स्वास्थ्य बना रह सके. एनजीटी का कहना है कि 6 पंचायतों भेरूखेड़ा, कोठिया, बालापुरा, परसरामपुरा, आगूचा, कल्याणपुरा में रहने वाले लोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के विकास कार्यों के भुक्तभोगी हैं.

18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधि करण की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी. पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से सं. बंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए इसे बनाया गया था.

यह भुक्तभोगी व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करने का काम भी करती है. यह एक विशिष्ट निकाय है जो कि पर्यावरण विवादों का समाधान करती है. यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के किसी भी **procedure** यानी कार्यविधि से चलने के लिए बाध्य नही है बल्कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों से निर्देशित होती है.

यह अधिकरण आवेदनों और याचिकाओं को प्राप्ति से 6 माह के अंदर उसके निपटारा हेतु प्रयत्न करने लिए आदेशाधीन है. यानी उसे ऐसा करने का उंदकंजम मिला है.

अधिकरण की प्रधान बेंच नई-दिल्ली में और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अधिकरण के अन्य चार बेंच है.

विज्ञान एवं तकनीक

1 परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन ऊर्जा (सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया) के उत्पादन में एक नवीन कीर्तिमान स्थापित किया है. परमाणु संलयन ऊर्जा पर खोज मानव की बहुप्रतीक्षित खोजो में से एक है क्योंकि इससे कम कार्बन उत्सर्जित होता है. साथ ही साथ इसके प्रयोग से परमाणु ऊर्जा का सुरक्षित तथा दक्ष उत्पादन (तकनीकी रूप से 100% से अधिक) सुनिश्चित किया जा सकता है.

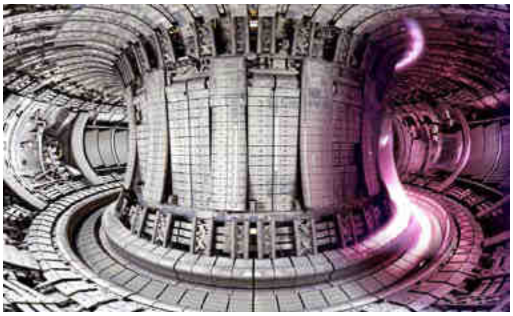

परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी :-

परमाणु संलयन प्रक्रिया में, दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा वे इस प्रक्रिया में भारी ऊर्जा निर्गमित करते हैं. इस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों को फ्यूजन रिएक्टर के रूप में जाना जाता है. परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं सूर्य और अन्य तारो की ऊर्जा का कारक होती हैं. इस प्रक्रिया में परिणामी एकल नाभिक का कुल द्रव्यमान दो मूल नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है, यही द्रव्यमान अंतराल इस प्रक्रिया में निर्गमित ऊर्जा का कारक होता है. परमाणु संलयन में उपयोग किए जाने वाले मुख्य ईंधन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हैं, दोनों हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक हैं। ड्यूटेरियम प्राकृतिक हाइड्रोजन का एक छोटा अंश (केवल 0,0153%,) है, तथा इसे समुद्री जल से सस्ते में निकाला जा सकता है. लिथियम से ट्रिटियम बनाया जा सकता है, यह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है.

परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी के लाभ :-

- **निम्न परमाणु अपशिष्ट:-** नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में परमाणु वेस्ट का उत्पादन नाभिकीय विखंडन की तुलना में कम होता है. अतः इस प्रक्रिया के उपयोग में वेस्ट निस्तारण की समस्या भी कम होगी. साथ ही साथ इस प्रक्रिया के अपशिष्ट का प्रयोग नाभिकीय शस्त्र के निर्माण में नहीं हो होता है.
- **कार्बन तटस्थ:-** संलयन प्रक्रिया से कोई CO_2 या अन्य हानिकारक वायुमंडलीय उत्सर्जन नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि संलयन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करता है.
- **कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी सिस्टम्स के अनुसार:-** "परमाणु संलयन ऊर्जा भविष्य में बेसलोड ऊर्जा के रूप में एक अच्छा विकल्प है, जिसमें कई लाभ हैं.
- परमाणु संलयन ऊर्जा के कई संभावित लाभ हैं, क्योंकि यह बिजली उत्पादन के लिए दीर्घकालिक, सतत, आर्थिक और सुरक्षित ऊर्जा स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है.
- इसमें प्रयुक्त ईंधन सस्ता है तथा यह प्रचुर मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध है. 1 लीटर जल में उपलब्ध ड्यूटेरियम की मात्रा सैद्धांतिक रूप से 300 लीटर जीवाश्म ईंधन के दहन के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है. अर्थात महासागरों में व्याप्त ड्यूटेरियम लाखों वर्षों तक मानव ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.

परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी की क्षमता:-

- परमाणु संलयन ऊर्जा का प्रयोग उच्च ऊर्जा आवश्यकता वाली अंतरिक्ष यात्राओं में भी किया जा सकता है. मंगल ग्रह से आगे की परियोजनाओं (अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो के परिवहन के उद्देश्य) के लिए लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों द्वारा प्रणोदन के लिए लेजर इग्नाइटेड (डी, टी) कैप्सूल के माध्यम से संलयन ऊर्जा के प्रत्यक्ष उपयोग की अवधारणा का प्रयोग किया है.
- परमाणु संलयन सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारो की ऊर्जा का स्रोत है. पृथ्वी पर संलयन ऊर्जा का उपयोग, बढ़ती विश्व जनसंख्या की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावहारिक तथा सतत अक्षय ऊर्जा का विकल्प प्रदान करेगा.

परमाणु संलयन का भविष्य अनिश्चित है. संलयन के विषय में पिछले दो दशकों से प्रयास किये गए हैं, साथ ही साथ इस उद्देश्य के लिए चुंबकीय प्रौद्योगिकियों का प्रयोग भी बढ़ा है. लेजर और कण बीम प्रत्यारोपण पर भी काम किया जा रहा है. यद्यपि इस क्षेत्र में विकास उत्साह जनक है इसकी संभावनाएं भी अधिक हैं परन्तु यह भी अन्य रूप से सत्य है कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक काम किया जाना बाकी है.

2 बायोमास आधारित हाइड्रोजन

देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगाया जा रहा है. संयंत्र 30 टन बायोमास फीडस्टॉक से प्रतिदिन एक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा.

बायोमास-

बायोमास को ऐसी सामग्री के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो एक जीवित जगत यथा जीव-जंतुओं, पेड़ पौधों का हिस्सा था या है. हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए, बायोमास की परिभाषा केवल उन सामग्रियों को शामिल करने तक सीमित है जो पौधों से प्राप्त होती हैं जैसे कि कृषि अवशेष.

ऊर्जा के लिए बायोमास स्रोतों में शामिल हैं :-

- **लकड़ी और लकड़ी प्रसंस्करण अपशिष्ट :-** जलाऊ लकड़ी, लकड़ी की चिपाके, लकड़ी और फर्नीचर का अपशिष्ट और मिल से मिली लुगदी पेपर.
- **कृषि फसलें और अपशिष्ट पदार्थ :-** मक्का, सोयाबीन, गन्ना, पौधे और शैवाल, फसल और खाद्य प्रसंस्करण अवशेष
- **नगरपालिका के ठोस कचरे में बायोजेनिक सामग्री :-** कागज, कपास, और ऊन उत्पाद, यार्ड और लकड़ी के अपशिष्ट.
- पशु खाद और मानव सीवेज.

बायोमास से हाइड्रोजन का उत्पादन क्यों महत्वपूर्ण है?

अक्षय स्रोत :- बायोमास ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है क्योंकि इसे अधिक पेड़ पौधे लगाकर नवीनीकृत किया जा सकता है. अत: बायोमास से हाइड्रोजन का उत्पादन एक नवीकरणीय ईंधन है. भारत मुख्य रूप से कृषि आधारित देश होने के नाते, हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए कृषि अवशेषों से बायोमास की उपलब्धता का लाभ उठा सकता है.

हरित गैस उत्सर्जन (जीएचजी) कम करता है :- प्राकृतिक विकास की अपनी प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे वातावरण से उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग कर बायोमास बनाते हैं. बायोमास गैसीकरण के माध्यम से हाइड्रोजन के उत्पादन से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को बंद कर देते हैं जिससे नेट ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है.

कम लागत :- बायोमास मार्ग के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन भारत के लिए एक व्यवहारिक लागत प्रभावी और कुशल विकल्प हो सकता है. बायोमास से बिजली उत्पादन भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, हालांकि बायोमास से हाइड्रोजन का उत्पादन अभी शुरुवाती चरण में होने के बावजूद भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आशान्वित करता है.

प्रचुर मात्रा में स्रोत :- भारत मुख्य रूप से कृषि आधारित देश होने के कारण, हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए कृषि अवशेषों से बायोमास की उपलब्धता का लाभ उठा सकता है. भारत में भोजन और पशुओं के चारे की जरूरत से कई अधिक बायोमास उपलब्ध है.

कार्बन न्यूट्रल:- यद्यपि हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है, जो उद्योग, बिजली और परिवहन जैसे कई क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है. जीवाश्म ईंधन द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाना एक विकार्बनिकारक के रूप में इसकी क्षमता को कम करता है. हालांकि, अक्षय स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन उत्सर्जन मुक्त है और इसे हरित ईंधन माना जाता है. इस हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की विधियों में से बायोमास कार्बन तटस्थ फीडस्टॉक का एक माध्यम से हो सकता है.

आगे की राह :-

बायोमास गैसीकरण के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रमुख चुनौतियों में पूंजीगत उपकरण और बायोमास फीड-स्टॉक से जुड़ी लागत को कम करना शामिल है. बायोमास गैसीकरण के माध्यम से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए समर्थन बढ़ाने की आवश्यकता है.

आर्थिक रूप से सस्ता और पर्यावरणीय दोनों पहलुओं के आधार पर बायोमास गैसीकरण से हाइड्रोजन का उत्पादन एक बेहतर विकल्प होगा.

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने भारतीय संदर्भ में बायोमास ऊर्जा की क्षमता और महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, कई कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली कुशल बायोमास रूपांतरण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सके.

आर्थिक

1 बजट 2022 में कृषि के लिए महत्वपूर्ण उपाय

हाल ही में प्रस्तुत बजट में कृषि के उच्च मूल्य वर्द्धन और फसल विविधीकरण से संबद्ध गतिविधियों पर अत्यधिक जोर दिया गया है.

बजट में कृषि के लिए उपाय : फसल विविधीकरण, आधुनिकीकरण

- फसल विविधीकरण :- बजट में कम उगाई जाने वाली फसलों जैसे-तिलहन और मोटे अनाज पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है.

a. भारत वार्षिक रूप से 70,000 करोड़ रुपये के खाद्य तेल का आयात करता रहा है.

b. घरेलू तिलहन और ताड़ जैसे अन्य स्रोतों को प्रोत्साहित कर भारत खाद्य तेल के उत्पादन में आयात निर्भरता को कम कर सकता है.

- समृद्धि के लिए दालें :- दलहन भी जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी फसल हैं, जो पोषण के साथ ही जलवायु नियंत्रण कार्यवाही में भारत के प्रयासों को मजबूती से आगे बढ़ाती है.

a. मोटे अनाज और दलहन फसल कटाई के बाद मूल्यवर्धन करने, घरेलू खपत बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण के लिए प्रयुक्त होंगी.

b. इन फसलों के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए 'फसल विविधीकरण' को बढ़ावा देना स्मार्ट कृषि का अभिन्न अंग है.

- जलवायु स्मार्ट कृषि : बजट में स्मार्ट कृषि के लिए डिजिटल तकनीक को उत्पादन तकनीक के पूरक के रूप में आगे बढ़ाया गया है.

1. डिजिटल तकनीक के अंतर्गत 'किसान ड्रोन' सहित मूल्य श्रृंखला के विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है.
2. इनमें उत्पादन योजना, संसाधन उपयोग दक्षता, मानसून और बाजार से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को शामिल किया गया है.
3. भूमि अभिलेखों का डिजिटाइजेशन और डिजिटल हाई-टेक सेवायें प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है.

- **किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) क्रांति :-**

1. एफपीओ द्वारा कृषि-उत्पादों के एकत्रीकरण से विपणन योग्य अधिशेष की मात्रा बढ़ाकर बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सकता है.
2. नाबार्ड के माध्यम से सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) मॉडल के तहत जुटाई जाने वाली मिश्रित पूंजी, बजटीय आवंटन को मजबूती प्रदान करगी.

- **कृषि और ग्रामीण उद्यमिता:-** कृषि उपज मूल्य श्रृंखला से जुड़े कृषि और ग्रामीण उद्यमशीलता स्टार्ट-अप के वित्तपोषण का स्पिन-ऑफ प्रभाव, कृषि के पदचिह्नों को द्वितीयक कृषि में विस्तारित करेगा.

बजट में सुझाए गए समाधान : क्रेडिट, संधारणीय, डीकार्बोनाईजेशन

क्रेडिट समर्थन :-

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए उच्च आवंटन द्वारा पर्याप्त समर्थन (125 प्रतिशत से अधिक की बढ़त).
- क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) सहित एमएसएमई क्षेत्र के पक्ष में किए गए विभिन्न पहल, क्रेडिट आकार को 200,000 करोड़ रूपए तक विस्तारित करते हैं.
- स्थिरता पर ध्यान:- द्वितीयक कृषि और जैव-अर्थव्यवस्था की परिणामी वृद्धि, रोजगार और आय सृजित करने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल विकासात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेगी.

कृषि क्षेत्र को कार्बनमुक्त करना :-

1. ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए सौर ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था, कृषि वानिकी और निजी वानिकी को बढ़ावा देने के प्रयास किये गये हैं.
2. ताप विद्युत केन्द्रों (थर्मल पावर प्लांटों) में यदि लक्ष्य के अनुरूप 5-7 प्रतिशत बायोमास जलाया जाता है तो कार्बन डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित होंगे.

नदियों को जोड़ना :- केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के साथ ही पांच अन्य नदी जोड़ो परियोजनाओं के वित्तपोषण की प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है. जब भी इन योजनाओं पर विभिन्न राज्यों की आम सहमति बन जाएगी तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों को योजना का लाभ मिलेगा. यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चलाये जा रहे एआईबीपी कार्यक्रम के तहत देश में उपयोग योग्य जल के संचयन के उद्देश्य को बल देगा.

निष्कर्ष :-

सरकार का ध्यान विभिन्न मंत्रालयों की नीतियों और कार्यक्रमों को समेट कर बजटीय और गैर-बजटीय वित्तीय स्रोतों के एकत्रीकरण करके उच्च पूंजी निवेश करने पर है. उदाहरण के लिए, रेलवे का इरादा लघु कृषि उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना है. यह एक सामंजस्यपूर्ण अंतर-मंत्रालयी दृष्टिकोण है जो पूंजी उपयोग दक्षता को बढ़ाएगा, जिससे कृषि विकास दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा है. बजट के माध्यम से सरकार का दृष्टिकोण कृषि क्षेत्र को रोजगार सृजन, आय सृजन और संधारणीय उद्यम प्रणाली के रूप में परिवर्तित करने के साथ ही खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का है.

2 ई-रूपी

चर्चा में क्यों :-

ई-रूपी वाउचर कैप को 1 लाख रुपए तक बढ़ाने से ऑफलाइन मोड में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा. विशेषज्ञों ने कहा इससे बैंक खाता होने के बिना भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा मिलेगी.

E-RUPI क्या है?

ई-रुपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी को अपने फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है. यह एक प्री-पेड वाउचर है, जिसे कोई व्यक्ति किसी भी भुगतान केंद्र पर जाकर रिडीम/भुगतान कर सकता है (जो केंद्र इसे स्वीकार करता हो।) ई-रुपी, भुगतान का एक बार का संपर्क रहित कैशलेस वाउचर-आधारित तरीका है जो उपयोगकर्ताओं को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने में मदद करता है. इसे वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया है.

ई-रूपी कैसे काम करेगा?

यह अनिवार्य रूप से एक प्रीपेड उपहार-वाउचर की तरह होगा जो किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना विशिष्ट स्वीकार केंद्रों पर भुगतान के लिए योग्य होगा.

- ई-रूपी, सेवाओं के प्रायोजकों को लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल तरीके से जोड़ेगा.

E-RUPI के फायदे :-

- ई-रूपी के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होने की आवश्यकता नहीं होती है, जो अन्य डिजिटल भुगतान प्रपत्रों की तुलना में एक प्रमुख विशिष्ट विशेषता है. यह एक आसान, संपर्क रहित दो-चरणीय भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित करता है जिसके लिए व्यक्तिगत विवरण साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है.
- इससे एक और लाभ यह है कि ई-रूपी साधारण फोन पर भी काम करने योग्य है, और इसलिए इसका उपयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हैं.
- यह एक प्रीपेड वाउचर होने के नाते, ई-रूपी सेवा प्रदाता को वास्तविक समय के भुगतान का आश्वासन देगा.
- ई-रूपी के माध्यम से भुगतान में, अन्य डिजिटल भुगतान प्रणाली की तुलना में इंटरनेट कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है.
- चूंकि, वाउचर को भौतिक रूप में जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह कुछ लागत की बचत भी करेगा।

E-RUPI की क्षमता :-

- यह लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभों की बेहतर डिजिटल डिलीवरी सुनिश्चित करेगा. इसलिए, यह अंतिम छोर के नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा, जिससे वित्तीय सहायता की व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी.
- सरकारों के लिए ई-रूपी का प्रमुख लाभ यह है कि बैंक रहित और साधारण फोन उपयोगकर्ताओं के बीच नये प्रकार की वित्तीय लेन देन की पहुच बनाई जा सकती है, जो प्राप्तकर्ता के बैंक खाते या केवाईसी की आवश्यकता के बिना भुगतान की अनुमति देता है.
- साथ ही यह निजी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को व्यवसाय-से-व्यवसाय लेनदेन की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रयोग के अलावा कर्मचारी लाभ प्रदान करने में भी भूमिका निभाएगा.
- यह भुगतान प्लेटफॉर्म प्रकृति से प्रीपेड होगा, जिसके लिए सेवा प्रदाता को भुगतान करने के लिए किसी भी प्रकार के मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अलावा इस प्लेटफार्म का उपयोग उन योजनाओं (जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मातृ और बाल कल्याण योजना, पूर्व टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, दवा और नैदानिक जैसी दवाओं और पोषण संबंधी सब्सडी आदि) के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है

आगे की राह :-

- ई-रूपी प्लेटफार्म वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार के नीतिगत उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य भारत भर में सेवा रहित (अंडर-सर्व्ड) क्षेत्रों, बैंक सेवाओं की पहुच से दूर रही आबादी और गैर-स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं तक पहुच बनाने के लिए आधारभूत संरचना स्थापित करना है.
- यह देखते हुए कि ई-रूपी के प्रयोग हेतु लाभार्थियों को बैंक खाता या मोबाइल एप्लिकेशन (अन्य डिजिटल भुगतान उपकरणों की तुलना में) की आवश्यकता नहीं है (न ही उन्हें स्मार्ट फोन रखने की आवश्यकता होती है), ई-रूपी मौजूदा प्री-पेड भुगतान उपकरणों की तुलना में भारत के ग्रामीण और दूरदराज के हिस्सों में उपयोग हेतु तेजी से स्वीकारा जा सकता है.
- ई-रूपी वाउचर का उपयोग वर्तमान में बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा है. विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सक्रिय रूप से अन्य उपयोग के मामलों में भी विचार किए जा रहे हैं. इसके द्वारा लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की आपूर्ति अधिक कुशलता से हो सकेगी.
- हालांकि, जैसे जैसे यह समाधान अधिक विकसित होगा, एनपीसीआई और इस पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि ई-आरयूपीआई का समर्थन करने वाला साइबर सुरक्षा ढांचा मजबूत रहे (उदाहरण के लिए, फिशिंग हमलों को रोकने के लिए) और ई-वाउचर केवल एक बार भुनाने योग्य ही रहे.

1. पी.आर. श्रीजेश को 'वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर' के लिए चुना गया

भारतीय हॉकी गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश को प्रतिष्ठित 'वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021' के लिए चुना गया है. यह पुरस्कार पाने वाले वह दूसरे भारतीय बन गए हैं. इससे पहले रानी रामपाल को 2019 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था. पी.आर. श्रीजेश के नाम कि सिफारिश अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने की थी. पी.आर. श्रीजेश के अलावा इस पुरस्कार के अन्य दावेदार स्पेन के अल्बर्टो गिन्स लोपेज और इटली के वुशु खिलाड़ी मिशेल जिओर्डानो थे. पी.आर. श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के पूर्व हॉकी कप्तान और टोक्यो ओलंपिक-कांस्य पदक विजेता टीम का हिस्सा थे. उन्होंने 244 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है.

2. भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में

मध्य प्रदेश के लम्हेटा गांव में (जबलपुर जिले में) नर्मदा नदी के तट पर देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा. इस पार्क की स्थापना के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से मंजूरी मिल गई है. इस परियोजना की अनुमानित लागत 35 करोड़ आएगी और इसका निर्माण पांच एकड़ भूमि में किया जाएगा. खास बात ये है कि यह साइट पहले से ही प्राकृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को की भू-विरासत की अस्थायी सूची में है. बता दें कि 1828 में यंही से ब्रिटिश सैन्य अधिकारी विलियम स्लीमैन ने लैमेटा बेड से डायनासोर का पहला जीवाश्म एकत्र किया था. इस जियोलॉजिकल पार्क के साथ-साथ जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में ही 15.20 करोड़ रुपये की लागत से एक विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा.

3. चंद्रयान-३ को अगस्त 2022 में लॉन्च होगा

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया है कि चंद्रयान-3 अगस्त 2022 में लॉन्च होगा. डॉ जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि जनवरी से दिसंबर 2022 के दौरान 19 मिशनों की योजना बनाई गई है. इनमें 08 लॉन्च व्हीकल मिशन, 07 स्पेसक्राफ्ट मिशन और 04 टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर मिशन शामिल हैं. इसरो द्वारा पिछले वर्ष में प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की सूची नीचे दी गई है.

पिछले वर्ष लॉन्च किए गए उपग्रह	
उपग्रह का नाम	प्रक्षेपण तिथि/प्रक्षेपण माह
ईओएस-03	अगस्त, 2021
अमेजोनिया-1	फरवरी 28, 2021
सतीश धवन सैट (एसडीसैट)	फरवरी 28, 2021
यूनिटीसैट	फरवरी 28, 2021

चंद्रयान-2 के विषय में :-

इसे 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी मार्क **III M 1** द्वारा लॉन्च किया गया था. इसके लैंडर (विक्रम), रोवर (प्रज्ञान) और ऑर्बिटर को भारत में विकसित किया गया था. 7 सितंबर 2019 को, इसरो का रोवर ले जाने वाले विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था.

4. 2021 में अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार

2021 में, चीन को पीछे छोड़ कर एक बार फिर संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है. 2021 में, अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 112.3 बिलियन डॉलर हो गया. बता दें कि अमेरिका 2019 में 90.1 बिलियन डॉलर के व्यापार मूल्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, लेकिन 2020 में महामारी के व्यवधान के कारण यह गिरकर 76 बिलियन डॉलर हो गया. भारत द्वारा मुख्य रूप से निर्यात कि जाने वाली वस्तुएं है:- फार्मास्युटिकल उत्पाद, मोती, कीमती पत्थर, धातु और कपड़ा. चीन से भारत का आयात पिछले साल की तुलना में 2021 में 49 फीसदी बढ़ा है. वहीं भारत से चीन को निर्यात भी 2021 में बढ़कर 22.9 अरब डॉलर हो गया. गौर करने वाली बात है कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2021 में बढ़कर 64.5 अरब डॉलर हो गया है. यूएई, सऊदी अरब, स्विटजरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया भारत के शीर्ष दस व्यापारिक साझेदारों में शामिल हैं.

5. ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में तीन शहरी खेल शामिल

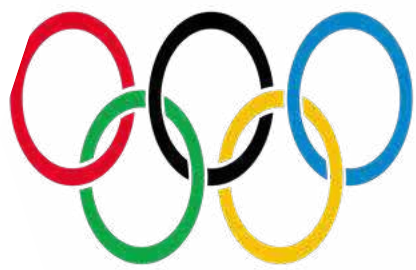

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइम्बिंग खेलों को लॉस एंजिल्स में आयोजित होने वाले 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शामिल किया है. वहीं भारोत्तोलन, आधुनिक पेंटाथलॉन और मुक्केबाजी को अभी शामिल किया जाना बाकी है. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वर्ष लक्ष्यों को पूरा करने पर आईओसी बोर्ड द्वारा उन्हें अगले साल जोड़ा जा सकता है. बता दें कि पेरिस आयोजकों के अनुरोध पर, ब्रेकडांसिंग 2024 के ओलंपिक का हिस्सा होगा.

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति :-

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक गैर-सरकारी खेल संगठन है. यह आधुनिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करता है. इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है. इसकी स्थापना वर्ष 1894 में हुई थी.

6. अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला ओईसीएम साइट होगा

विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर, गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला "अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय" (**OECM**) साइट घोषित किया गया है. ओईसीएम का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) द्वारा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो संरक्षित नहीं हैं लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं. ओईसीएम टैग उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता के प्रभावी स्व-स्थानिक संरक्षण को प्राप्त कर रहे हैं. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने 2020 में आईयूसीएन को अरावली जैव विविधता पार्क को ओईसीएम साइट घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था.

अरावली जैव विविधता पार्क :-

यह 390 एकड़ में 300 देशी पौधों और 101,000 पेड़ों के साथ फैला हुआ है और पक्षियों की कई प्रजातियों का घर है. पारिस्थितिकीविदों और जीवविज्ञानी की मदद से इसे एक परित्यक्त खदान स्थल से शहर के जंगल के रूप में बदला गया है. इसमें दिल्ली-एनसीआर के लिए लगभग 7.07% ऑक्सीजन की आवश्यकता की आपूर्ति करने की क्षमता है. अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसे दिल्ली-एनसीआर का 'ग्रीन लंग्स' माना जाता है.

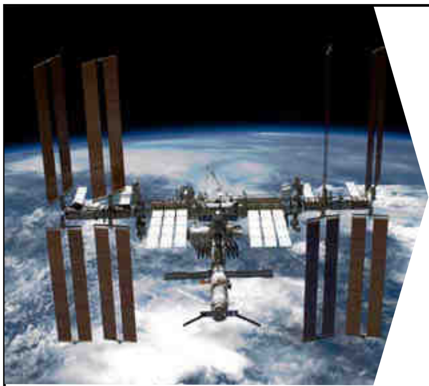

7. 2031 तक बंद होगा नासा का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन

हाल में ही नासा ने घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) का संचालन 2031 में बंद कर देगा. यह कक्षा से बाहर निकलकर और दक्षिण प्रशांत महासागर के पानी में गिर जाएगा. बता दें कि करीब दो दशकों से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन लगभग आठ किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का विचार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने दिया था. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला भाग 1998 में एक रूसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था. इसके बाद 2 नवंबर, 2000 को पहला दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा था. तब से अब तक 19 विभिन्न देशों के 200 से अधिक अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जा चुके हैं. अपने स्थापना के समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का जीवन काल लगभग 15 वर्षों के लिए था लेकिन 2014 में इसके कार्यकाल को और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था.

8. इस वर्ष 'सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी' का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला

उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 की 'सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी' घोषित किया गया है. इस वर्ष उत्तर प्रदेश की झांकी 'एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम' की थीम पर आधारित थी. वहीं कर्नाटक की झांकी को दूसरा स्थान मिला है जो 'पारंपरिक हस्तशिल्प का पालना' थीम पर आधारित थी. लोकप्रिय पसंद श्रेणी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है. शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी ने संयुक्त रूप से केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (सीपीडब्ल्यूडी) की झांकी और वंदे भारतम नृत्य समूह को विशेष पुरस्कार श्रेणी के लिए चुना गया. भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सीएपीएफ/अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है.

9. "भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना" पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन संपन्न

15 और 16 फरवरी 2022 को, संस्कृति मंत्रालय द्वारा "भारत में संग्रहालयों की पुनक. ल्पना" पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया. इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अपने गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को सब तक पहुचना था. वैश्विक शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के संग्रहालय के अग्रणी दिग्गजों, क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया. यह शिखर सम्मेलन ब्लूमबर्ग के सहयोग से आयोजित किया गया. संस्कृति मंत्री श्री जी.किशन रेड्डी ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया. यह शिखर सम्मेलन ऑनलाइन रूप से आयोजित किया गया. सम्मेलन में चार प्रमुख विषय शामिल किये गए थे :

1. वास्तुकला व कार्यात्मक जरूरतें
2. प्रबंध
3. संग्रह (क्यूरेशन और संरक्षण प्रथाओं सहित)
4. शिक्षा व दर्शकों की भागीदारी

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

- राष्ट्रीय जलमार्ग 1 खुल गया और 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न के साथ पहला मालवाहक जहाज 'एमवी लाल बहादुर शास्त्री' पटना से रवाना हुआ.

- 1000 क्रिकेट वनडे खेलने वाला भारत पहला देश बना.

- दिनेश प्रसाद सकलानी होंगे एनसीईआरटी के नए निदेशक.

- ओडिसी शास्त्रीय गायक पंडित दामोदर होता का निधन हो गया. वे ओडिसी शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक थे.

- शांतिश्री पंडित जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त.

- 70 वर्षों तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पहली ब्रिटिश सम्राट बनीं.

- गुलमर्ग में खोला गया दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे.

- खेल लेखक नवदीप सिंह गिल ने 'गोल्डन बॉय नी रज चोपड़ा' के नाम से नीरज चोपड़ा पर एक किताब लिखी.

- आरपीएफ (रेलवे पुलिस फोर्स) ने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान "ऑपरेशन आहट" प्रारम्भ किया है.

- भारत सेल्सफोर्स वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक, 2022 में शीर्ष पर है. ब्राजील और थाईलैंड क्रमश: 53 और 48 के स्कोर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं.

- चीन ने एएफसी महिला एशियाई कप 2022 जीता. चीन ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में एएफसी महिला एशियाई कप के फाइनल में कोरिया गणराज्य को 3-2 से हराया. चीन ने नौवीं बार एएफसी महिला एशियाई कप का खिताब जीता.

- पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनीं जारा रदरफोर्ड.

- भारत की 'राइटिंग विद फायर' को डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है. इस डॉक्यूमेंट्री निर्देशन और निर्माण रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष ने किया है.

- कंचोथ महोत्सव जम्मू-कश्मीर में मनाया गया.

- भारत श्रीलंका को उसके आधार संस्करण शुरू करने में सहायता करेगा.

- सफेद गाल वाला मैकाक अरुणाचल प्रदेश में देखा गया.

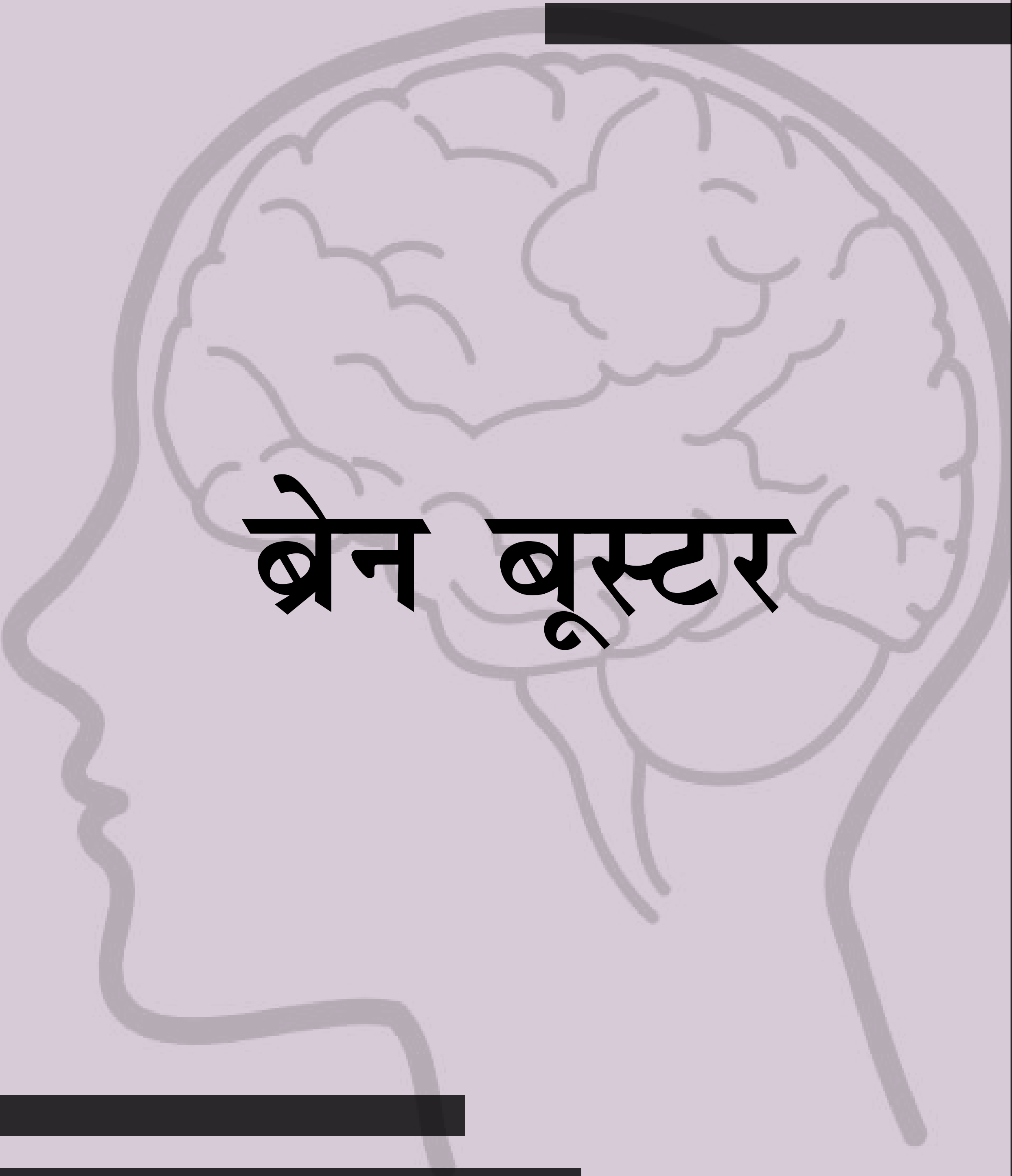

ब्रेन बूस्टर

अंतरराष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में ब्रह्मोस

1. खबरों में क्यों:

28 जनवरी को, फिलीपींस ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी-शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह मिसाइल के लिए पहला निर्यात ऑर्डर है.

2. सौदे के बारे में

- फिलीपींस के साथ हुए अनुबंध के अंतर्गत तीन ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी की डिलीवरी, ऑपरेटरों और अनुरक्षकों के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ आवश्यक एकीकृत रसद समर्थन (ILS) पैकेज शामिल हैं.
- फिलीपींस मरीन की तटीय रक्षा रेजिमेंट, जो नौसेना के अधीन है, मिसाइल प्रणाली का प्राथमिक नियोक्ता होगी.
- सौदे की लागत $374.96 मिलियन होगी.

3. ब्रह्मोस एयरोस्पेस के बारे में

- ब्रह्मोस एयरोस्पेस का गठन **DRDO** भारत और **NPO Mashinostroeniya,** रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया था.
- ब्रह्मोस नाम दो नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा के नाम से बना है

4. रेंज

- मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) के नियमो के अनुसार ब्रह्मोस की सीमा मूल रूप से 290 किलोमीटर तक सीमित थी, जिसमें रूस एक हस्ताक्षरकर्ता था.
- जून 2016 में क्लब में भारत के प्रवेश के बाद, इस सीमा को पहले 450 किलोमीटर और बाद में 600 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना की घोषणा की गई.
- 450 किलोमीटर तक विस्तारित रेंज वाले ब्रह्मोस का परीक्षण कई बार किया गया है.

5. प्लेटफॉर्म

I. जहाज आधारित हथियार प्रणाली

- इसका नौसैनिक विन्यास, हथियार को समुद्र या भूमि लक्ष्यों के खिलाफ स्टैंड-ऑफ रेंज से चलती या स्थिर समुद्री प्लेटफॉर्म से लंबवत या झुकाव मोड में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है.
- ब्रह्मोस को ष्प्राइम स्ट्राइक वेपनष के रूप में डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट सहित भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन सर्फेस कॉम्बैट प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है.

II. भूमि आधारित हथियार प्रणाली

- भूमि आधारित हथियार प्रणाली में 4 से 6 मोबाइल ऑटोनॉमस लांचर होते हैं.
- प्रणाली जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से लैस है.

III. एयर लॉन्च हथियार प्रणाली

- हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल (एएल.सीएम) में समुद्र और जमीन के लक्ष्यों के खिलाफ सटीक हमले की क्षमता है।
- **Su-30MKI** में लगने वाला सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मोस एएलसीएम है.

IV. पनडुब्बी लॉन्च संस्करण

- ब्रह्मोस मिसाइल पनडुब्बी से 40-50 मीटर की गहराई से लॉन्च की जा सकती है.

6. अन्य इच्छुक ग्राहक

- फिलीपींस सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों का सौदा लंबे समय से लंबित है जो निकट भविष्य में प्रगति देख सकता है.
- अगला ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौदा शीघ्र ही होने की संभावना है क्योंकि इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ बातचीत अंतिम चरणों में है.
- कथित तौर पर पश्चिम एशिया के देशों से भी ब्रह्मोस के लिए रुचि है.

7. सुर्खियों में अन्य उत्पाद

- भारत द्वारा दिए गये 100 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) के तहत सात ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों और आठ डोर्नियर डीओ228 विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को फिलीपींस के तटरक्षक बल के साथ वार्ता हो रही है.
- भारतीय कंपनियों के लिए फिलीपींस में समुद्री क्षेत्र और जहाज निर्माण अत्यंत संभ‌ावित क्षेत्र है.
- संभवत: भारत का एलसीए तेजस, मलेशिया की वायु सेना की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा.

8. सरकार का लक्ष्य

- 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात सहित 25 अरब डॉलर या 1,75,000 करोड़ रुपये के रक्षा विनिर्माण कारोबार का लक्ष्य रखा गया है.

- भारत ने बिक्री के लिए सैन्य हार्डवेयर की एक श्रृंखला रखी है जिसमें विभिन्न मिसाइल सिस्टम, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए), हेलीकॉप्टर, युद्धपोत और गश्ती जहाज, आर्टिलरी गन, टैंक, रडार, सैन्य वाहन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के अलावा अन्य हथियार सिस्टम शामिल हैं.

9. सरकार द्वारा उठाये गये कदम

- सरलीकृत रक्षा औद्योगिक लाइसेंसिंग.
- निर्यात नियंत्रण में ढील.
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करना.
- रक्षा उत्पादों के आयात के लिए कस्टमर देशों को ऋण सहायता (एलओसी) का विस्तार करना.
- रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों में रक्षा संलग्नकों को सशक्त बनाना.
- प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों के निर्यात के लिए तेजी से अनुमोदन प्रदान करने के लिए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की एक समिति का गठन किया गया है.

भारत - श्रीलंका संबंध

1. खबरों में क्यों:

श्रीलंका (SL) के विदेश मंत्री (FM) जीएल पेइरिस ने 7 फरवरी, 2022 को नई दिल्ली में अपने समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात की. SL FM ने कहा हाल के हफ्तों में कोलंबो को नई दिल्ली की आर्थिक सहायता ने महतवपूर्ण भूमिका निभाई है

2. भारत द्वारा मदद

- जनवरी 2022 से भारत, गंभीर डॉलर संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है.
- SL द्वारा लोन डिफॉल्ट का डर तथा आयात-निर्भर देश में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी थी.
- 2022 की शुरुआत से, भारत ने 1.4 अरब डॉलर की राहत प्रदान की है जो $400 मुद्रा स्वैप, $500 ऋण आस्थगन और ईंधन आयात के लिए $500 लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में है.
- श्रीलंका आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत से $1 बिलियन की सहायता के लिए बातचीत कर रहा है.

3. राजनीतिक संबंध

- दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को नियमित अंतराल पर यात्राओं के उच्च स्तरीय आदान-प्रदान द्वारा चिह्नित किया गया है.
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2020 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की.
- विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 5-7 जनवरी 2021 को श्रीलंका का दौरा किया, 2021 में विदेश मंत्री की यह पहली विदेश यात्रा थी.

4. वाणिज्यिक संबंध

- 2000 में भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (आईएसएफटीए) ने दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
- आर्थिक संबंधों में बुनियादी ढांचे, संपर्क, परिवहन, आवास, स्वास्थ्य, आजीविका और पुनर्वास, शिक्षा और औद्योगिक विकास जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं.

5. विकास सहयोग

- लगभग 570 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान के साथ, भारत सरकार द्वारा श्रीलंका के विकास हेतु समग्र प्रतिबद्धता 3.5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की है.

6. लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) के तहत परियोजनाएं

- पिछले 15 वर्षों में भारत के एक्सिम बैंक द्वारा श्रीलंका को 11 एलओसी प्रदान किए गए हैं.
- इन एलओसी के तहत जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाएं निष्पादित की गयी हैं/जा रही हैं उनमें शामिल हैं: रेलवे, परिवहन, कनेक्टिविटी, रक्षा, सौर.

7. सांस्कृतिक संबंध

- भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और भाषाई संबंधों की साझा विरासत है जो 2,500 वर्ष से अधिक पुरानी है.
- समसामयिक समय में, दोनों सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग समझौता दोनों देशों के बीच समय-समय पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आधार बनता है.

8. श्रीलंका भर में विशेष प्रार्थनाए

- मई-जून 2021 में, COVID-19 महामारी के मद्देनजर भारत के लोगों की भलाई के लिए श्रीलंका भर में विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा विशेष प्रार्थनाओ की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी.

9. स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (एसवीसीसी)

- स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (एसवीसीसी), भारतीय उच्चायोग, कोलंबो की सांस्कृतिक शाखा है.
- यह 1998 में अपनी स्थापना के बाद से इन संबंधों को मजबूत करने और भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच संपर्कों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
- एसवीसीसी भरतनाट्यम, कथक, हिंदुस्तानी और कर्नाटक गायन, वायलिन, सितार, तबला, हिंदी और योग में कक्षाओं का आयोजन कर सक्रिय रूप से भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है.

10. भारत-श्रीलंका फाउंडेशन

- भारत-श्रीलंका फाउंडेशन, जिसे दिसंबर 1998 में एक अंतर सरकारी पहल के रूप में स्थापित किया गया था, का उद्देश्य नागरिक समाज के आदान-प्रदान के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना और दोनों देशों की युवा पीढ़ियों के बीच संपर्क बढ़ाना है.

11. पर्यटन:

- पर्यटन भी भारत और श्रीलंका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है.
- भारत सरकार ने 14 अप्रैल 2015 को औपचारिक रूप से श्रीलंकाई पर्यटकों के लिए ई-पर्यटक वीजा (ईटीवी) योजना शुरू की.
- श्रीलंका का पर्यटन उद्योग, जो ईस्टर संडे के हमलों से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, को भारतीय पर्यटकों के आगमन से बढ़ावा मिला.
- 24 जुलाई 2019 को श्रीलंका ने भारत को आगमन पर नि:शुल्क वीजा योजना में शामिल किया और 1 अगस्त 2019 को इस योजना की शुरुआत की.

12. मछुआरों का मुद्दा

- दोनों देशों ने अनजाने में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करने वाले दोनों पक्षों के वास्तविक मछुआरों के मुद्दे से निपटने के लिए कुछ व्यावहारिक व्यवस्थाओं पर सहमति व्यक्त की है.

भारत में डिजिटल मुद्रा

1. खबरों में क्यों:

- 2022-23 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) की शुरुआत की घोषणा की और कहा कि डिजिटल रुपया, डिजिटल अर्थव्यवस्था को 'बड़ा बढ़ावा' देगा.

2. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में

- सीबीडीसी उस नकदी से अलग नहीं है जो हम अपने वॉलेट में रखते हैं, सिवाय इसके कि यह एक डिजिटल रूप में मौजूद है.
- सीबीडीसी को एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाएगा जिसकी निगरानी केंद्रीय बैंक करेगा.
- भारत में आरबीआई, डिजिटल रुपये की निगरानी करेगा , हालांकि यह बैंकों को कुछ शक्ति सौंप सकता है.
- ऐसा लगता है कि आरबीआई भौतिक नकदी पर अपनी डिजिटल मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाएगा.
- आरबीआई का डिजिटल रुपया बैंकों में जमा डिमांड डिपॉजिट को सीधे तौर पर रिप्लेस नहीं करेगा.
- बैंकों द्वारा भौतिक नकदी का उपयोग जारी रहेगा, और जो लोग बैंकों से नकदी निकालना चाहते हैं, वे अब भी ऐसा कर सकते हैं.
- वे अपनी बैंक जमा राशि को नए डिजि. टल रुपये में बदलने का विकल्प भी चुन सकते हैं.

3. सीबीडीसी को लाने के कारण

- केंद्रीय बैंकों का दावा है कि डिजिटल मुद्राओं की मांग बढ़ रही है, जिसे वे संतुष्ट करना चाहते हैं.
- वे बिटकॉइन जैसी निजी डिजिटल मुद्राओं के उदय और डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग की ओर इशारा करते हैं.
- केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं को निजी मुद्राओं के विश्वसनीय, संप्रभु-समर्थित विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो अस्थिर और अनियमित हैं.
- केंद्रीय बैंक यह भी मानते हैं कि डिजिटल मुद्रा जारी करने की लागत वास्तविक नकदी के मुद्रण और वितरण की लागत से काफी कम है.
- आरबीआई डिजिटल रुपये का निर्माण और वितरण लगभग शून्य लागत पर कर सकता है क्योंकि डिजिटल रुपये का निर्माण और वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा.
- डिजिटल नकदी की शुरुआत का एक अन्य संभावित कारण भौतिक नकदी के उपयोग को कम करना हो सकता है.
- भौतिक नकदी का पता लगाना कठिन है, इसके विपरीत एक डिजिटल मुद्रा, जिसकी निगरानी आरबीआई करता है, उसे केंद्रीय बैंक द्वारा अधिक आसानी से ट्रैक और नियंत्रित किया जा सकता है.

4. निजी मुद्राओं के लाभ

- निजी मुद्राओं की मांग मुख्य रूप से उन लोगों से आती है जिनका केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी फिएट मुद्राओं से विश्वास खो चुका है.
- उनका तर्क है कि दुनिया भर की सरकारें अपनी-अपनी मुद्राओं को अत्यधिक मात्रा में प्रिंट करके उनका अवमूल्यन कर रही हैं, इस प्रकार कई लोगों को निजी मुद्राओं पर स्विच करने के लिए मजबूर किया गया है जिनकी आपूर्ति डिजाइन द्वारा सीमित है.
- निजी डिजिटल मुद्राओं में स्विच करने के पीछे गोपनीयता की आवश्यकता प्राथमिक कारणों में से एक रही है.

5. दुनिया भर में सीबीडीसी की स्थिति

- संयुक्त राज्य अमेरिका सहित यूरोपीय संघ और चीन सहित कई देश हाल के वर्षों में अपने स्वयं के सीबीडीसी जारी करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रहे हैं.
- अक्टूबर 2020 में बहामास ने दुनिया का पहला CBDC लॉन्च किया.
- फिनलैंड और डेनमार्क सहित कुछ देशों ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा है कि उन्होंने डिजिटल मुद्रा शुरू करने के प्रयासों को रद्द कर दिया है.

6. सीबीडीसी को अपनाने में जोखिम

- विभिन्न केंद्रीय बैंकरों को डर है कि लोग अपने बैंक खातों से पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं क्योंकि केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी डि. जिटल मुद्राएं अधिक लोकप्रिय हो सकती हैं.
- जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेश किया गया डिजिटल वॉलेट सुरक्षित रूप से नकदी जमा कर सकता है, तो लोग अपने बैंक जमा को डिजिटल नकदी में परिवर्तित करना शुरू कर सकते हैं.
- एक कारण जो बैंक खातों से डिजिटल मुद्राओं में पूंजी की किसी भी बड़ी उड़ान को रोक सकती है, वह यह है कि बैंक खाते, डिजिटल मुद्राओं के विपरीत, जमा पर ब्याज प्रदान करते हैं.
- बैंक जमा की निकासी, बैंकों द्वारा बनाए गए ऋणों की राशि को भी प्रभावित कर सकती है.

7. आगे क्या हो सकता है?

- केंद्रीय बैंक सीबीडीसी के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा धारित राशि की सीमा निर्धारित कर सकते हैं. यह बैंकों से जमा की बड़े पै. माने पर निकासी को रोकने में सहायक होगा.
- कुछ केंद्रीय बैंक, जैसे कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक, अपनी डिजिटल मुद्राओं पर नकारात्मक जुर्माना लगा सकते हैं.
- यह लोगों को अपनी डिजिटल मुद्रा खर्च करने के लिए बाध्य करने और नकारात्मक ब्याज दर लगाने वाले बैंकों से जमा की निकासी को हतोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है.
- केंद्रीय बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों में नए पैसे डालने पड़ सकते हैं कि बैंकों की ऋण बनाने की क्षमता डिजिटल मुद्राओं में जमाकर्ताओं की भीड़ से प्रभावित न हो.

क्रिप्टो की पहेली

1. खबरों में क्यों

बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से अर्जित आय पर 30% कर की शुरुआत की. सरकार ने अभी तक क्रिप्टो-मुद्राओं को मान्यता नहीं दी है, परन्तु इस अस्पष्टता ने लोगों को बड़ी संख्या में डिजिटल संपत्ति में व्यापार करने से नहीं रोका है, जिसने स्पष्ट रूप से ऐसे लेनदेन पर कर की घोषणा करने के लिए सरकार को मजबूत कारण दिया है.

2. क्रिप्टोकरेंसी के बारे में

क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जिसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिससे नकली या दोहरा खर्च करना लग.भग असंभव हो जाता है. कई क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित विकेंद्रीकृत नेटवर्क हैं

3. ब्लॉकचेन

- क्रिप्टोकरेंसी की अपील और कार्यक्षमता का केंद्र ब्लॉकचेन तकनीक है.
- ब्लॉकचेन अनिवार्य रूप से कनेक्टेड ब्लॉक्स या ऑनलाइन लेजर का एक सेट है.
- प्रत्येक ब्लॉक में लेनदेन का एक सेट होता है जिसे नेटवर्क के प्रत्येक सदस्य द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया गया है.
- सृजित किए गए प्रत्येक नए ब्लॉक की पुष्टि होने से पहले प्रत्येक नोड द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, जिससे लेनदेन इतिहास बनाना लगभग असंभव हो जाता है.
- ऑनलाइन लेजर की सामग्री पर एक व्यक्तिगत नोड के पूरे नेटवर्क, या कंप्यूटर द्वारा लेजर की एक प्रति बनाए रखने पर सहमति होनी चाहिए.

4. आभासी डिजिटल संपत्तियों से होने वाली आय पर कर लगाना

- बजट में "किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण" से होने वाली आय पर 30% कर का प्रस्ताव किया गया है.
- अधिग्रहण की लागत को छोड़कर, किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- ऐसे स्थानान्तरण से होने वाली हानियों को किसी आय से समायोजित नहीं किया जा सकता है.
- स्रोत पर कर की कटौती 1% की दर से की जाएगी, ताकि लेन-देन विवरण प्राप्त किया जा सके.

5. क्रिप्टोकरेंसी के लिए भारत का दृष्टिकोण

- सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने अतीत में लोगों को क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी निविदा के रूप में मानने के प्रति आगाह किया है.
- चूंकि इस तरह की मुद्राओं का उपयोग करने वाले लेन-देन कर जाल को आसानी से बायपास कर सकते हैं, और इसलिए अवैध लेनदेन के लिए उपयोग किया जा सकता है, दुनिया भर की सरकारों को परेशान कर रहा है.
- भारतीय रिजर्व बैंक ने 2018 में, बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र को सेवाएं प्रदान नहीं करने का निर्देश दिया.
- सर्वोच्च न्यायालय ने इस कदम को असंगत बताते हुए इसे रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि देश में ऐसी मुद्राओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था.
- क्रिप्टोकरेंसी पर एक कानून, जिसे पिछले साल लाया जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आया है.
- इस पर सरकार का दृष्टिकोण एक अंत.र-मंत्रालयी समिति द्वारा 2019 की रिपोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसने सभी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी.
- सुश्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ष्आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों में लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई हैष्
- इन लेनदेनों के परिमाण और आवृत्ति ने एक विशिष्ट कर व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है.

6. कर पर क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थि.तिकी तंत्र का मत

- सभी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी ने कर का स्वागत किया है. उन्होंने इसे एक ऐसे कदम के रूप में लिया जो उनके उद्योग को स्पष्टता और "मुख्यधारा" प्रदान करता है.
- कुछ इसे सरकार द्वारा उद्योग को वैध बनाने के रूप में देखते हैं.

7. क्या क्रिप्टोकरेंसी कानूनी रूप से मान्य हैं

- बजट के बाद मंत्रियों और नौकरशाहों के बयानों से लगता है कि देश में क्रिप्टोकरेंसी की वैधता अभी भी एक ग्रे क्षेत्र है.
- वित्त सचिव ने कहा:" यह एक ग्रे क्षेत्र में हैं. क्रिप्टो को खरीदना और बेचना गैरकानूनी नहीं है."
- केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया, "कल के बजट ने सीधा जवाब दिया है-क्रिप्टो पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा."
- सुश्री सीतारमण ने सुझाव दिया कि प्रतिबंध पर सवाल एक या दूसरे तरीके से तय नहीं किया गया है. वह वैधता के मुद्दे से कर योग.यता के मुद्दे को भी भिन्नता देती दिख रही थी. उन्होंने आगे कहा कि कर लगाना पूरी तरह से उनका विशेषाधिकार है.
- विशेषज्ञों ने बताया है कि कानूनी स्थि.ति, सुश्री सीतारमण की विचार प्रक्रिया के अनुरूप है

- 1980 में आयकर आयुक्त बनाम पियारा सिंह के फैसले को आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम एससी कोठारी के फैसले से उद्धृत किया गया था, जिसमें अदालत ने कहा था कि ष्यदि व्यवसाय अवैध है, तो न ही अर्जित लाभ तथा न ही किए गए नुकसान कानून में लागू करने योग्य होंगे. लेकिन, यह लाभ को कर कानून से बाहर नहीं निकालता है. "

पद्म पुरस्कार

1. खबरों में क्यों:

पद्म पुरस्कारों की घोषणा 25 जनवरी को की गई थी. पुरस्कारों की घोषणा हमेशा गणतंत्र दिवस समारोह से एक दिन पहले की जाती है. राष्ट्रपति भवन में आयोजित औपचारिक समारोहों में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं. COVID19 महामारी के कारण पिछले नवंबर में 2020 और 2021 के पुरस्कार विजेताओं के लिए समारोह आयोजित किए गए थे. इस वर्ष राष्ट्रपति ने 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी.

2. भारत रत्न

- भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है.
- यह मानवीय प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा/उच्चतम प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है.
- इसका स्तर पद्म पुरस्कार से अलग है.
- भारत रत्न की सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती हैं.
- भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं है.
- भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम तीन तक सीमित है.
- सरकार अब तक 45 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान कर चुकी है.

3. पद्म पुरस्कारों के बारे में

- भारत रत्न के बाद, पद्म पुरस्कार देश में दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार हैं और तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं.
- पुरस्कार, शुरू में पद्म विभूषण के रूप में जाना जाता था और फिर पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया था, यह पहली बार 1954 में गठित किया गया था.
- इन्हें बाद में 8 जनवरी, 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री नाम दिया गया.
- पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है.
- पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है.
- पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है.

- जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं. हालांकि, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ काम करने वाले सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं.

4. पुरस्कारों के लिए मान्यता प्राप्त क्षेत्र

यह पुरस्कार विशिष्ट कार्यों को मान्यता देना चाहता है और गतिविधियों/विषयों के सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए दिया जाता है.

- कला (संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, सिनेमा, रंगमंच)
- सामाजिक कार्य (समाज सेवा, धर्मार्थ सेवा, सामुदायिक परियोजनाओं में योगदान)
- सार्वजनिक मामले (कानून, सार्वजनिक जीवन, राजनीति)
- विज्ञान और इंजीनियरिंग (अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, परमाणु विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और इसके संबद्ध विषयों में अनुसंधान और विकास)
- व्यापार और उद्योग (बैंकिंग, आर्थिक गतिविधियां, प्रबंधन, पर्यटन को बढ़ावा देना, व्यवसाय)
- चिकित्सा (चिकित्सा अनुसंधान, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, एलोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा आदि में विशेषज्ञता / विशेषज्ञता)
- साहित्य और शिक्षा (पत्रकारिता, शिक्षण, पुस्तक रचना, साहित्य, कविता, शिक्षा को बढ़ावा देना, साक्षरता को बढ़ावा देना, शिक्षा सुधार)
- सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रशासन आदि में विशिष्टता/उत्कृष्टता)
- खेल (लोकप्रिय खेल, एथलेटिक्स, साहसिक, पर्वतारोहण, खेल को बढ़ावा देना, योग)
- अन्य (उपरोक्त में जो क्षेत्र शामिल नहीं हैं और इसमें भारतीय संस्कृति का प्रचार, मानव अधिकारों का संरक्षण, वन्य जीवन संरक्षण/संरक्षण)

5. पुरस्कार कौन तय करता है?

- पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकनों को पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखा जाता है, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है.
- पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और सदस्यों के रूप में चार से छह प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं.
- समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है.

6. पुरस्कार देना

- पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं. पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण पत्र) और एक पदक प्रदान किया जाता है.
- प्राप्तकर्ताओं को पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे यदि पुरस्कार विजेता चाहें तो किसी भी समारोह/राज्य समारोह आदि के दौरान पहन सकते हैं.
- पुरस्कार विजेताओं के नाम प्रस्तुति समारोह के दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं.

- एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या (मरणोपरांत पुरस्कारों और एनआरआई/विदेशियों/ओसीआई को छोड़कर) 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- पुरस्कार एक शीर्षक के बराबर नहीं है और पुरस्कार विजेताओं के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है.

डॉ यू वी स्वामीनाथ अय्यर

1. डॉ यू वी स्वामीनाथ अय्यर के बारे में

डॉ. उत्तमाधानपुरम वेंकटसुब्बैयर स्वामीना. थ अय्यर, जिन्हें यू.वी. स्वामीनाथ अय्यर, प्रसिद्ध तमिल विद्वानों में से एक थे, जिनका जन्म 19 फरवरी 1855 को तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास उथमधनपुरम में हुआ था. प्रकाशन क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए, उन्हें सम्मानपूर्वक "तमिल तात" कहा जाता है, तमिल साहित्य के दादा. उनके पिता वेंकट सुब्बू अय्यर एक प्रमुख संगीतकार थे.

2. शिक्षा

- डॉ. स्वामीनाथ अय्यर ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने ही शहर में प्राप्त किया.
- अपने 17वें वर्ष में, उन्होंने थिरिसीपुरम सुंदरम पिल्लई से तमिल सीखना शुरू किया, जो तिरुवदुथुराई शैव एथिनम में शिक्षक थे.
- यू.वी. स्वामीनाथ अय्यर ने 5 साल तक तमिल सीखी और बाद में उन्होंने वर्ष 1880 में कुंभकोणम के एक कॉलेज में काम किया और फिर उन्होंने कुछ समय के लिए प्रेसी. डेंसी कॉलेज, मद्रास में काम किया.

3. तमिल साहित्य में योगदान

- शास्त्रीय तमिल साहित्य के कई लंबे समय से भूले हुए कार्यों को प्रकाश में लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था.
- उनके प्रयासों के कारण, बड़ी संख्या में साहित्यिक कृतियाँ जो ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों के रूप में घरो , भंडार कक्ष, बक्से और अलमारी में धूल जमा कर रही थीं, लोगो के सामने आयी.
- तमिल प्रेमियों ने सिलप्पतिकरम, मणिमे. कलाई और पुराणनुरु को बहुत पसंद किया.
- संगम काल के दौरान तमिलों के जीवन को प्रतिबिंबित करने वाले पुराणनुरु ने इस विषय पर विद्वानों के शोध को प्रेरित किया.
- अय्यर ने अपने जीवनकाल में शास्त्रीय तमिल साहित्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर 90 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कीं, और 3,000 से अधिक कागज पांडुलिपियां, ता. ड़-पत्ती पांडुलिपियां और विभिन्न प्रकार के नोट एकत्र किए.
- स्वामीनाथ अय्यर ने छोटी कविताओं, गीतों, पुराणों और भक्ति कार्यों सहित पुस्तकें प्रकाशित कीं.

4. तमिल संगीत में योगदान

- स्वामीनाथ अय्यर ने तमिल संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
- स्वामीनाथ अय्यर द्वारा सिलप्पतिकरम, पट्टुपट्टू और एट्टुथोकाई के प्रकाशन से पूर्व तक , संगीत तमिल शोध में एक ग्रे क्षेत्र था.
- पिछली चार शताब्दियों के दौरान, तमिल संगीत पर किसी भी मूल्यवान जानकारी के अभाव में तमिलनाडु में संगीत के क्षेत्र में तेलुगु और संस्कृत का बोलबाला था.
- स्वामीनाथ अय्यर के प्रकाशनों ने पिछली शताब्दियों में तमिल संगीत की उपस्थिति पर प्रकाश डाला और इस विषय पर गंभीर शोध का मार्ग प्रशस्त किया.
- अपने समय के एक प्रसिद्ध संगीतकार के पुत्र के रूप में, स्वामीनाथ अय्यर ने संगीत के प्रतिपादक और नंदन सरिथिराम के लेखक गोपालकृष्ण भारती से संगीत सीखा.

5. आत्मकथा

- स्वामीनाथ अय्यर ने जनवरी 1940 से मई 1942 तक तमिल साप्ताहिक आनंद विकटन में अपनी आत्मकथा, एन सरिथम प्रकाशित की.
- बाद में इसे 1950 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, यह पुस्तक 762 पृष्ठों की है.
- पुस्तक गांवों के जीवन और समय का एक उत्कृष्ट विवरण है, खासकर तंजावुर जिले में 19वीं शताब्दी के अंत में.
- तमिल सरल है और लोगों पर कई टिप्पणियों के साथ-साथ स्कूली जीवन, मठों में जीवन का वर्णन है.
- यह पुस्तक तमिल में महारत हासिल करने और पांडुलिपियों को बचाने के लिए यू वी स्वामीनाथ अय्यर की अत्यधिक दृढ़ता को भी प्रकट करती है.

6. सम्मान

- रवींद्रनाथ टैगोर 1926 में चेन्नई में स्वा. मीनाथ अय्यर से मिले थे .
- टैगोर ने ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों से प्राचीन शास्त्रीय तमिल साहित्यिक कृतियों को जीवित करने के अय्यर के प्रयासों की प्रशंसा में एक कविता लिखी थी .
- 1906 में मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा अय्यर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि (डी. लिट) प्रदान की गई थी. उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक उपलब्धियों और योगदानों के लिए, उन्हें महामहोपथियाय की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है: "महान शिक्षकों में महान शिक्षक"-
- उसी वर्ष, जब वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी ने मद्रास का दौरा किया, तो एक समारोह का आयोजन किया गया जहां स्वामीनाथ अय्यर को सम्मानित किया गया. अय्यर को 1925 में दक्षिणाथ्य कलानिधि की उपाधि से सम्मानित किया गया था.

- 1932 में, मद्रास विश्वविद्यालय ने तमिल के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के सम्मान में उन्हें मानद पीएचडी से सम्मानित किया.
- भारतीय डाक विभाग ने 18 फरवरी 2006 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया.
- उथमधनपुरम में उनके घर को स्मारक के रूप में बदल दिया गया है.

नुसंतारा

1. खबरों में क्यों:

18 जनवरी को, इंडोनेशिया की संसद ने देश की राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो द्वीप पर बनाए जाने वाले एक नए शहर में स्थानांतरित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी, जिसका नाम नुसंतारा है. जकार्ता की दीर्घकालिक स्थिरता की बढ़ती चिंताओं के बाद निर्णय लिया गया था. इस कदम ने बोर्नियो के वनाच्छादित द्वीप पर पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है.

2. बोर्नियो द्वीप के बारे में

- दक्षिणपूर्व एशियाई द्वीप बोर्नियो, जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, दुनिया के कुछ सबसे विविध वर्षा वनों और दक्षिण पूर्व एशिया के अंतिम अक्षुण्ण वनों का घर है.
- बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है.
- द्वीप की उष्ण कटिबंधीय जलवायु और विविध पारिस्थितिकी-क्षेत्रों ने ऐसे आवास बनाए हैं जिनमें हजारों अनोखी प्रजातियां रहती हैं.
- विशाल नदियाँ पूरे भू-दृश्य में मौजूद हैं, जो द्वीप की जीवन रेखा हैं. ये नदियाँ द्वीप के लोगों के लिए परिवहन और मीठे पानी की जरूरतें पूर्ण करती हैं.
- बोर्नियो और सुमात्रा पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे स्थान हैं जहाँ बाघ, गैंडे, वनमानुष और हाथी एक साथ रहते हैं.
- प्रोबोस्किस मंकी , सन भालू, क्लाउडेड लेपर्ड और फ्लाइंग फॉक्स बैट जैसे अद्भुत जीवों का घर हैं.

3. जकार्ता की कमियां

- अगस्त 2019 में, राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पहली बार घोषणा की कि राजधानी को जावा द्वीप पर स्थित जकार्ता से बोर्नियो द्वीप पर स्थित पूर्वी कालीमंतन में बनने वाले एक नए शहर में स्थानांतरित किया जाएगा.
- शहर भीड़, प्रदूषण, जगह की कमी और तंग सड़कों जैसी कई तरह की शहरी समस्याओं से जूझ रहा है.
- इसके दीर्घकालिक भविष्य के बारे में एक प्रमुख चिंता जकार्ता का धीरे-धीरे डूबना था.
- अध्ययनों ने अनुमान लगाया है कि 2050 तक पूरा शहर डूब सकता है, जबकि बाढ़ एक आवर्ती समस्या है.

4. बिल और योजना

- बिल ने श्री विडोडो द्वारा लिए निर्णय को हरी झंडी दे दी है और राजधानी को पांच चरणों में स्थानांतरित करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है.
- योजना मंत्री सुहार्सो मोनोआर्फा ने संसद को बताया कि पहला चरण, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, इसके अंतर्गत साइट तक पहुंच प्रदान करने के लिए नई सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
- अंतिम चरण 2045 में पूर्ण होगा.
- इस परियोजना पर 30 अरब डॉलर से अधिक की लागत आने का अनुमान है. राष्ट्रपति विडोडो के अनुसार, राजधानी स्थ. ानांतरित करने का व्यापक लक्ष्य, कालीमंतन में अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधि लाना और जकार्ता पर निर्भरता को कम करना था.
- सभी सरकारी कार्यालयों को नुसंतारा स्थ. ानांतरित कर दिया जाएगा.
- यदि वर्तमान राजधानी प्रदूषण और बाढ़ जैसी समस्याओं से पीड़ित है, तो पर्यावरण समूहों ने चिंता व्यक्त की है कि नई परियोजना उन समस्याओं को कालीमंतन में ला सकती है. जबकि कालीमंतन, अपने जंगलों और जैव विविधता के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र है.

5. नाम "नुसंतारा"

- नाम का शाब्दिक अर्थ है "द्वीपसमूह".
- इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है, जिसमें इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में इसके पड़ोसियों सहित पूरे क्षेत्र का जिक्र है.
- योजना मंत्री ने कहा कि नुसंतारा "एक एकता अवधारणा है जो हमारी सभी विविधताओं को समायोजित करती है, चाहे वह नस्ल, भाषा या जातीयता में हो" और नई राजधानी उस आकांक्षा को प्रतिबिंबित करे, ऐसी आशा है.
- नुसंतारा नाम एक हिंदू साम्राज्य माजापहित में मिलता है, जो जावा में स्थित था और 13वीं सदी के अंत से 15वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन करता था. अपने चरम पर, इसका प्रभाव आज के इंडोनेशिया से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था , जिसमें ब्रुनेई, थाईलैंड और फिलीपींस के कुछ हिस्से शामिल हैं.
- यद्यपि आधिकारिक व्याख्या यह है कि यह विविधता को दर्शाता है, इस बात को लेकर बेचैनी रही है कि 80 सुझावों की सूची में से नाम क्यों चुना गया, जो न केवल इंडोनेशिया को बल्कि पूरे क्षेत्र को संदर्भित करता है.

6. देशों द्वारा राजधानियों का स्थानांतरण

- देशो ने विभिन्न कारणों से राजधानियों को स्थानांतरित किया है, इन कारणों में मौसम और सेना से संबंधित कारणों से लेकर गर्व परियोजनाओं और न्यायपूर्ण राजनीति तक कारण शामिल हैं .
- 1997 में, कजाखस्तान ने अपनी राजधानी को अल्माटी से एक नियोजित शहर अस्ताना में स्थानांतरित कर दिया
- लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, नूरसुल्तान नज. रबायेव को श्रद्धांजलि स्वरुप अस्ताना का नाम बदलकर 2019 में नूर-सुल्तान कर दिया गया.
- 2005 में म्यांमार ने अपनी राजधानी को यांगून से दूसरे नियोजित शहर, नायपीडॉ में स्थानांतरित कर दिया. सामरिक कारणों को सैन्य शासन के निर्णय के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण के रूप में उद्धृत किया गया था.

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न

1. ताजे भौम जल का च्भ्ए वायु प्रभावित होने पर थोड़ा घट जाता है, क्योंकि

(a) वायु से कार्बनडाईऑक्साइड जल में घुल जाती है.

(b) वायु से ऑक्सीजन जल में घुल जाती है.

(c) भौमजल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निकल जाती है.

(d) भौमजल में घुलित ऑक्सीजन वायु में निकल जाती है.

2. वातावरण के प्रधान गैसों का उनके घनफल संबंधी अनुपात के संबंध में घटते क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए:

1. आर्गन
2. कार्बनडाई ऑक्साइड
3. नाइट्रोजन
4. ऑक्सीजन

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए.

(a) 1 – 2 – 4 – 3

(b) 4 – 3 – 2 – 1

(c) 3 – 4 – 1 – 2

(d) 3 – 4 – 2 – 1

3. निम्नलिखित में से कौन सा एक रसोई संबंधी व्यवहार पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से लाभदायक समझा जाता है?

(a) खाना पकाते समय सेम तथा मसूर में बेकिंग सोडा को अतिरिक्त मिलाना

(b) भोजन पकाने के आधे घंटे पूर्व सब्जियों का छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना

(c) इडली या ढोकला को बनाने की पूर्व तैयारी में उसके भागों/अंशों को उत्तेजित करना.

(d) पकाने के पूर्व चावल को जल की अच्छी मात्रा के साथ धोना

4. निम्नलिखित में से किसका प्रति निधित्व किसी ताजे जल वाले पारितंत्र में जैविक ऑक्सीजन मांग (वी.ओ.डी.) को कम कर सकता है?

(a) मल की बड़ी मात्रा

(b) व्यापक जैवभार का संचय तथा पृथक्करण

(c) कार्बनिक पदार्थ प्रदूषण का बढ़ना

(d) निम्नतापमान तथा निम्न पादप जैवभार संचय

5. जीवाश्म की आयु, कार्बन के दो समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर, मालूम की जा सकती है। वे सम स्थानिक कौन-से हैं?

(a) C-12 और C-13

(b) C-13 और C-14

(c) C-12 और C-14

(d) C-12 और कार्बन ब्लैक

6. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश रासायनिक कोहरे की रचना के लिए जरूरी नहीं है?

(a) कार्बन मोनोऑक्साइड

(b) नाइट्रोजन के ऑक्साइड

(c) ऑक्सीजन

(d) सूर्य का प्रकाश

7. निम्नलिखित अल्पकालिक शरीर संबंधी परिवर्तनों पर विचार कीजिए:

1. रक्त दाब में वृद्धि
2. भीतरीकपालीय दाब में कमी
3. आंख की पुतली का विस्तार
4. श्वसन में वृद्धि

उपर्युक्त में से कौन से परिवर्तन खुले ध्वनि प्रदूषण में रहने वाले व्यक्ति में अल्पकालिक उपस्थित होते हैं?

(a) 1, 2, 3 और 4

(b) केवल 3 और 4

(c) केवल 1 और 4

(d) केवल 1 और 2

8. कार्बन क्रेडिट सी.ई.आर. (प्रमाणित उत्सर्जन कटौती) पद की इकाई में जारी किया जाता है. प्रत्येक सी.ई.आर. बराबर है.

(a) CO_2 के एक किलो कटौती के

(b) CO_2 के 10 किलो कटौती के

(c) CO_2 के 100 किलो कटौती के

(d) CO_2 के 1 टन कटौती के

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. तैलीय दुर्घटना शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण की तुलना में उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में तीव्र वाष्पोत्सर्जन दर के कारण कम पर्यावरणीय तथा कम खतरनाक होता है.

2. उष्णकटिबंधीय दशा में तटीय वनस्पतियों की वृद्धि तैलीय प्रदूषण के द्वारा प्रभावित नहीं होती है.

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

10. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कार्बन फुट प्रिंट को कम करने में मदद कर सकते है/हैं?
1. भवन निर्माण में राख आधारित सीमेंट का प्रयोग करना.
2. प्रकाष्ठा दीप्त लैंप की बजाय एल.ई.डी. आधारित इलेक्ट्रिक लैप का प्रयोग करना.
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

11. सी. एन. जी. को पर्यावरण मित्र ईधन के रूप में समझा गया है. निम्नलिखित में से कौन सा एक सी. एन. जी. का लक्षण नहीं है?
(a) सी.एन.जी. वायु की अपेक्षा भारी होता है
(b) यह लगभग 80-90% मिथेन के मिलावट में गैसीय रूप में हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है
(c) यह न तो द्रव ईधन होता है ना ही एल.पी.जी. की तरह होता है, जो द्रव रूप में प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है.
(d) सी. एन. जी. डीजल की तुलना में उत्प्रेरक परिवर्तक (कैटालिटिक कनवर्टर) को अधिक कार्यसक्षम प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है.

12. निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए:
1. धूल
2. कुहरा
3. राख
4. धुंआ
5. धूम
उपर्युक्त में से कौन से वायु प्रदूज़क हैं?
(a) 1, 2, 3, 4 और 5
(b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 2, 4, और 5
(d) केवल 1, 2, 3 और 4

13. निम्नलिखित स्वास्थ्य संकटों पर विचार कीजिए:
1. बच्चों में आई. क्यू. का कम होना
2. सिस्टोलिक (धमनीय) रक्त दाब का कम होना
3. आर. वी. सी (ष्टवेत रक्त कणिकाएं) की उत्तरजीविता का दुर्बल होना तथा रक्त जैव संष्ठलेज़ण का कम होना
4. असमय प्रसव का उच्च दर, मरे बच्चे का जन्म तथा अवधि पूर्व बच्चे का जन्म
उपर्युक्त में से कौन सा/से पर्यावरणीय ग्रसित विपदग्रस्तता से संबंधित है/हैं?
(a) 1, 2, 3 और 4
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) केवल 1, 2 और 3

14. निम्नलिखित में से कौन-से/सा महीन कणिकीय पदार्थ वाले खुले प्रदूज़ण को रोकने का उपयोगी नियंत्रित नीति है/हैं?
1. द्वी स्ट्रोक (आद्यात) वाले इंजनों के प्रयोग का निरोध
2. जीवभार के जलने का निरोध
3. घर में ईधन के रूप में कोयले के प्रयोग का निरोध
4. जंगल की आग के नियंत्रण हेतु सक्रिय उपाय
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1, 2, 3 और 4
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 1, 2 और 3

15. व्यापक आपदा का प्रबन्धन करते समय ''ट्राइएज'' पद सूचित करता है
(a) यह प्रथम आगमन, प्रथम उपचार का सिद्धान्त है.
(b) यह क्षतियों को बचाने के आधार पर, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त को प्रथम उपचार की संकल्पना के साथ पीड़ा प्राप्त व्यक्तियों का वर्गीकरण है.
(c) यह क्षतियों को बचाने के आधार पर, बच्चों तथा यौवन प्राप्त लोगों को उपचार करने की संकल्पना के साथ, पीड़ा प्राप्त व्यक्तियों का वर्गीकरण है.
(d) यह क्षतियों को बचाने के आधार पर, जो चिकित्सकीय मध्यस्थता के साथ सम्भवत: जीवित रह सकते हैं, को प्रथम उपचार की संकल्पना के साथ पीड़ा प्राप्त व्यक्तियों का वर्गीकरण है.

समसामायिक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न

Q1. मत्स्य पालन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. बजट आवंटन में 2021-22 की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है.
2. मत्स्य क्षेत्र 2014-15 से 10.87% की दो अंको वाली प्रभावशाली औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज कर रहा है.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

Q2. भारत में रक्षा निर्माण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. पिछले पांच वर्षों में कुल रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ रही है.
2. 2016-20 के दौरान वैश्विक हथियारों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 10% थी, जिससे देश प्रमुख हथियारों का दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया.

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों1 और 2
d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: a

Q.3 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. परिवेश पोर्टल का सम्बन्ध व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंजूरी से है.
2. वित्त वर्ष 2022 के लिए राज्यों को राजकोषीय घाटे को जीएस डीपी के 3% की अनुमति दी जाएगी.

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें.

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों सही हैं.
d) उपरोक्त में से कोई नहीं.

उत्तर : a

Q4. इन्टेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. यह टीकाकरण के लिए 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है.
2. यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सभी टीके-निवारक रोगों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करता है.

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों1 और 2
d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: a

Q5 निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है ?

a) श्रीलंका
b) यूनाइटेड किंगडम
c) मलेशिया
d) ऑस्ट्रेलिया

उत्तर: c

Q6 बायोमास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. बायोमास ऊर्जा का एक गैर-नवीकरणीय स्रोत है.
2. गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्बनिक या जीवाश्म-आधारित कार्बनयुक्त पदार्थों को उच्च तापमान पर, बिना दहन के सिनगैस में परिवर्तित करती है.

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर : b

Q7 निम्नलिखित में से किस देश में प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (EAST), एक प्रायोगिक सुपरकंडक्टिंग टोकामक चुंबकीय संलयन ऊर्जा रिएक्टर है ?

a) रूस
b) जापान
c) फ्रांस
d) चीन

उत्तर: d

Q8 भारतीय संविधान के तहत, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट आधार नहीं है जिस पर राज्य धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है?

a) सार्वजनिक आदेश
b) नैतिकता
c) सामाजिक न्याय
d) स्वास्थ्य

उत्तर : c

Q9 भारत में होने वाले डिजिटल भुगतान में निम्नलिखित में से भुगतान की कौन सी प्रणाली सबसे बड़े हिस्से के रूप में योगदान देती है ?

a) कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली
b) UPI
c) आधार सक्षम भुगतान प्रणाली
d) इंटरनेट बैंकिंग

उत्तर: b

Q10 दक्षिण एशियाई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. यह क्षेत्र विश्व की लगभग 24.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है.
2. यह क्षेत्र कुल वैश्विक जी.डी.पी. में 4.42% का हिस्सा रखता है.

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर : c

Q11 दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अस्थिरता के कारण निम्न में से क्या क्या है ?

1. कृत्रिम सीमाएं
2. देशों के मध्य आपसी विश्वास का संकट
3. चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव
4. आर्थिक संकट
5. शरणार्थी संकट
6. धार्मिक संघर्ष

उपरोक्त में कौन कौन से सही हैं। कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें ?

a) केवल 1, 3 और 4
b) केवल 2, 6, 5 और 3
c) दोनों 3, 4, 5 और 6
d) उपरोक्त सभी

उत्तर : d

Q12 भूजल प्रबंधन तथा रेगुलेशन पर कैग की रिपोर्ट के आधार पर निम्न कथनों का परीक्षण करें :

1. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूजल निष्कर्षण का स्तर (पुनर्भरण तथा निस्कर्षण का अनुपात) 2004 में 58 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 63 प्रतिशत हो गया है.
2. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में निष्कर्षण 100 प्रतिशत से अधिक है.
3. 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में निष्कर्षण का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है.

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर : c

Q13 भारत में भूमिगत जल के अधिक दोहन के कारण क्या है ?

1. बढ़ता शहरीकरण
2. हरित क्रांति
3. बढ़ता औद्योगिक क्षेत्र

कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 3
d) इनमें से सभी

उत्तर : d

Q14 निम्न में कौन-कौन से भारत में शिक्षा के डिजिटलीकरण के लिए किये गए प्रयास हैं ?

1. ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड
2. शगुन
3. भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी
4. शोधगंगा

कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 3
d) इनमें से सभी

उत्तर : d

Q15 भारत में डिजिटल यूनिवर्सिटी क्यों आवश्यक है ?

1. कोरोना प्रभाव के शमन के लिए
2. एजुकेशन फॉर आल के लक्ष्य के लिए

3. एसडीजी -4 के लक्ष्यों की प्राप्त के लिए

कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1, 2 और 3
d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर : c

Q16 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. अनुच्छेद 25 तथा अनुच्छेद 16 धर्म के आधार पर विभेदन से प्रतिषेध करता है।

2. अनुच्छेद 15 :- यह सभी व्यक्तियों को ''अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को निर्बाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त है. यद्यपि यह अधिकार आत्यंतिक नहीं है तथा राज्य द्वारा इस स्वतंत्रता को लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर निर्बंधित किया जा सकता है.

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर : d

Q17 निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है ?

a) अनुच्छेद 14: अनुच्छेद 14 विधिके समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है यह धार्मिक आधार पर विभेदन से निषेध करता है.

b) अनुच्छेद 15 : सार्वजनिक स्थल पर आवाजाही पर धर्म के आधार पर सकारात्मक विभेदन की अनुमति

c) अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन में धर्म के आधार पर विभेदन से प्रतिषेध.

d) अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक: व्यापक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

उत्तर : b

Q18 भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कंहा स्थापित किया जा रहा है ?

a) जबलपुर (मध्य प्रदेश)
b) उदयपुर (राजस्थान)
c) लखीमपुर (उत्तर प्रदेश)
d) नागपुर (महाराष्ट्र)

उत्तर : a

Q19 निम्न में से किसे वर्ष 2021 का 'वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर' के लिए चुना गया है?

a) रानी रामपाल
b) अल्बर्टो गिन्स लोपेज
c) पी.आर. श्रीजेश
d) मिशेल जिओर्डानो

उत्तर : c

Q20 2021 में भारत के व्यापारिक साझेदार का सही क्रम लगाइए

1. अमेरिका
2. सऊदी अरब
3. सिंगापूर
4. यूएई

कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें ?

a) 1,2,4,3
b) 1,4,2,3
c) 1,3,4,2
d) 1,2,3,4

उत्तर : b

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण उत्तर

1. (a)
2. (c)
3. (c)
4. (c)
5. (c)
6. (c)
7. (a)
8. (d)
9. (d)
10. (c)
11. (a)
12. (a)
13. (c)
14. (a)
15. (b)

Paper IV केस स्टडी

आप पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के एक जिले में जिलाधिकारी हैं केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री आज शाम को यहाँ आने वाले हैं.

धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि न होने एवं धान खरीद में विलंब होने से स्थानीय किसानों में असंतोष है. अतः स्थानीय किसान संगठनों ने, कृषि मंत्री का घेराव करके उन्हें ज्ञापन सौपने का निश्चय कर लिया. कुछ राजनीतिक दल भी किसानों का समर्थन कर रहें हैं.

इन किसानों ने मंत्री के कार्यक्रम स्थल का घेराव कर लिया एवं सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में एकत्रित हो गये. इसी बीच आपको खुफिया इकाई से सूचना मिलती है कि कुछ असामाजिक तत्व हथियारों के साथ किसानों के प्रदर्शन में शामिल हैं. ये अवसर का लाभ उठाकर दंगे भड़काना चाहते हैं। मंत्री के आने में मात्र 3 घंटे शेष हैं.

अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? विस्तार से समझाएं।

उत्तर :

दिए गए केस स्टडी में, मैं एक जिले का जिला मजिस्ट्रेट हूँ और मुझे स्थिति की जटिलताओं के कारण उत्पन्न हुए अशांत वातावरण को नियंत्रित करना है.

संभावित चुनौतियां :

- बड़े पैमाने पर दंगे के कारण हिंसा होने की सम्भावना.
- भगदड़ की सम्भावना.
- मंत्री की कमजोर सुरक्षा.
- जान और माल की हानि.
- किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

मेरी प्रतिक्रिया का तरीका निम्नलिखित होगा :

- मैं किसान नेताओं के साथ एक बैठक की व्यवस्था करूंगा और उनसे धरना समाप्त करने का अनुरोध करूंगा, नई योजनाओं को सुनूंगा जो उनके लिए फायदेमंद हो सकती हैं और उसके बाद ही शांतिपूर्वक मंत्री से उनकी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए मिलें.
- मैं विरोध करने वाले किसानों के समूह को उनके अनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनके समूहों में मौजूद असामाजिक तत्वों से अवगत कराऊंगा.
- मैं तत्काल पुलिस बैकअप की भी मांग करूंगा और जहां मंत्री आ रहे हैं उस पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर दूंगा और केवल पहचान सत्यापन पर ही प्रवेश की अनुमति दूंगा.
- मैं विपक्षी पार्टी के नेताओं को सार्वजनिक रूप से आने के लिए मनाऊंगा और विरोध कर रहे किसानों से शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए सिफारिश करने का अनुरोध करूंगा.
- मैं अपनी निगरानी में समय पर खरीद का आश्वासन देकर विरोध करने वाले किसानों को उनकी उपज की खरीद के संबंध में भी मनाऊंगा.
- मैं स्थानीय सामाजिक समूहों से सभा में स्वयंसेवक बनने और असामाजिक तत्वों की तलाश करने और पुलिस को वापस रिपोर्ट करने और प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक आगे बढ़ने के लिए मनाने के लिए मदद मांगूंगा.
- यदि स्थिति बिगड़ती है तो मैं मंत्री जी से उनके कार्यक्रम में देरी करने का अनुरोध करूंगा और किसान नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी मांगों को व्यक्तिगत रूप से अपनी पसंद के स्थान पर प्रस्तुत करें.

NOTES

व्यक्ति विशेष : दादा साहब फाल्के

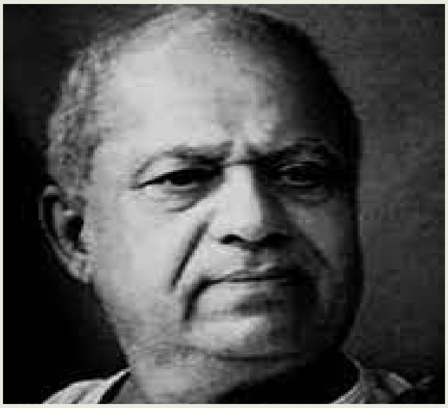

दादा साहब फाल्के किसी परिचय के मोहताज नहीं है. एक ऐसे सिनेमेटिक विजनरी इंसान जिन्होंने भारतीय अभिनय की परंपरा की नींव रखी, जिन्होंने भारत की पहली फिल्म बनाई और भारत के सभी प्रमुख पौराणिक चरित्रों को पर्दे पर उतारा. ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान स्वदेशी आंदोलन से ऊर्जा लेते हुए उन्होंने स्वदेशी भारतीय फिल्म निर्माण का ऐतिहासिक काम किया. उनकी काबि. लियत इस बात में थी कि उन्होंने भारतीय फिल्म जगत में अभिनय के संभावनाओं की पहली बार खोज की.

दादा साहब फाल्के (धुंडीराज गोविन्द फालके) का जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक के त्रियंबक में हुआ था. उन्होंने अपनी पढ़ाई 1885 में मुंबई में सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में पूरी की और उसके बाद गुजरात के बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के कला भवन चले गए जहां उन्होंने मूर्तिकला, ड्राइंग, पेंटिंग और फोटोग्राफी सीखी. थोड़े समय के लिए फाल्के ने बड़ौदा में एक पेंटर के रूप में भी काम किया और फिर गोधरा में एक फोटोग्राफर के रूप में और वहीं पर ब्यूबोनिक प्लेग में उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया और इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र वापस लौटने का फैसला किया.

फिल्म मेकर के रूप में अपना कैरियर शुरू करने के पहले उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रिंटिंग प्रेस में काम किया और इसके अलावा कई और नौकरियां की थीं. ऐसा बताया जाता है कि फाल्के ने 1890 के दशक में राजा रवि वर्मा के साथ उनके लिथोग्राफी प्रेस में काम किया था. उसके बाद फाल्के ने अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था. कुछ समय बाद फाल्के ने प्रिंटिंग की नई तकनीकों को सीखने के लिए जर्मनी जाने का निर्णय लिया. उन्होंने अपने उपकरणों को अपडेट करने का मन बनाया और वहां से वापस आने के बाद उन्होंने भारत के सबसे प्रमुख प्रेस की शुरुआत की लेकिन बहुत लंबे समय तक प्रिंटिंग प्रेस में उनका कैरियर नहीं चला और उन्होंने इस्तीफा देने का मन बनाया.

फाल्के के जीवन में टर्निंग प्वाइंट तब आया जब उन्होंने 1903 में फ्रेंच साइलेंट फिल्म "The life of christ" देखी और इससे बहुत अधिक प्रभावित हुए. बंबई के अमरीका-इंडिया पिक्चर पैलेस में 'द लाइफ ऑफ क्राइस्ट' दिखाई गई थी. थियेटर में बैठकर फिल्म देख रहे धुंदीराज गोविंद फाल्के ने तालियां पीटते हुए निश्चय किया कि वो भी भारतीय धार्मिक और मिथकीय चरित्रों को रूपहले पर्दे पर जीवंत करेंगे.

इसके बाद फिल्म मेकिंग पर उन्होंने हर चीज पढ़ना और देखना शुरू किया. वह इंग्लैंड गए और वहां से विलियमसन कैमरा, एक परफोरेटेड और कुछ कोडेक फिल्म भी खरीदी, अपनी फिल्म बनाने के लिए पत्नी के गहने तक भी बेंच दिए.

उन्होंने अपनी पहली फुल लेंथ 40 मिनट की मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई. भारत में दर्शकों के मन को ये फिल्म ऐसी भा गईं कि फाल्के की फिल्म निर्माण की जर्नी शुरू हो गई. उन्होंने इसका निर्माण किया, निर्देशक भी वही थे, कॉस्ट्यूम डिजाइन, लाइटमैन और कैमरा डिपार्टमेंट भी उन्हीं ने संभाला था. वही फिल्म की पटकथा के लेखक भी थे। 3 मई 1913 को इसे कोरोनेशन सिनेमा बॉम्बे में रिलीज किया गया। यह भारत की पहली फिल्म थी.

फाल्के को लगा कि चूंकि उस दौर में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो इसका लाभ भारतीय सिनेमा उद्योग को भी मिल सकता है. इसके बाद अगले दो दशकों तक उन्होंने 95 फिल्में बनाई जिनमें अधिकांश पौराणिक किरदार वाले थे, उन्होंने 20 से अधिक शार्ट फिल्में भी बनाई। उन्होंने 1913 में मोहिनी भस्मासुर, 1914 में सत्यवान सावित्री, 1918 में श्री कृष्णा, कालिया मर्दन (1919) 1922 में राज ऋषि अम्बरीश, 1923 में गुरु द्रोणाचार्य, 1927 में द्रौपदी वस्त्रहरण, 1929 में संत मीराबाई, 1930 में कबीर कमाल जैसी फिल्में बनाई.

उनकी 1917 में एक फिल्म लंका दहन में अभिनेता अन्ना सालुंके ने लॉर्ड राम और सीता दोनों का रोल प्ले किया था और यह भा. रतीय सिनेमा में डबल रोल निभाने की पहली घटना थी. दादा साहब फाल्के ने देश के अलग-अलग क्षेत्रों जैसे कोलकाता, पुणे, मुंबई और कोल्हापुर को फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में प्रेरित किया और इसके चलते एक बड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अस्तित्व में आ सकी.

उन्होंने हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म्स कंपनी में पार्टनरशिप भी किया था लेकिन उसे बाद में छोड़ भी दिया था और अपने को काशी में सेटल कर लिया था. 1937 में उन्होंने गंगावतरण नामक फिल्म बनाई जो कि उनकी पहली साउंड फिल्म थी और यह उनकी निर्देशन में बनी अंतिम फिल्म भी थी. उनकी आखिरी मूक मूवी सेतुबंधन थी और आखिरी मूवी गंगावतरण थी.

16 फरवरी 1944 को दादा साहब फाल्के ने नासिक में अपनी अंतिम सांसे ली. उनकी याद में 1969 में भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट शुरू किया गया था.

राजव्यवस्था शब्दावली

संविधान बनाने की प्रक्रिया

संविधान सभा की मांग

- पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय ने भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग की.
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा की मांग की.
- 1940 में "अगस्त प्रस्ताव" द्वारा, ब्रिटिश सरकार ने अंततः सैद्धांतिक रूप से मांग को स्वीकार कर लिया.
- क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन राज्य स्थिति की पेशकश की. गांधी ने क्रिप्स की पेशकश को "पोस्टडेटेड चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला है" कहा था.
- 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया; इसने संविधान सभा के लिए एक योजना प्रस्तुत की.

संविधान सभा की संरचना

संविधान सभा में 389 सदस्य थे. इनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से थे.

संविधान सभा की पहली बैठक

- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी.
- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया.
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था.

उद्देश्य प्रस्ताव

- 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया.
- इसने संवैधानिक संरचना के मौलिक और दर्शन को निर्धारित किया.

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कारण तीन बड़े पर्ि. रवर्तन हुए:-

- संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई.
- अब संविधान सभा को दो कार्य करने थे
- संविधान निर्माण :- इसकी अध्यक्षता डॉ राजेंद्र प्रसाद ने की थी. बाद में डॉ राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने.
- प्रांतीय विधानमंडल :- इसकी अध्यक्षता जी वी मावलंकर ने की थी. बाद में वे भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने.
- मुस्लिम लीग के सदस्य (पाकिस्तान क्षेत्रों से सम्बद्ध) भारत के लिए संविधान सभा से हट गए. अब कॉन्सटेंट असेंबली में 299 सदस्य थे, जिनमें से 229 सदस्य भारतीय प्रांतों से थे और 70 देसी रियासतों से थे.

संविधान सभा की समितियाँ

- संघ शक्ति कमेटी - जवाहरलाल नेहरू
- संघीय संविधान समिति - जवाहरलाल नेहरू
- प्रांतीय संविधान समिति - सरदार पटेल
- प्रारूप समिति - डॉ बी आर अम्बेडकर
- मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीयों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति - सरदार पटेल

प्रारूप समिति

- 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की. इसके 7 सदस्य थे:-

1. डॉ बी आर अम्बेडकर (अध्यक्ष)
2. एन गोपालस्वामी अय्यंगार
3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यार
4. सैयद मोहम्मद सादुल्ला
5. डॉ के एम मुंशी
6. एन माधव राव (बी एल मित्तर की जगह)
7. टी टी कृष्णमाचारी (डीपी खेतान की जगह)

- 21 फरवरी, 1948 को भारत के संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था

संविधान का प्रभाव में आना

- भारत के संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर, 1948 को पेश किया गया था और पहली बार वाचन हुआ था.
- दूसरा वाचन 15 नवंबर, 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ.
- तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ. 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने "भारत के संविधान को अपनाया. इसमें एक प्रस्तावना , 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं .

संविधान का प्रवर्तन

- 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था.
- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया.
- 26 जनवरी 1950 को शेष लेख लागू हुए.
- "संविधान का प्रारंभ" 26 जनवरी 1950 को हुआ.

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Target UPPCS Prelims 2022

हिन्दी माध्यम

भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सेवा होने के कारण सिविल सेवा देशभर से अभ्यर्थियों को आकर्षित करती हैं। लेकिन सीटों की संख्या सीमित होने से इस परीक्षा में सफलता हेतु उच्चतम स्तर की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता हैं। ऐसे मे एक नियोजित तैयारी और प्रभावी रणनीति सफलता की कुंजी बन जाती हैं। इस विचार और इरादे के साथ हमारे अत्यंत ही कुशल, दक्ष एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ऐसी विशिष्ट एवं प्रभावी रणनीति तैयार की जाती हैं, जिससे सुपरिभाषित तरीके से सभी टॉपिक को कवर किया जा सके। बेहतर अवधारणात्मक समझ हेतु हम अभ्यर्थियों की सहायता करते हैं। साथ ही अन्तर–अनुशासनात्मक दृष्टीकोण के विकास हेतु मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। हमारी नवोन्मेषी अध्ययन प्रणाली एक विश्वासयुक्त रोड मैप तैयार करती है ताकि इस सुनहरे लक्ष्य को प्रभावी ढंग से हासिल किया जा सके। सपनों को साकार करने और आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु हम आपको सशक्त बनाते हैं, साथ ही परिश्रम, समर्पण, विश्वास एवं सही दिशा जैसे अव्यय के विकास में आपके साथ हर कदम पर खड़े रहते हैं। UPPCS के तेजी से बदलते पैटर्न के अनुरूप अपने प्रदर्शन में समायानुकूल बदलाव हेतु हम सदैव अभ्यर्थियों के साथ प्रो–ऐक्टिव होकर कार्य भी करते हैं।

छात्र अपनी आवश्यकता अनुरूप निम्नलिखित में से किसी भी कोर्स का चयन कर सकते है।

Target UPPCS Prelims 2022

Fee: 28,000/-

Objective

कोर्स में सामान्य अध्ययन के सभी भागों को विस्तार से कवर किया जायेगा जिसमें करेंट अफेयर्स भी शामिल रहेगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से सामान्य अध्ययन के परंपरागत (Static) और अद्यतन (Dynamic) भाग की गहन समझ प्रदान किया जाएगा। इस प्रोग्राम में विषय विशेषज्ञों के द्वारा live class में विभिन्न मुद्दों और उनसे तत्संबंधी हाल के नवीन घटनाक्रमों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही लाइव/डिलेड लाइव या रिकॉडेड क्लास के माध्यम से सामान्य अध्ययन के परंपरागत (Static) हिस्से पर गुणवत्तापूर्ण कंटेंट भी दिया जाएगा।

इस कोर्स में सी–सैट भी शामिल होगा। इस हिस्से में छात्र विभिन्न सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग संबंधी बेहतर और प्रभावी समझ विकसित कर सकेंगे। अवधारणात्मक समझ और संबंधित विषयवस्तु का स्पष्टीकरण भी इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा होगा।

CSAT खंड से जुड़े प्रश्नों को आसानी से हल करने के जरूरी तकनीकों और तरीकों पर विस्तृत परिचर्चा भी आयोजित की जायेगी।

Features

- 100 घण्टे की लाइव क्लास जिसमें सामान्य अध्ययन के अद्यतन (Dynamic) हिस्से को कवर किया जाएगा।
- 150 घण्टे की लाइव/डिलेड (Delayed) लाइव/रिकॉडेट क्लास जिसमें सामान्य अध्ययन के परम्परागत (Static) हिस्से को अपनी सुविधानुसार देखने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
- 150 घंटे की क्लास में सी–सैट का पूर्ण कवरेज।
- सभी लाइव क्लासेस के अंत में समस्या समाधान हेतु आधे घंटे का समय दिया जाएगा।
- एकेडमिक चैट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- PDF फारमैट में डाउनलोड हेतु विषय–सामग्री App पर प्रदान की जाएगी।
- Perfect 7 की 24 कॉपियां (2000 रुपये मूल्य वाली) भी कोर्स के साथ प्रदान की जाएगी।
- कोर्स के साथ एक Prelims टेस्ट सीरीज (2500 रुपये मूल्य वाली) भी शामिल रहेगा।

Course Content	Faculty Name
General Studies- Static	
Indian History+ Art & Culture	Vijay Ved
Geography of India & World	Divyavadan Singh Parihar
Indian Polity & Governance	Vineet Anurag & Jay Singh
Economy	Kumar Amit
General Science	Raghvendra Singh
General Studies- Dynamic (Current Issues & Developments)	
Indian Polity & Governance	Vineet Anurag & Shashidhar
Environmental Ecology, Bio-Diversity & Climate Change	Sanjay Singh
Economy + Budget & Economic Survey	Kumar Amit
Technology	Q. H. Khan & Peeyush
Health	Javed Haque
International Issues	Vineet Anurag
CSAT	
Maths and Reasoning	Mukesh Singh
Comprehension	Shweta Singh
English Language	Athar Abbasi
General Hindi	Sandeep Sahil

Call : 9205274741 / 42 / 44

CLICK HERE FOR ENROLLMENT

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

General Studies - Target UPPCS Prelims 2022

Fee: 18,000/-

Objective	Features	Course Content	Faculty Name
कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि उसमें करेंट अफेयर्स के साथ सामान्य अध्ययन के सभी खण्डों को विस्तार पूर्वक कवर किया जा सके। इस प्रोग्राम के माध्यम से सामान्य अध्ययन के सभी अद्यतन हिस्सो की गहन समझ प्रदान की जाएगी। विषय- विशेषज्ञों के द्वारा Live Class के माध्यम से मुद्दों और तत्संबंधी हालिया घटनाक्रमों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही Live/Delayed Live या Recorded classes के माध्यम से करेंट अफेयर्स के परम्परागत भाग पर गुणवत्ता पूर्ण सामग्री भी प्रदान की जाएगी, जिससे छात्र असीमित समय तक देख सकेंगे।	• 100 घण्टे की लाइव क्लास जिसमें सामान्य अध्ययन के अद्यतन (Dynamic) हिस्से को कवर किया जाएगा। • 150 घण्टे की लाइव/डिलेड (Delayed) लाइव/रिकॉर्डेड क्लास जिसमें सामान्य अध्ययन के परम्परागत (Static) हिस्से को अपनी सुविधानुसार देखने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। • सभी लाइव क्लासेस के अंत में समस्या समाधान हेतु आधे घंटे का समय दिया जाएगा। • एकेडमिक चैट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। • PDF फारमैट में डाउनलोड हेतु विषय-सामग्री App पर प्रदान की जाएगी।	**General Studies- Static**	
		Indian History+ Art & Culture	Vijay Ved
		Geography of India & World	Divyavadan Singh Parihar
		Indian Polity & Governance	Vineet Anurag & Jay Singh
		Economy	Kumar Amit
		General Science	Raghvendra Singh
		General Studies- Dynamic (Current Issues & Developments)	
		Indian Polity & Governance	Vineet Anurag & Shashidhar
		Environmental Ecology, Bio-Diversity & Climate Change	Sanjay Singh
		Economy + Budget & Economic Survey	Kumar Amit
		Technology	Q. H. Khan & Peeyush
		Health	Javed Haque
		International Issues	Vineet Anurag

Spotlight Current Affairs - UPPCS Prelims 2022

Fee: 10,000/-

Objective	Features	Course Content	Faculty Name
कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि उसमें करेंट अफेयर्स के साथ सामान्य अध्ययन के सभी खण्डों को विस्तार पूर्वक कवर किया जा सके। इस प्रोग्राम के माध्यम से सामान्य अध्ययन के सभी अद्यतन हिस्सो की गहन समझ प्रदान की जाएगी। विषय - विशेषज्ञों के द्वारा live class के माध्यम से मुद्दो और तत्संबंधी हालिया घटनाक्रमों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा।	• 100 घण्टे की लाइव क्लास जिसमें सामान्य अध्ययन के अद्यतन (Dynamic) हिस्से को कवर किया। • सभी लाइव क्लासेस के अंत में समस्या समाधान हेतु आधे घंटे का समय दिया जाएगा। • एकेडमिक चैट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। • PDF फारमैट में डाउनलोड हेतु विषय-सामग्री App पर प्रदान की जाएगी।	**General Studies- Dynamic (Current Issues & Developments)**	
		Indian Polity & Governance	Vineet Anurag & Shashidhar
		Environmental Ecology, Bio-Diversity & Climate Change	Sanjay Singh
		Economy + Budget & Economic Survey	Kumar Amit
		Technology	Q. H. Khan & Peeyush
		Health	Javed Haque
		International Issues	Vineet Anurag

UPPCS CSAT

Fee: 10,000/-

Objective	Features	Course Content	Faculty Name
इस हिस्से में छात्र विभिन्न सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग संबंधी बेहतर और प्रभावी समझ विकसित कर सकेंगे। अवधारणात्मक समझ और संबंधित विषयवस्तु का स्पष्टीकरण भी इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा होगा। CSAT खंड से जुड़े प्रश्नों को आसानी से हल करने के जरूरी तकनीकों और तरीकों पर विस्तृत परिचर्चा भी आयोजित की जायेगी।	• 150 घंटे की क्लास में सी-सैट का पूर्ण कवरेज। • सभी लाइव क्लासेस के अंत में समस्या समाधान हेतु आधे घंटे का समय दिया जाएगा। • एकेडमिक चौट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। • PDF फारमैट में डाउनलोड हेतु विषय-सामग्री App पर प्रदान की जाएगी।	Maths and Reasoning	Mukesh Singh
		Comprehension	Shweta Singh
		English Language	Athar Abbasi
		General Hindi	Sandeep Sahil

जिन विद्यार्थियों ने पहले तीन कोर्स में से किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है उन्हें UP स्पेशल की 10 दिन की क्लास अतिरिक्त दी जाएगी।

ध्येय स्टूडेंट्स के लिए आकर्षक छूट

- 100% छूट Spotlight Current Affairs प्रोग्राम के लिए उन ध्येय विद्यार्थियों को जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद एडमिशन लिया है।
- 50% छूट Spotlight Current Affairs प्रोग्राम के लिए उन ध्येय विद्यार्थियों को जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 से पहले एडमिशन लिया है।

SYLLABUS OF PRELIMS

प्रश्न पत्र 1 (अंक: 200) अवधि: 2 घंटे

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ
- भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन
- भारत एवं विश्व भूगोल - भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल
- भारत राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था - संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि।
- आर्थिक और सामाजिक विकास - सतत् विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि।
- पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है।
- सामान्य विज्ञान

प्रश्न पत्र 2 (अंक: 200) अवधि: 2 घंटे

- काम्प्रिहेन्शन (विस्तारीकरण)
- अन्तवैंयक्तिक क्षमता जिसमें सम्प्रेषण कौशल भी समाहित होगा।
- तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता।
- निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान।
- सामान्य बौद्धिक योग्यता।
- प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक - अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित व सांख्यिकी।
- सामान्य अंग्रेजी हाईस्कूल स्तर तक।
- सामान्य हिन्दी हाईस्कूल स्तर तक।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

IAS Prelims Knock Out Test Series 2022

Bilingual

Total tests 14

3 Sectional + 6 GS Full Test+
4 CSAT +1 Full Current Affairs

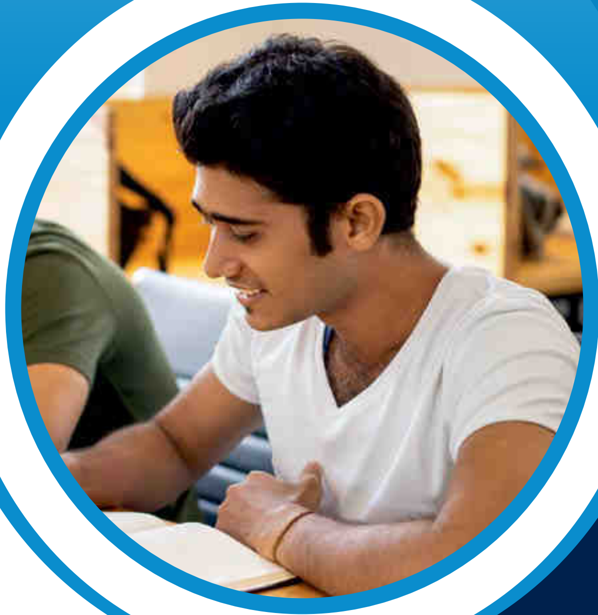

DHYEYA ADVANTAGE

- 20% for non Dhyeya Students who have cleared UPSC Prelims at least once.
- 20% for Dhyeya Students.
- 40% for Dhyeya Students who have cleared UPSC Prelims at least once.

Starts From
6th March

9205274741/42/44

www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

We are hiring

Job Opening : Translators | Test paper Developers | Academic Associates | Content Developers

25 positions: Full time | Part Time | Freelancing

Criteria:

UPSC background: candidates who have appeared or cleared the mains exam

Minimum 1 Year Experience

Location Mukherjee Nagar, Delhi

Send your CV to hr@dhyeyaias.com | Call: 9205336068

AN INTRODUCTION

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DhyeyaIAS, one and half decade old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4000 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 | **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 | **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 | **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 | **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 | **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow , UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 | **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 | **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha - 751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

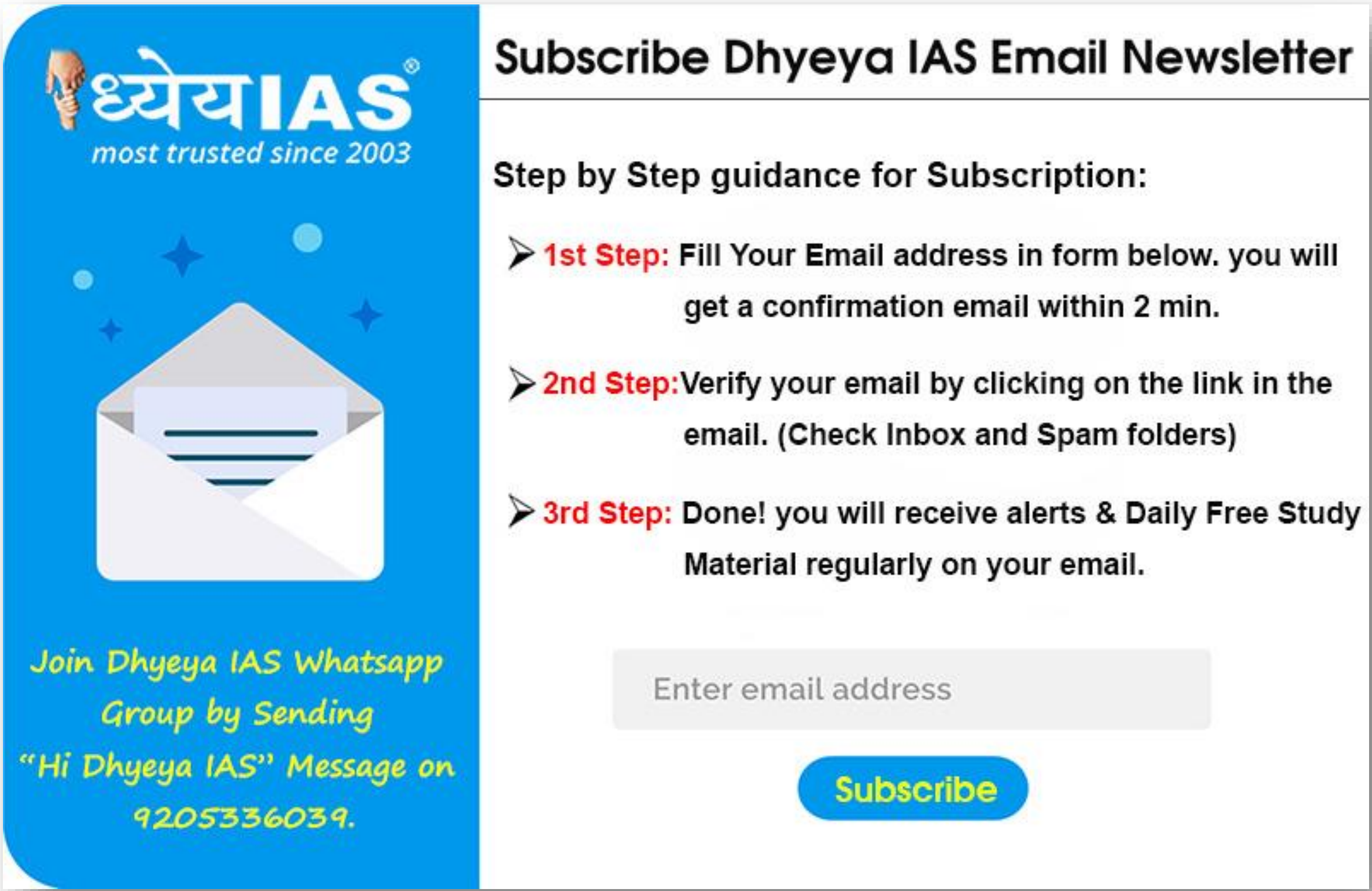

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744